प्रभात

अन्दर के पन्नों पर ...

★ *'कोया भूमकाल मिलिशिया' का ऐलान*
★ *'सलवा जुडूम' तथ्यान्वेषण कमेटी की रिपोर्ट*
★ *पोस्को करार - उड़ीसा की लूट*
★ *कलिंगनगर हत्याकाण्ड*
★ *शहीदों को श्रद्धांजली*
★ *पीएलजीए की कुछ शानदार कार्रवाइयां*
★ *दण्डकारण्य संघर्षों की खबरें*
★ *शीर्ष माओवादी नेताओं को रिहा करो*

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का तिमाही मुख-पत्र

वर्ष - 19 **अंक - 1** **जनवरी-मार्च 2006** **सहयोग राशि - 10 रुपए**

'सलवा जुडूम' जनता का सस्फूर्त आन्दोलन नहीं - दण्डकाण्य की जनता के खिलाफ सरकारी और सरकार-प्रायोजित आतंक का अभियान है !

पिछले 9 महीनों से छत्तीसगढ़ की सरकारी मशीनरी ने दण्डकारण्य के क्रान्तिकारी जन समुदायों के खिलाफ अत्यन्त बर्बरतापूर्ण अभियान छेड़ रखा है. अब तक 150 से ज्यादा लोग, जिनमें जन संगठनों व जन मिलिशिया के कार्यकर्ता समेत आम लोग भी शामिल हैं, क्रूरतापूर्वक मारे गए हैं. 100 से ज्यादा गांवों को जलाकर राख कर दी गई है. महिलाओं पर केन्द्रीय सशस्त्र बलों, नगा पुलिस और आतंकी ''सलवा जुडूम'' गुण्डों के अत्याचारों का कोई हिसाब नहीं है. यहां तक कि 10-12 साल के बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है. सैकड़ों निर्दोष किसानों को गिरफ्तार कर निर्मम यातनाओं का शिकार बनाया जा रहा है. हजारों लोगों को तथाकथित राहत शिविरों में बन्दी बनाकर रखा जा रहा है जिन्हें अकथनीय यातनाओं से गुजरना पड़ रहा है. विडम्बना है कि इसे 'शांति मिशन' के रूप में चित्रित किया जा रहा है. वास्तव में गोण्डी भाषा में 'जुडूम' का अर्थ ही है 'सामूहिक शिकार'. और शिकार कभी शांतिपूर्ण ढंग से नहीं होता. 'शिकार' का अर्थ है 'सफाया'. ठीक वही आज बस्तर के बीहड़ जंगलों में सरकार कर रही है. यह जुल्मी अभियान कुख्यात कांग्रेसी सरगना महेन्द्र कर्मा और छत्तीसगढ़ की भाजपाई रमन सरकार के नेतृत्व में चलाया जा रहा है. इसका तालमेल केन्द्र सरकार ज्वाइन्ट ऑपरेशनल कमाण्ड के जरिए कर रही है जो उसने अरसा पहले खोल रखी है. खबर है कि सोनिया गांधी और एलके आड़वाणी भी इन इलाकों का दौरा करने वाले हैं ताकि इस आतंकी अभियान को और ज्यादा भड़काया जा सके.

'सलवा जुडूम' - झारखण्ड से लेकर आन्ध्र तक फैले समूचे इलाके को लूटने की बड़ी साजिश का हिस्सा

लुटेरे शासक वर्गों ने देश में तेजी से बढ़ रहे जनयुद्ध का दमन करने का सपना पाल रखा है. दण्डकारण्य (छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र), झारखण्ड, आन्ध्र, बिहार, उड़ीसा और मध्यप्रदेश में उभर रही वैकल्पिक क्रान्तिकारी जन राजसत्ता को तथा पश्चिम बंगाल, उत्तरांचल, उत्तरप्रदेश व अन्य प्रदेशों में फैल रहे क्रान्तिकारी आन्दोलन को कुचलने को वे उतावले हो रहे हैं. झारखण्ड से आन्ध्र तक पसरा हुआ यह इलाका भारतीय शासक वर्गों और साम्राज्यवादियों के लिए रणनीतिक रूप ते काफी अहमियत रखता है क्योंकि यहां पर देश की सर्वाधिक खनिज और वन सम्पदा मौजूद है. हालांकि यह समूचा इलाका भाकपा (माओवादी) के प्रभाव में है जोकि इस क्षेत्र में केन्द्र और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जारी शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ व्यापक आदिवासी जन समुदायों का नेतृत्व कर रही है. सभी सरकारें बड़े जमींदारों, दलाल नौकरशाही पूंजीपतियों के हितों का पोषण करती हैं और साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की जी-हुजूरी करती हैं. लिहाजा, असली जनवाद का प्रतिनिधित्व करने वाली जनता की नई वैकल्पिक राजसत्ता लुटेरों के लिए एक चुनौती बन गई है. वे उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इससे उनके ढोंगी लोकतंत्र की पोल लगातार खुलती जा रही है. भ्रष्ट, तानाशाही, साम्प्रदायिक और फासीवादी ताकतें हमारे देश के अत्यधिक जन समुदायों पर चढ़ बैठी हैं. इसलिए, शासक वर्गों ने बर्बरतापूर्ण दमन अभियान छेड़ने की एक मुकम्मल साजिश रच रखी है ताकि इस खनिज सम्पदाओं से समृद्ध इलाके में दलाल पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के निवेश के लिए रास्ता साफ किया जा सके और इस समूचे क्षेत्र में बढ़ रही जनता की क्रान्तिकारी जनवादी राजसत्ता को कुचला जा सके.

दरअसल नवम्बर 2004 में बंगलूर में बोलते हुए खुद प्रधानमंत्री ने यह इंगित करते हुए कि यह इलाका लुटेरों के लिए कितना महत्व रखता है, इस दमन अभियान के लिए धुन तैयार की. उन्होंने यूं कहा: ''*केन्द्र सरकार इस बात से चिन्तित है कि खासकर नक्सलवादी मध्य भारत के उन पहाड़ी इलाकों में उभरे हैं जहां हमारे खनिज व जल संसाधन मौजूद*

हत्या, बलात्कार, आगजनी, लूट के भयावह हमलों के बीचोबीच 'कोया भूमकाल मिलिशिया' में संगठित होकर प्रतिरोध का परचम बुलन्द रखने वाली दण्डाकरण्य की बहादुर जनता को लाल सलाम !!

हैं. नक्सलवादी आन्दोलन तेज हो रहा है, जिससे केन्द्र सरकार चिन्तित है.''

तबसे लेकर दलाल पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ उत्खनन के कई बड़े करारों पर दस्तखत किए गए हैं ताकि स्थानीय आदिवासियों को विस्थापित कर हमारे देश की प्राकृतिक सम्पदाओं को लूटा जा सके. एक साल के अन्दर उड़ीसा, झारखण्ड और छत्तीसगढ़ राज्यों की सरकारों के साथ इन कम्पनियों ने भारी भरकम 3 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर दस्तखत किए हैं. झारखण्ड में सिर्फ पिछले दो महीनों में मित्तल (अनिवासी भारतीय) और जिन्दल के साथ दो एमओयू किए गए. जहां मित्तल का करार 40 हजार करोड़ रुपए का है, वहीं जिन्दल के साथ हुआ करार 35 हजार करोड़ रुपए का है. टाटानगर में टाटा के विस्तार की बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं.

उड़ीसा में 37 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए जिनमें विशालकाय पोस्को कम्पनी के साथ हुआ एमओयू एक है जोकि इस्पात संयंत्र लगाकर सालाना 477 लाख टन इस्पात पैदा करने वाली है. कुल मिलाकर वे उड़ीसा में 1,18,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाले हैं. छत्तीसगढ़ सरकार ने 60 हजार करोड़ रुपए के एमओयू पर दस्तखत किए. पिछले गर्मियों के दौरान उसने 17 हजार करोड़ रुपए के निवेश के दो एमओयू पर हस्ताक्षर किए जोकि बस्तर में लगने वाले हैं. टाटा और एस्सार (रुइया) के साथ ये समझौते हुए थे. छत्तीसगढ़ में टाटा कम्पनी बैलाडीला और रावघाट खदानों से लौह अयस्क का दोहन करने की फिराक में है.

इतना सारा पैसा लगाने वाले बड़े पूंजीपति और सरकारें अच्छी तरह जानते हैं कि इन इलाकों में नक्सलवादियों का दमन कर ही वे अपनी लूट का सिलसिला बेरोकटोक जारी रख सकते हैं और भारी मुनाफा कमा सकते हैं. ये सारी तथाकथित विकास परियोजनाएं आदिवासियों की जीविका को तबाह करने की कीमत पर ही हासिल की जा सकती हैं. लोगों का खून बहाकर ही यहां बड़ी पूंजी कार्यवाही में उतर सकती है. पुलिस, अर्ध-सैनिक और सैनिक बल पोस्को, जिन्दल, मित्तल, टाटा जैसों के भाड़े के कुत्तों के अलावा कुछ भी नहीं है. ये सभी बल 'आतंकवाद' के नाम पर जनता के खिलाफ लड़ रहे हैं ताकि देश की जनता को धोखे में रखा जा सके. आखिर दुनिया का नम्बर एक आतंकवादी और अव्वल दर्जे का झूठा बुश ने उन्हें यही तो सिखाया!

खासकर पिछले एक साल से झारखण्ड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश की सरकारों के साथ बड़े पूंजीपति और बहुराष्ट्रीय कम्पनियां दर्जनों एमओयू के जरिए देशद्रोहपूर्ण समझौते कर ही रही हैं, साथ ही साथ, इस विशाल क्षेत्र में भयानक आतंक मचाने की साजिशें भी रची गई हैं. सितम्बर 2004 में भाकपा (माओवादी) के गठन के बाद से कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों और पुलिस के मुखियाओं की बैठकों के दौर लगातार चलते रहे. ज्वाइंट टास्कफोर्स का गठन किया गया. 24 से ज्यादा सीआरपीएफ के बटालियन इन राज्यों में तैनात कर दिया गया. कई नए इंडियन रिजर्व बटालियनों का गठन किया जा रहा है. प्रतिक्रियावादी सरकारों की इस नीचतापूर्ण योजना के अहम पहलू ये हैं - निजी सेनाओं का गठन, व्यापक आतंक मचाना, जनता में से एक तबके को राज्य-प्रायोजित आतंकी अभियान से जुड़ने पर बाध्य करना और उन्हें माओवादियों या क्रान्तिकारियों के खिलाफ खड़ा कर देना, इस तरह एक बड़ा झूठ गढ़ना कि आदिवासी खुद ही माओवादियों के खिलाफ खड़े हो गए हैं. दण्डकारण्य में 'जन जागरण' अभियान या 'सलवा जुडूम' के नाम पर, झारखण्ड में 'सेन्देरा' (संथाली में इसका अर्थ 'सामूहिक शिकार' है) के नाम पर, महाराष्ट्र में 'गांवबन्दी' के नाम पर, उड़ीसा में 'शांति सेना' के नाम पर यह योजना अमल में लाई गई है. आन्ध्र में 'कोब्रास' और 'टाइगर्स' के नाम पर पुलिस अधिकारियों की अगुवाई में निजी हथियारबन्द गिरोहों का गठन कर 2005 जनवरी से हत्या और आतंक का सिलसिला तेज कर दिया गया.

'सलवा जुडूम' की भयावहता और बर्बरता

नगा पुलिस व सीआरपी बलों की अगुवाई में 'सलवा जुडूम' गुण्डावाहिनी जनता को आतंकित करने के लिए अत्यन्त बर्बरतापूर्ण तरीके अपना रही है. वे एक के बाद एक गांव पर हमला बोलते हुए घरों पर स्प्रेयरों के जरिए मिट्टी तेल छिड़ककर आग लगा रहे हैं. इस तरह उन्होंने अब तक 100 से ज्यादा गांवों को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया. और कुछ गांवों को आंशिक तौर पर तबाह कर दिया.

निम्नांकित घटनाओं पर गौर करने से इस तथाकथित 'शांति मिशन' का खूंखार चेहरा खुद-ब-खुद बेनकाब हो जाता है. 28 अगस्त को नगा बटालियन और गुण्डावाहिनी ने आकवा गांव में 12 साल के एक किशोर का सिर कलम कर दिया. अरियाल (चेरली) गांव में उन्होंने कुल 10 लोगों को कतार में खड़े करवाकर गोली मार दी. मारे गए लोगों में एक 10 साल का बच्चा भी शामिल था. 10 अक्टूबर को परालनार गांव का 14 साल किशोर बारसा सोनू को पुलिस ने जिन्दा पकड़कर क्रूरतापूर्ण यातनाएं देने के बाद उसकी हत्या कर दी. 3 अक्टूबर को मनकेली गांव के लोक नायक कोवाल को पुलिस ने उनके खेत पर पकड़ कर वहीं उनकी हत्या की. उनके शरीर के सारे अंग काट दिए. दिल को बाहर निकालकर फेंक दिया. जीभ काट डाली. आंखें निकाल दीं. उनका 14 साल का बेटा राजू का अभी तक कोई अता-पता नहीं है जिसे उसके पिता के साथ पकड़ लिया गया था. मूकावेल्ली गांव में तो उन्होंने पाशविकता की सारी हदें तोड़ डालीं. अपने खेत पर काम कर रही दो महिलाओं को घेरकर नगा पुलिस वालों और 'सलवा जुडूम' गुण्डों ने सामूहिक बलात्कार के बाद उनकी हत्या की. उनमें से एक महिला गर्भवती थी जिसकी कोख को उन दरिंदों ने चाकुओं से चीरकर भ्रूण को बाहर निकालकर फेंक दिया. एक महिला के डेढ़ साल के नन्हे बच्चे को भी गोली मारकर घायल कर दिया. नगा जवानों ने सोनिया नामक एक आंगनवाड़ी शिक्षिका को इस शक पर कि वह नक्सली समर्थक है, बांधकर थाने में यातनाएं दीं. नवम्बर 29-30 तारीख को उन्होंने इन्द्रावती नदी के उत्तर में वेड़मा और डुंगा गांवों पर हमला बोलकर सारे घर जला दिए. दुकारू और बुधरू नामक दो मासूम किसानों की निर्मम हत्या की. खेतों में खड़ी फसल में आग लगा दी.

नगा और सीआरपी बलों का आतंक दिसम्बर महीने में माड़ डिवीजन के डौला और उत्तर बस्तर डिवीजन के कोइलीबेड़ा इलाकों में भी पहुंच गया. काकनार इलाके में जन संगठन नेता कॉमरेड जलमा को नगा पुलिस बलों ने मार डाला. गांव की कई महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया. उसके पहले 14 नवम्बर 2005 को इंद्रावती नदी के किनारे एहकेल गांव पर पुलिस ने जन संगठन कार्यकर्ताओं पर तब घात लगाकर हमला किया जब वे खेत में फसल काट रहे थे. अंधाधुंध गोलीबारी करके एक महिला समेत 3 लोगों की हत्या की और कुछ लोगों को घायल किया. दरअसल जन संगठन कार्यकर्ता और जन मिलिशिया सदस्य उस गांव में पुलिसिया दमन से डरकर भाग चुके लोगों की फसल काट रहे थे. पार्टी

और जन संगठनों ने यह फैसला लिया था कि जो लोग डर के मारे भागकर तथाकथित राहत शिविरों में रह रहे हैं, उनकी फसलें काटकर सुरक्षित रखी जाएं और जब भी वे लौट आएंगे तो उन्हें सौम्प दी जाएं. निरीह लोगों की हत्या कर पुलिस अधिकारियों ने इसे नक्सलियों के साथ मुठभेड़ बताकर 3 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया. दो घायल ग्रामीण महिलाओं को महिला नक्सली बताकर जेल में सड़ाया जा रहा है, जबकि असल में वे अपने खेतों में काम करने के दौरान हुई पुलिस की एकतरफा गोलीबारी में घायल हुई थीं.

उपरोक्त तथ्य केन्द्रीय-राज्य पुलिस बलों और 'सलवा जुडूम' गुण्डावाहिनी द्वारा आए दिन किए जा रहे अनगिनत अकथनीय जुल्मों के कुछ उदाहरण भर हैं. एक गांव में एक किशोर का सिर कलम कर उसके घर के दरवाजे पर लटका दिया जाता है, तो किसी और गांव में एक बूढ़े किसान का सिर कलम कर धड़े को गांव के बीचोबीच टांग दिया जाता है और वहां यह संदेश छोड़ा जाता है कि आत्मसमर्पण नहीं करने पर सभी का यही हश्र होगा. पीएलजीए का लाल योद्धा कॉमरेड पाकलू एक मुठभेड़ के दौरान घायल हो दुश्मन के हाथों पड़ गया था जिसे नगा पुलिस वालों और गुण्डों ने निर्मम तरीके से मार डाला. उसके शरीर के सारे अंग टुकड़ों में काट दिए. जननांग काट दिए और सिर कलम कर बीजापुर ले जाकर एसपी केएल मनहर के सामने पेश किया. कई अन्य लोगों की हत्या कर लाशें इन्द्रावती नदी में बहा दीं. कुछ लाशें कुटरू और बीजापुर कस्बों में यूं ही बाहर सड़कों पर फेंक दीं तो उन्हें कुत्तों ने खाया. मानवता की सारी हदें पार करने वाले इस जुल्मी 'सलवा जुडूम' की जघन्य करतूतों की फेहरिश्त काफी लम्बी है. लेकिन इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, एक न एक दिन उन्हें इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी.

इस जुल्मी अभियान की आड़ में जो लूटपाट मचाई जा रही है उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है. सैकड़ों पुलिस, अर्ध सैनिक और गुण्डे विदेशी हमलावरों की तर्ज पर गांवों पर धावा बोलते हैं और हर घर में लूटपाट मचाते हैं. अनाज, नगद पैसा, बरतन-भाण्डा, जेवरात, मुरगियां, बकरे, सुअर, बैल आदि सब चीजों को ये हत्यारे लूट रहे हैं. आत्मसमर्पण करने वालों को भी वे नहीं बख्श रहे हैं. उन्हें अमानवीय यातनाएं दी जा रही हैं. तथाकथित राहत शिविरों में रह रहे पीड़ित जब इन यातनाओं के चलते दम तोड़ देते हैं तो उनकी लाशें उठाकर इंद्रावती नदी में फेंक रहे हैं.

सरकार लोगों को जबरन बन्दी शिविरों में कैद कर रही है जिन्हें वह 'राहत शिविर' बताकर बाहरी जनता को दिग्भ्रमित कर रही है. जिस तरह अमेरिकी सेनाओं ने वियत्नाम में किया था, अंग्रेजी सेनाओं ने मलया में किया था और 'स्वतंत्र' भारत की नेहरू सेनाओं ने तेलंगाना में अपनाया था, वही रणनीतिक उपग्राम नीति या 'ब्रिग्स योजना' अपनाकर सरकार लोगों को 'राहत शिविरों' में रख रही है ताकि उन्हें क्रान्तिकारी आन्दोलन से अलग किया जा सके. और तो और सरकार यह झूठा प्रचार कर रही है कि ये सब नक्सल अत्याचारों से पीड़ित हैं जिन्हें पुलिस सुरक्षा दे रही है. सच तो यह है कि इन 'राहत शिविरों' में रह रहे लोगों से पुलिस-अर्ध सैनिक बल बेगारी करवा रहे हैं. तरह-तरह की 'विकास' योजनाओं के नाम से आवंटित पैसों को पुलिस-प्रशासन के अधिकारी डकार रहे हैं तो शिविरों में रह रही जनता भूखों मर रही है. खाना तो दूर पीने के पानी के लिए भी उन्हें तरसना पड़ रहा है. कई लोगों ने तो मामूली बीमारियों से दम तोड़ बैठा. लोगों की लाचारी का आलम यह है कि अपने मृत परिजनों को दफनाने के लिए भी उन्हें जगह नहीं मिल रही है. दरअसल आदिवासियों को जबरन वहां रखकर अपनी जमीन व जंगल से दूर किया जा रहा है. उनकी संस्कृति का विनाश किया जा रहा है. जो लोग शिविरों से वापस अपने गांव जाना चाहते हैं उन्हें यातनाएं दी जा रही हैं. नगा पुलिस व एसपीओ नामधारी गुण्डे राहत शिविरों में रह रही महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं, उनका यौन शोषण कर रहे हैं. खबरें हैं कि कई महिलाएं गर्भवती बन गई हैं. पुलिस-प्रशासन की बन्दिशों की परवाह न करते हुए कई लोग अब भागकर अपने घरों में वापस आने लगे हैं.

जिस किसी पर भी यह शक हुआ कि वह नक्सलियों का समर्थक है या संघम सदस्य है तो उसे क्रूरतापूर्ण तरीके से यातनाएं दी जाती हैं. कई आदिवासियों पर पुलिस मुखबिरी करने का दबाव डाला जा रहा है. खासकर बीजापुर और भैरमगढ़ ब्लॉकों में जनवादी और नागरिक अधिकारों का नामोनिशान तक नहीं है. इस क्षेत्र के अधिकतर गांवों में पुरुष नहीं हैं. वे या तो जान हथेली पर रखकर कहीं दूर भाग गए हैं या फिर उन्हें जबरन 'राहत शिविरों" में बन्दी बनाकर रखा गया है. वहां उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है. आदिवासियों की खेतीबाड़ी ठप्प हो चुकी है. इन तमाम कार्यवाहियों से आदिवासियों का आर्थिक और सामाजिक जीवन ढांचा पूरी तरह टूट चुका है.

'सलवा जुडूम' की शुरूआत दन्तेवाड़ा जिले के भैरमगढ़ और बीजापुर ब्लॉकों में हुई थी और कर्मा, कश्यप, नेताम, अन्सारी आदि ने दावा किया था कि बहुत जल्द इसे समूचे बस्तर में फैलाया जाएगा. दावे तो यहां तक किए जा रहे थे कि पूरे देश में इसे एक नमूने के तौर पर पेश किया जाएगा. नवम्बर 2005 में रायपुर और बिलासपुर शहरों में 'सलवा जुडूम' की रैलियां निकाली गईं जिनमें सरकारी जूठन खाने वाले कुछ इने-गिने लोगों ने ही भाग लिया. लेकिन अत्यधिक शहरी मेहनतकश जनता ने इन रैलियों से दूर रहकर इसका मौन विरोध किया. सलवा जूडूम के विस्तार का जहां तक सवाल है, 9 महीने के बाद भी ऊसूर और भूपालपटनम ब्लॉकों में इसे फैलाने के लिए कर्मा-कश्यप-अन्सारी-पिस्दा की चौकड़ी चौकड़ी हाथ-पैर मार रही है. साफ जाहिर है, स्थानीय जनता के जबर्दस्त प्रतिरोध ने ही इन लुटेरों और हत्यारों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है. इसे नारायणपुर इलाके में फैलाकर माड़ अंचल में विस्तार करने की भी साजिशें रची जा रही हैं. लेकिन नारायणपुर और उसके आसपास के गांवों के सभी वर्गों की जनता ने इसका सिरे से विरोध किया. सिर्फ मुट्ठी भर गोपनीय सैनिकों या मुखबिरों के जरिए सभाओं का आयोजन कर उन्हें 'जन सभा' की संज्ञा दी जा रही है. हालांकि सरगुजा और जशपुर जिलों में भी 'सलवा जुडूम' के विस्तार की बातें की गई थीं लेकिन वहां की संघर्षशील जनता ने क्रान्तिकारी संघर्ष का परचम बुलन्द रखते हुए लुटेरों की नापाक कोशिशों को नाकाम कर दिया.

क्या 'सलवा जुडूम' माओवादियों के खिलाफ जनता की बगावत है?

नहीं, यह माओवादियों के खिलाफ जनता की बगावत कतई नहीं है, बल्कि शासक वर्गों द्वारा चलाया जा रहा अत्यंत बर्बरतापूर्ण दमन अभियान है.

'सलवा जुडूम' दण्डकारण्य की संघर्षरत जनता को हत्या और आतंक के जरिए भयभीत करने के लक्ष्य से छेड़े गए दमनकारी अभियान के अलावा कुछ भी नहीं है. स्थानीय प्रतिक्रियावादी ताकतें और जनता के

खिलाफ किए अपराधों के लिए दण्डित किए गए लोगों का एक तबका इसमें खूब पैसा खर्च कर रहा है और लम्पट तत्वों को इकट्ठा कर रहा है. पुलिस उन्हें प्रशिक्षित कर, हथियारबन्द कर 'विशेष पुलिस अधिकारी' के नाम से नियुक्ति भी दे रही है. ये गुण्डे राज्य और केन्द्र के सशस्त्र बलों के साथ मिलकर 200-300 की संख्या में गांवों पर दण्डात्मक हमले कर रहे हैं जिन्हें माओवादियों का गढ़ माना जाता है. अभी महेन्द्र कर्मा और रमन सरकार 'सलवा जुडूम' को दक्षिण बस्तर डिवीजन के कोंटा और बासागूडेम इलाकों में फैलाने की जी-तोड़ कोशिश कर रही है. पर वहां की स्थानीय जनता इन कोशिशों को विफल करने के लिए कमर कस चुकी है. पीएलजीए के सभी बलों के सैनिक एक के बाद एक हमले करके भाड़े के नगा और सीआरपी बलों के छक्के छुड़ा रहे हैं. जनता का व्यापक प्रतिरोधी संघर्ष न सिर्फ जुल्मी 'सलवा जुडूम' पर अंकुश लगा पा रहा है, बल्कि उसे 'जनता का सस्फूर्त आन्दोलन' बताने वालों को बेनकाब भी कर रहा है.

मीड़िया की बेहद संदिग्ध भूमिका

इस 'सलवा जुडूम' अभियान ने देश के बड़े प्रसार माध्यमों (मीडिया) के जन विरोधी चरित्र को साफ तौर पर नंगा कर दिया. 'सलवा जुडूम' के नाम पर जारी कत्लेआमों और अन्य अत्याचारों पर मीडिया ने पूरी तरह चुप्पी साध रखी है. इसके बावजूद भी कि अब तक करीब 100 गांव जलाए जा चुके हैं और मीडिया को स्थानीय प्रतिनिधियों को अच्छी तरह मालूम है कि इन जघन्य अपराधों के पीछे किसका हाथ है, फिर भी मीडिया ने जानबूझकर अपनी आंख बन्द कर ली है. जब कभी भी एकाध प्रगतिशील पत्रकार तथ्यात्मक रिपोर्टें भेजता भी है तो मीडिया सम्राट उन्हें दबा दे रहे हैं. और तो और, मीडिया यह चित्रित करते हुए कि ''सलवा जुडूम'' नक्सलवादियों की कथित हिंसा और अत्याचारों के खिलाफ आदिवासी जनता द्वारा छेड़ा गया 'सस्फूर्त विद्रोह' है, एक के बाद एक लगातार झूठी कहानियां गढ़ रही है.

पुलिस अमला अपने बंदी शिविरों (तथाकथित राहत शिविरों) से कुछ लोगों को उठा लाकर समर्पित नक्सली बताकर मीडिया के सामने प्रस्तुत करता है. और मीडिया के लोग शर्म-हया छोड़कर पुलिस द्वारा आयोजित पूर्व नियोजित नुमाइशों में उनका इंटरव्यू लेते हैं तथा माओवादियों के खिलाफ आए दिन झूठी खबरें गढ़ते रहते हैं. इन्हें देखकर हमें अमेरिका के एमबेडेड पत्रकारों की याद आ जाती है जिनका इराक पर अमेरिकी हमले और बमबारी के दौरान इस्तेमाल किया गया था. जून 18 और 19 को ताड़मेंडरी और कोतरापाल गांवों में घटित घटनाओं को लेकर मीडिया ने इस अंदाज में झूठी खबरें फैलाईं कि शायद उन्हें सुनकर कब्र में लेटे गोबेल्स भी दंग रह जाए. जून के दूसरे पखवाड़े और जुलाई महीने के दौरान कई कहानियां प्रसारित की गईं कि बीसियों आदिवासियों को माओवादियों ने मार डाला. ये झूठी कहानियां आज तक नहीं थमीं. उदाहरण के लिए, 'फ्रन्टलाइन' (अंग्रेजी पत्रिका) के 21 अक्टूबर 2005 के अंक में अन्नी जैदी ने लिखा, ''ताड़मेंडरी में आयोजित सभा पर, जिसमें 10 हजार से ज्यादा लोगों ने भाग लिया, नक्सलवादियों ने कथित तौर पर गोलियां चलाईं और सैकड़ों लोगों की हत्या की.'' तेलुगु अखबार 'वार्ता' में आनन्द राव ने भी कुछ ऐसा ही लिखा. तेलुगु की खबरिया चैनल 'टीवी9' ने कई बार बताया कि नक्सलवादियों ने कोतरापाल में 12 ग्रामीणों की हत्या की. रायपुर से छपने वाला अखबार 'दैनिक भास्कर' ने रंगीन तस्वीरों के साथ यही झूठी खबर कई बार लिखी. लेकिन सच्चाई यह है कि ताड़मेंडरी और कोतरापाल में महेन्द्र कर्मा की अगुवाई में आ रहे हमलावर गुण्डों व पुलिस बलों पर जनता ने जवाबी हमला किया था. जनता के इस जवाबी हमले में कोतरापाल में तीन गुण्डे मौके पर ही मारे गए थे जबकि कुछ अन्य को लोगों ने गिरफ्तार किया था. ताड़मेंडरी की घटना में तो एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, ऐसा दन्तेवाड़ा जिले के कलेक्टर पिस्दा ने खुद ही एक रिपोर्ट में बताया.

पुलिस के आला अधिकारी स्वयं ऐसी रिपोर्टें लिखवाकर उन्हें सभी अखबारों में प्रकाशित करवा रहे हैं. अखबार वाले उनकी प्रामाणिकता पर बिना कोई सवाल उठाए ही, जस की तस छाप रहे हैं. पढ़ने से रिपोर्टिंग ऐसी लगती है मानों पत्रकार ने खुद अपनी आंखों से देखकर यह सब लिखा होगा. पर उसकी पोल तब खुल जाती है जब हम पाते हैं कि वही खबर 'दैनिक भास्कर', 'नव भारत', 'हरिभूमि' और अन्य पत्रिकाओं में हू-ब-हू उसी रूप में छापी जाती है. यहां तक कि शीर्षक, शब्द और संलग्न तस्वीर भी सभी अखबारों में एक ही होते हैं. इससे साफ पता चलता है कि इन अखबारों के प्रबन्धन ने लुटेरे शासक वर्गों के साथ पूरी तरह सांठगांठ कर रखी है और एक नीति के तौर पर क्रान्तिकारी आन्दोलन के खिलाफ जहरीला प्रचार शुरू कर दिया है. वहीं पार्टी कमेटियों और प्रगतिशील जन संगठनों द्वारा जारी बयानों को वे दबाकर रख रहे हैं. मीडिया प्रबन्धन पत्रकारिता के नैतिक आदर्शों की धज्जियां उड़ा रहे हैं. लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहलाने वाली मीडिया वास्तव में पूंजी का एक औजार बनकर काम कर रही है.

अखबार वाले झूठी खबरें तो लिख ही रहे हैं, साथ ही साथ, वे पुलिसिया अत्याचारों को स्वीकृति भी दे रहे हैं. उदाहरण के लिए 8 फरवरी 2006 के 'दैनिक भास्कर' के 'बस्तर भास्कर' पन्ने पर कोंटा क्षेत्र में 'सलवा जुडूम' के सम्बन्ध में सुरेश रावल ने अपने रिपोर्ट में लिखा, ''अनेक गांवों में जब नगा फोर्स के जवान पहुंचे तो उन्हें घर खाली मिला.... नगा पुलिस ने चेतावनी दी कि घर खाली मिला तो जला दिया जाएगा... सूत्रों ने कहा कि नगा जवानों ने कुछ गांवों में खाली घरों को आग के हवाले कर दिया है. नीलामडुगू में कुछ घर जलाने की जानकारी सूत्रों से ज्ञात हुई.'' हैरान की बात है, इस रिपोर्ट में लोगों के घरों को जलाने के जघन्य अपराध के खिलाफ कोई आपत्ति नहीं उठाई गई. लोग चाहे किसी के भी डर से भागे हों, उनके घरों को जलाने का अधिकार आखिर पुलिस व अर्ध सैनिक बलों को किस संविधान ने दिया है. इस तरह की रिपोर्टिंग के जरिए अखबार वाले परोक्ष रूप से पुलिस व 'सलवा जुडूम' के गुण्डों द्वारा आदिवासियों के खिलाफ किए जा रहे अपराधों को क्या जायज नहीं ठहरा रहे हैं?

13 जनवरी 2006 के 'दैनिक भास्कर' में ताकिलोड़ में हुई 'सलवा जुडूम' सभा के संदर्भ में सुरेश महापात्र ने यूं लिखा, ''... पता चला सभी घर खाली पड़े हैं पर घरों में कोई है यह जतलाने के लिए नक्सलियों ने हर घर से धुएं निकलने का इंतजाम कर दिया था. हर गांव से धुएं की धुंध उठ रही थी. जिसके पीछे कहीं ओझल हो गए थे लाल चेहरे, निशान, नारे.'' हैरान की बात है कि इस रिपोर्ट का शीर्षक ही उन्होंने ''नदी के पार धुंए की धुंध में ढंका लाल चेहरा'' रखा. एक अत्यंत जघन्य और फासीवादी कार्यवाही को किस तरह तोड़ा-मरोड़ा जा सकता है, इसे कोई 'दैनिक भास्कर' के सुरेश महापात्र से ही सीख सकते हैं. सच्चाई यह है कि 12 जनवरी के दिन करीब 500 पुलिस व अर्ध सैनिक बलों के साथ-साथ कुछ सौ गुण्डों (जिन्हें अब 'विशेष पुलिस अधिकारी' का

'कोया भूमकाल मिलिशिया' का ऐलान

लुटेरे शासक वर्गों ने साम्राज्यवादियों की शह पर हमारी 'जनताना सरकार' का समूल नष्ट करने तथा अपने 'कोया' समुदाय का सफाया करने का फैसला ले रखा है. 'कोया' समुदाय का मतलब माड़िया, मुरिया, गोण्ड, राज गोण्ड, दोरला, दंडामी, गांडो, हल्बी, भतरा – आदि तमाम शोषित आदिवासी समुदायों का मिश्रण है जोकि सदियों से दण्डकारण्य में निवासरत हैं. इन सभी समुदायों का खात्मा करना लुटेरी सरकारों की साजिश का हिस्सा है. ऐसा करके वे दण्डकारण्य को टाटा, एस्सार, मित्तल, जिन्दल जैसे बड़े पूंजीपतियों और साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की लूट का चारागाह में तब्दील करना चाह रही हैं. इस रास्ते में सबसे बड़ा अवरोध यहां पर पिछले 25 सालों से जारी क्रान्तिकारी आन्दोलन है. इसीलिए वे यहां की जनता का सफाया कर क्रान्तिकारी आन्दोलन की कमर तोड़ना चाह रही हैं. पिछले 25 बरसों की लड़ाई के दौरान लूटपाट के जो रस्मोरिवाज बन्द हो चुके थे उन्हें दोबारा चालू करने की बातें की जा रही हैं. इसी को 'सलवा जुडूम' का नाम देकर महेन्द्र कर्मा, केदार कश्यप, रामविचार नेताम, बलिराम कश्यप जैसे झूठे आदिवासी नेताओं को सामने लाया गया है. इस अभियान के तहत अभी तक 150 से ज्यादा आदिवासी स्त्री–पुरुषों की निर्मम हत्या की गई. 100 से ज्यादा गांवों में 2,000 से ज्यादा घरों को जलाकर राख कर दिया गया. करीब 5 करोड़ रुपए की सम्पत्ति तहस–नहस कर दी गई. 50 से ज्यादा महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया.

कोयतूर भाइयो और बहनो! सुनो! इस जुल्मी 'सलवा जुडूम' के खिलाफ अब भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के नेतृत्व में 'कोया भूमकाल मिलिशिया' उठ खड़ी हुई है. 'सलवा जुडूम' को खत्म किए बिना हमारा कोया समुदाय बच नहीं सकता. चुगलखोरो, एसपीओ नामधारी गुण्डो, नगा पुलिस, टास्क फोर्स, सीआरपीएफ वालो! खबरदार! महेन्द्र कर्मा, केदार कश्यप, रमन सिंह, एमडब्ल्यू अन्सारी, कलेक्टर केआर पिस्दा! खबरदार! जब तक 'सलवा जुडूम' को जड़ से मिटा नहीं दिया जाएगा तब तक 'कोया भूमकाल मिलिशिया' को कोई आराम नहीं! इसलिए हमारी 'कोया भूमकाल मिलिशिया' अपनी जन मुक्ति छापामार सेना (पीएलजीए) के अन्य बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने और जनयुद्ध को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है!

नव युवतियो, युवको! स्त्री–पुरुषो! किशोर–किशोरियो! आओ! सब लोग हमारी 'कोया भूमकाल मिलिशिया' में शामिल हो जाओ! इसे और मजबूत बनाओ! हाथ में जो भी चीज मिले उसे हथियार बनाकर इस्तेमाल करो! पत्थर, ढेला, चाकू, गुम्ती, बंडा, कुल्हाड़ी, फरसी, भाला, मिर्च पावडर, तीर–धनुष, भरमार, रायफल, बम – जो भी हाथ लगे उसका दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करो! इसकी चिन्ता न करो कि हमारे पास आधुनिक हथियार नहीं है. दुश्मन के हाथों में मौजूद हथियारों को छीनकर उन्हीं के सीने पर तान देंगे! युद्ध में हार–जीत का फैसला आधुनिक हथियार नहीं करते!! सचेत जनता ही युद्ध में हार–जीत का फैसला करती है!!! हम अपने बूढ़ों, नन्हे बच्चों, मां–बहनों की हिफाजत करेंगे. हमारे घरों और अनाज को बचा लेंगे. गाय–बैल और बकरों–सूअरों को बचा लेंगे. तमाम शोषित जनता हमारे पक्ष में है. इन्साफ हमारी तरफ है. आखिरी जीत हमारी ही होगी, इसमें कोई शक नहीं है. लुटेरे शासक वर्गों व उनके साम्राज्यवादी आकाओं को दफना देंगे. असली लोकतंत्र की स्थापना करेंगे. हमारी अपनी 'जनताना सरकार' को मजबूत बनाएंगे और उसका विस्तार करेंगे.

तमगा मिला हुआ है) ने ताकिलोड़ पर एक विदेशी सेना की तर्ज पर हमला बोलकर करीब 200 घरों को पूरी तरह जला दिया था. ताकिलोड़ के अलावा आसपास के सभी गांवों में उन्होंने जाते-आते हुए दर्जनों घर जला दिए. उस क्षेत्र की समूची जनता ने इस खतरे को पहले ही भांपकर गांव खाली कर जंगल में शरण ले रखी थी. यह सब जान-समझकर भी इतनी नीचता के साथ तोड़-मरोड़कर खबरें लिखने वालों की कितनी भी निंदा की जाए, कम है. पुलिस व गुण्डावाहिनी द्वारा लोगों के घर जलाए जाने की सच्चाई को दबाकर ''नक्सलियों द्वारा हर घर से धुएं निकलने का इंतजाम'' के रूप में उसका चित्रण करना न सिर्फ झूठ है, बल्कि आपराधिक झूठ है.

इसी अखबार में इसी पत्रकार ने ताकिलोड़ गांव में महेन्द्र कर्मा और रामविचार नेताम के समक्ष नगा पुलिस बलों, सीआरपीएफ और एसपीओ गुण्डों द्वारा शहीद स्मारक को तोड़ने के विफल प्रयास का बखान किया. इस गांव में जनता ने कुछ साल पहले अपने प्यारे केन्द्रीय नेता कॉमरेड्स श्याम, महेश और मुरली की याद में एक स्मारक का निर्माण किया था. मृत व्यक्ति की विचारधारा चाहे जो भी हो, जनता को यह पूरा अधिकार है कि वह अपनी मर्जी से स्मारक बनाए. लेकिन तोते की तरह हर पल लोकतंत्र की रट लगाने वाले पत्रकारों को इस नीचतापूर्ण हरकत पर थोड़ी सी भी शर्म महसूस नहीं हुई. उसे तोड़ने वालों की रंगीन तस्वीरें खींचकर बाकायदा अखबारों के पहले पन्ने पर छाप भी डालीं. इतिहास बताता है कि इलाहाबाद के आलफ्रेड पार्क में जंगे आजादी के सेनानी 'आजाद' चन्द्रशेखर की हत्या के बाद अंग्रेजों ने वहां उस पेड़ को काट डाला था जिसके नीचे आजाद की मृत्यु हुई थी. उन्हें डर था कि उस पेड़ की पूजा करने वाले लोगों को अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा मिल सकती है! आज अंग्रजी साम्राज्यवादियों के सच्चे वारिस महेन्द्र कर्मा, रमन सिंह व रामविचार नेताम क्रान्तिकारी नेताओं के स्मृति चिन्हों को भी तोड़ने पर तुले हुए हैं क्योंकि उन्हें डर है कि मरने के बाद भी शहीद नेता स्मारक के रूप में जनता को शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देते रहेंगे. वे ऐसा करते भी क्यों नहीं?! आखिर बाबरी मस्जिद (1992) ढहाने वालों तथा महान सूफी शायर वली गुजराती (2002) के मकबरे को तोड़कर उसके ऊपर से सड़क बिछाने वालों के वारिस जो ठहरे!!

रायपुर में आयोजित 'सलवा जुडूम' सभाओं में 'दैनिक भास्कर', 'नव भारत', 'हरिभूमि' आदि अखबारों के प्रबन्धनों का शामिल होना और उनके अखबारों में इस तरह की लगातार रिपोर्टिंग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. साफ जाहिर है, देश की मीडिया बड़े पूंजीपतियों की मुट्ठी में बन्द है, जिनकी सांठगांठ साम्राज्यवादियों के साथ है. सारे लुटेरे वर्ग दण्डकारण्य समेत देश के अनेक हिस्सों में उभर रही जनता की नई जनवादी

राजसत्ता से बौखलाए हुए हैं. इसीलिए उन्होंने एक सोची-समझी साजिश के तहत 'सलवा जुडूम' जैसा छद्म दमन अभियान शुरू कर रखा है. लेकिन छत्तीसगढ़ और समूचे देश की मेहनतकश जनता को मीडिया की इस नीचतापूर्ण भूमिका को समझने और उसका पर्दाफाश करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी.

आरएसएस की षड़यंत्रकारी भूमिका

छत्तीसगढ़ में भाजपा के सत्तारूढ़ होने में आरएसएस के 'आदिवासियों की घर वापसी' अभियान का बड़ा योगदान रहा. पिछले कुछ दशकों से खासकर छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों को अपनी पकड़ में लेने के लिए आरएसएस और उसके संघ गिरोह के अन्य संगठन सुनियोजित तरीके से काम कर रहे हैं. आदिवासियों को हिन्दू बताकर बड़े पैमाने पर झूठा प्रचार कर रहे हैं. लाखों किताबें छपवा रहे हैं. दण्डकारण्य में क्रान्तिकारी आन्दोलन का सफाया करना आरएसएस का एक बड़ा लक्ष्य है ताकि इस इलाके को वह अपने मजबूत वोटबैंक में बदल सके और इस समूचे इलाके को साम्राज्यवादी लूट का मैदान बनाया जा सके. इसलिए वह अपनी छद्म धार्मिक संस्थाओं के जरिए आदिवासियों के बीच फूट के बीज बोने की जी-तोड़ कोशिश कर रहा है. खासकर इंद्रावती नदी के दोनों तरफ 'सलवा जुडूम' का सक्रिय नेतृत्व करने वालों में अधिकतर 'मालाधारी' और अन्य धार्मिक संगठनों के लोग ही हैं. और वे जिस तरह लोगों की गला रेत कर हत्या कर रहे हैं, महिलाओं के साथ सामूहिक हत्या कर रहे हैं, बच्चों की हत्या कर रहे हैं और गर्भवती माताओं की कोख को चाकुओं से चीरने के जो करतूत सामने आ रहे हैं - क्रूरता और बर्बरता के मामलों में इन घटनाओं का मेल 2002 में संघ गिरोह द्वारा गुजरात में किए गए दंगों के दौरान हुई घटनाओं से खा रहा है. 'सलवा जुडूम' के नाम पर आदिवासियों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने की घिनौनी साजिश के पीछे आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका है. माता रुकमणी आश्रम जैसे संगठन 'सलवा जुडूम' का सक्रिय सहयोग दे रहे हैं. इस साजिश को आदिवासी जनता को समझना होगा. उसे विफल बनाकर इस क्षेत्र को साम्राज्यवादी लूट का चारागाह बनाने के उनके नापाक मंसूबों पर पानी फेरना होगा.

जनता का शानदार प्रतिरोध

पुलिस व अर्ध सैनिक बल एक के बाद एक लगातार दमनात्मक ऑपरेशनों को अंजाम दे रहे हैं. कॉर्पेट सेक्यूरिटी के नाम से 5-10 किलोमीटर की दूरी पर दर्जनों पुलिस कैम्प बिठाए गए हैं. पूरे इलाके को सेक्टरों में बांटकर फौजी तौर-तरीकों में हजारों पुलिस-अर्ध सैनिक बलों को एक साथ उतारकर गहन खोजबीन व सफाया अभियान चलाए जा रहे हैं. ऑपरेशन ग्रीन हन्ट 1, 2, 3 के नाम से लगातार कई आपरेशन चलाए जा चुके हैं और अभी भी जारी हैं. एक नगा बटालियन पहले से मौजूद है, और एक बटालियन की मांग राज्य सरकार कर रही है. सीआरपीएफ की दो अतिरिक्त बटालियनों की मांग कर रही है. सैकड़ों लम्पट युवाओं को विशेष पुलिस अधिकारी के बतौर नियुक्त किया जा रहा है. खासकर विंजरम और बैलाडीला में हुए बहादुराना हमलों के बाद केन्द्र सरकार ने आनन-फानन एनएसजी (ब्लैककैट्स) के 330 कमाण्डो भेज दिए हैं.

इसके बावजूद भी दण्डकारण्य की जनता ने प्रतिरोध का परचम ऊंचा रखा हुआ है. हत्या, बलात्कार, लूटपाट, घर जलाना, गिरफ्तारी, यातना - इन सबके बावजूद भी दण्डकारण्य जनता का मनोबल नहीं टूटा बल्कि वह अनमोल कुरबानियां देकर वर्तमान जनयुद्ध को नई बुलन्दियों पर पहुंचा रही है. पीएलजीए की अगुवाई में 'कोया भूमकाल मिलिशिया', जन संगठनों और जनताना सरकार के कार्यकर्ताओं के साथ आम लोग भी सैकड़ों हथियारबन्द कार्रवाइयों को अंजाम देकर जबर्दस्त कामयाबियां हासिल कर रहे हैं. 3 सितम्बर 2005 को पीएलजीए के लाल योद्धाओं ने बीजापुर के निकट पुलिस के माइन प्रूफ गाड़ी की धज्जियां उड़ाकर सीआरपीएफ के 24 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था. गौरतलब है कि इस कामयाब कार्रवाई का नेतृत्व पीएलजीए की एक महिला कमाण्डर ने किया था. इस कार्रवाई में पीएलजीए ने 3 स्वचालित रायफलें जब्त कर लीं. इसके अलावा पदेड़ा, भेज्जी, मेंडरी, विंजरम, बैलाड़ीला, चिन्तलनार आदि कार्रवाइयों में 20 से ज्यादा सशस्त्र बलों का सफाया कर दर्जनों को घायल कर दिया गया. 20 से ज्यादा एसएलआरें पीएलजीए ने छीन लीं. खासकर विंजरम और बैलाड़ीला हमलों ने पीएलजीए के गौरवशाली इतिहास में चार चांद लगा दिए. (पीएलजीए की प्रतिरोधी कार्रवाइयों की तफ्सील रिपोर्टें अलग से दी गई हैं.) इसके अलावा, इस जुल्मी 'सलवा जुडूम' का नेतृत्व करने वाले कुछ मंजे हुए गुण्डों व चोर नेताओं को भी जनता ने मार गिराया. ऐसे कुछ कट्टर जन दुश्मनों के घरों पर धावा बोलकर उनकी सारी सम्पत्ति छीन ली. इस तरह हजारों जनता ने सैकड़ों हथियारबन्द कार्रवाइयों में भाग लेकर सरकार के झूठे प्रचार का मुंहतोड़ जवाब दिया और साथ ही साथ, वर्तमान जनयुद्ध को आगे बढ़ाने का अपना संकल्प दोहराया.

तमाम प्रगतिशील व जनवादी ताकतों से अपील

यह है पिछले 9 महीनों से दण्डकारण्य में जारी हत्या और अराजकता के अभियान की एक तस्वीर. हम तमाम जनता की तरफ से आपसे अपील करते हैं कि आप इस फासीवादी जुल्मी अभियान को तत्काल बन्द कराने हेतु अपनी आवाज उठाएं. साम्राज्यवादियों (खासकर अमेरिकी साम्राज्यवादियों) का समर्थन प्राप्त भारत सरकार हमारे देश के शोषित जन समुदायों पर एक गृहयुद्ध थोपना चाह रही है. उनकी जायज मांगों और जीविका सम्बन्धी समस्याओं को हल करने की बजाए उन्हें और ज्यादा गरीबी और तबाही की अंधेरी गर्त में धकेल रही है ताकि जिन्दल, मित्तल, टाटा, रिलएन्स जैसे बड़े पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का मुनाफा पहुंचाया जा सके. इन डकैतों के लिए भारत को लूट का चारागाह बनाने की कोशिश कर रही है. जिस तेजी से इनके साथ एमओयू किए जा रहे हैं, जैसे कि पिछले एक साल में देखा गया है, उसे देखकर यह अन्दाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि आने वाले 30-40 सालों में देश में लौह अयस्क के भण्डार पूरी तरह खत्म हो जाएंगे. यह 'विकास' नहीं, बल्कि 'विनाश' है. देश की समृद्ध खनिज सम्पदा लूटी जा रही है. जंगलों की तबाही की जा रही है. नदियां प्रदूषित की जा रही हैं और समूचे पर्यावरण को ही बिगाड़ा जा रहा है. देश की विशाल जंगली पट्टियां खदान माफिया के हवाले कर दी जा रही हैं. यह सब साम्राज्यवादियों के साथ सांठगांठ कर चुके शासक वर्गों द्वारा अपनाई जा रही नव-उदार नीतियों का नतीजा है, जोकि अपने स्वार्थ हितों को साधने के लिए स्थानीय आदिवासियों का दमन करने से नहीं चूकेंगे. आर्थिक उदारीकरण और भूमण्डलीकरण को फासीवादी राजनीतिक दमन की जरूरत है.

देशवासियों को तथाकथित शांति और 'आतंकवाद' के बीच नहीं, बल्कि साम्राज्यवाद के नेतृत्व वाली इस माफिया और माओवादियों के नेतृत्व वाले जन समुदायों के बीच एक पक्ष को साफ तौर पर चुन लेना होगा. तय करना होगा कि उन्हें किस पक्ष में रहना है क्योंकि विभाजन की रेखाएं साफ तौर पर खींची जा चुकी हैं. ✶

प्रेस विज्ञप्ति

सलवा जुडूम तथ्यान्वेशण संयुक्त कमेटी

(छत्तीसगढ़ व झारखण्ड पीयूसीएल, पीयूडीआर, एपीडीआर और आइएपीएल)

नवम्बर-दिसम्बर 2005

28 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2005 तक एक अखिल भारतीय टीम ने दन्तेवाड़ा जिले का दौरा किया. इस 14 सदस्यीय टीम ने इस जिले में सलवा जुडूम के दौरान मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन की वास्तविकता और जनता के जीवन पर उसके प्रभावों की तहकीकात की. इस टीम ने शिविरों व गांवों में रह रहे लोगों, इस ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों, सलवा जुडूम के नेताओं, पुलिस व नागरिक प्रशासन के अधिकारियों (कलेक्टर, एसडीएम, आदि) से मुलाकातें कीं.

इस तथ्यान्वेषण के निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

1. सलवा जुडूम माओवादियों के खिलाफ आदिवासियों का सस्फूर्त विद्रोह कतई नहीं है, जैसा कि इसके बारे में दावा किया जा रहा है. यह एक संगठित और सरकार द्वारा संचालित उद्यम है, जिसकी जड़ें महेन्द्र कर्मा की अगुवाई में अतीत में चलाए गए जन जागरण अभियानों में पाई जाती हैं. 75 प्रतिशत सलवा जुडूम सभाओं में कलेक्टर खुद शामिल रहे और सुरक्षा बल सलवा जुडूम सभाओं का समर्थन कर रहे हैं. सलवा जुडूम के मुख्य काडर स्पेशल पुलिस अफसर हैं जिन्हें सरकार वेतन दे रही है और हथियारबन्द कर रही है. यह जिस गति से हो रहा है वह देश के अन्य हिस्सों में विद्रोह विरोधी कार्रवाइयों के प्रमाण से मेल खाती है.
2. दन्तेवाड़ा, गीदम और बीजापुर इलाकों में सलवा जुडूम के परिणामस्वरूप पुलिस व प्रशासनिक देखरेख में जनता का बलपूर्वक विस्थापन हो रहा है. आधिकारिक अनुमानों के मुताबिक 420 गांवों के करीब 15 हजार लोग शरणार्थियों की तरह अस्थाई शिविरों में जी रहे हैं. उनके मवेशी और तमाम घरेलू सामान गांवों में ही रह गए हैं. यह समूचा इलाका वीरान हो गया है जबकि नई सड़कें बनाई जा रही हैं और पुलिस व अर्ध सैनिक थानों की स्थापना की जा रही है. यह इलाका पूरा एक विशाल सैन्य छावनी में तब्दील हो चुका है. कई स्थानों पर साप्ताहिक बाजार जैसी नियमित आर्थिक गतिविधियां ठप्प हो गईं.
3. हमने एक भारी अव्यवस्था का नमूना देखा है : जब सलवा जुडूम सभाएं आयोजित होती हैं तब आसपास के गांवों से लोगों को उपस्थित रहने को कहा जाता है. ये सभाएं भारी सुरक्षा बलों की उपस्थिति में आयोजित की जाती हैं. जो गांव इनमें भाग लेने से इनकार करते हैं उन पर सलवा जुडूम, जिला पुलिस व नगा बटालियन के मिले जुले बल बार-बार हमले करते हैं. इसके अलावा नगा बटालियन के अलग से भी हमले होते हैं. इन हमलों के दौरान कई बार लूटपाट, आगजनी और हत्याएं की जाती हैं. समूचा गांव जब तक खाली नहीं हो जाता तब तक हमले लगातार किए जाते हैं. कुछ अन्य मामलों में सिर्फ बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों को बख्शा जाता है. कई गांव इन शिविरों में इसलिए आ रहे हैं ताकि इन हमलों से खुद को बचाया जा सके, यही मुख्य कारण है.
4. जब एक बार शिविरों में आ जाते हैं तो लोगों के सामने सलवा जुडूम का समर्थन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता. कुछ लोगों पर खुद अपने गांवों और आसपास के गांवों के लोगों के खिलाफ मुखबिरी करने का दबाव डाला जाता है. उनके खिलाफ हमलों में भाग लेने पर वे विवश हो जाते हैं. कई परिवार ऐसे भी बंट गए हैं जिनके कुछ सदस्य सलवा जुडूम के समर्थक बन गए हैं तो कुछ अन्य सदस्य गांवों में रह रहे हैं. हमने ऐसे उदाहरण भी देखे हैं कि गांव के युवाओं को सलवा जुडूम उठा ले गया है और उनके परिवारों को उनके सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है.
5. हमने एक भयावहता देखी है कि दन्तेवाड़ा जिले के कई हिस्सों में नागरिक प्रशासन खत्म हो चुका है. सलवा जुडूम सदस्य सड़कों पर नाके खोलकर लोगों के सामान की तलाशी ले रहे हैं. वाहनों और बसों के यातायात को वे ही नियंत्रित कर रहे हैं. शिविरों में आने से मना करने वाले गांवों पर वे आर्थिक नाकेबन्दी लागू करते हैं. वे नागरिक अधिकारियों पर भी अपने आदेशों का पालन करने का दबाव डालने की कोशिश करते हैं.
6. सलवा जुडूम गिरोहों और सुरक्षा दस्तों द्वारा जारी लूटपाट, आगजनी, मारपीट व यातनाओं सम्बन्धी मामलों पर कोई एफआइआर नहीं दर्ज किया जा रहा है. हमें कुछ ठोस उदाहरण बताए गए हैं जिसमें सुरक्षा बलों ने लाशें गांव के अन्दर या नजदीक फेंक दीं. इन हत्याओं को रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है, इसलिए इनकी पुष्टि करना मुश्किल है. कुछ रिपोर्टों के मुताबिक 34 गांवों के 96 लोगों की हत्या की गई है. केवल उन्हीं हत्याओं को रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो माओवादियों ने की हैं. यह बात सही है कि सलवा जुडूम के शुरू होने के बाद माओवादियों द्वारा हत्याओं की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुई है जो अब तक आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 70 है. इसके 'शांति मिशन' होने के दावों के उलट, सलवा जुडूम ने दरअसल ऐसा माहौल पैदा किया है जहां हिंसा अचानक बढ़ गई है.
7. बस्तर समाज के कुछ निश्चित तबकों द्वारा इस सलवा जुडूम को मजबूत समर्थन मिल रहा है. इन तबकों में देश के अन्य हिस्सों से आने वाले कुछ गैर-आदिवासी आप्रवासी अवस्थापक, सरपंच व परम्परागत मुखियागण जिनकी सत्ता को माओवादियों ने चुनौती दे रखी है, कर्मा और उनके समर्थकों जैसे स्थानीय शक्तिशाली राजनीतिक नेता - कांग्रेसी और भाजपाई दोनों मिलकर सलवा जुडूम का समर्थन कर रहे हैं.
8. सैन्यीकरण : हमें कुछ आला अफसरों से सुनने को मिला है कि बस्तर में एक अघोषित युद्ध लड़ा जा रहा है. हमें आशंका है कि आगे और भी बदतर हालात बनने वाले हैं. सीआरपीएफ, नगा बटालियन जैसे अर्ध सैनिक बलों की भारी संख्या यहां मौजूद है. इससे ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है कि अन्य राज्यों से आए हुए सशस्त्र बल आक्रमणकारी सेना जैसा व्यवहार कर रहे हैं. हमने अपनी आंखों से देखा कि नगा बटालियन के जवान एक हमले के बाद

(शेष पेज 10 में....)

पोस्को करार - उड़ीसा की प्राकृतिक सम्पदाओं को लूटने की साजिश

झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा - ये तीन ऐसे राज्य हैं जहां देश के समृद्ध खनिज भण्डार मौजूद हैं. उड़ीसा में 32.9% लौह अयस्क, 59.95% बॉक्साइट, 98.4% क्रोमाइड, 28.8% कोयला और 67.6 % मैंगनीज के भण्डार निक्षिप्त हैं.

विश्व बाजार में पिछले साल इस्पात का दाम दुगुना होने के बाद देश-विदेश की कम्पनियां उड़ीसा की तरफ रुख कर रही हैं. झारखण्ड में इस्पात सम्राट मित्तल, छत्तीसगढ़ में जिन्दल, उड़ीसा में पोस्को (पोहंग स्टील कम्पनी) ने करार कर लिए हैं. दुनिया में इस्पात बनाने वाली सबसे बड़ी कम्पनियों में दक्षिण कोरिया की पोस्को कम्पनी पांचवे स्थान पर है. 22 जून 2005 को पोस्को प्रबन्धन और दलाल नवीन पटनायक की सरकार ने एमओयू पर दस्तखत किए.

नवीन सरकार में जोड़ीदारी करने वाली भाजपा ने दिखावटी विरोध किया. हालांकि तथाकथित वामपंथी पार्टियां, कांग्रेस, उड़ीसा गण परिषद आदि विपक्षी पार्टियों ने विधानसभा में विरोध तो जताया पर करार को रद्द करवाने के इरादे से कोई आन्दोलन नहीं छेड़ा. प्रदेश के जनवादी संगठनों ने इस करार का जमकर विरोध किया. ऑस्ट्रेलिया, जहां विश्व में लौह अयस्क के अत्यधिक भण्डार मौजूद हैं, सिर्फ 10 प्रतिशत का निर्यात कर रहा है. दूसरे स्थान पर स्थित ब्राजील एक टन लोहे का भी निर्यात नहीं कर रहा है. लेकिन भारत तो 50 प्रतिशत का निर्यात कर विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है. इन मूर्खतापूर्ण निर्यातों और विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की खुल्लमखुल्ला लूटखसोट के परिणामस्वरूप अबसे 30 साल बाद भारत में थोड़ा भी लोहा नहीं बचेगा, ऐसा विशेषज्ञों का अनुमान है.

पोस्को कम्पनी को लोहा खदान पट्टे पर देने से उसे सिर्फ 300 से 400 रुपए प्रति टन खर्च आता है. वहीं विश्व बाजार में एक टन लौह अयस्क की कीमत 2 हजार रुपए प्रति टन है. पोस्को को 1500 रुपए प्रति टन के हिसाब से मुनाफा पहुंचाया जा रहा है.

पोस्को ने पहले चीन और ब्राजील के साथ करार करने की कोशिश की थी. पर लोहा खदान पट्टे पर देने के करार का उन देशों की सरकारों ने विरोध किया जिससे उसे भारत की तरफ रुख करना पड़ा. उसने बेहद सस्ते में उड़ीसा सरकार के साथ करार कर लिया. इस करार के मुताबिक पहले 30 साल तक लौह अयस्क का दोहन किया जाएगा और बाद में 20 साल और बढ़ाने का प्रावधान भी है. 30 सालों में पोस्को 18 करोड़ टन लोहे का निर्यात करेगी और 40 करोड़ टन इस्पात के उत्पादन में खपाएगी. 60 करोड़ टन लौह अयस्क के पट्टे से प्रदेश को 40 हजार करोड़ रुपए का घाटा होगा. चूंकि पोस्को अपना कारखाना पारादीप स्थित विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) में लगाएगी, इसलिए उसे निर्यात शुल्क और प्रवेश शुल्क में रियायत देनी होगी जिससे प्रदेश को 20 हजार करोड़ रुपए का और घाटा सहना पड़ेगा. पारादीप में पोस्को अपने निर्यातों के लिए एक विशेष बन्दरगाह बनाने वाली है जिससे पारादीप बन्दरगाह की क्षमता घट जाएगी. बुनियादी संरचना का निर्माण और कच्चामाल की ढुलाई के लिए विशेष रेल लाइन का निर्माण आदि रियायतें अतिरिक्त होंगी. पोस्को 51 हजार करोड़ रुपए की भारी भरकम पूंजी से 120 लाख टन की उत्पादन क्षमता वाला कारखाना खोलने जा रही है. पोस्को जैसी विशालकाय कम्पनी के चलते कई छोटी-छोटी देशी कम्पनियों का दिवालिया निकलना तय है. 13 हजार लोगों को नौकरियां मिलने के नवीन का दावा सही है या झूठा, यह तो वही जाने पर इससे कहीं ज्यादा संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे और प्रदेश कई गुना लुट जाएगा, यह निश्चित है.

इस करार के चलते 40 हजार परिवारों का विस्थापन किया जाएगा. इनमें से अत्यधिक संख्या आदिवासियों की है. हजारों एकड़ जंगल बर्बाद हो जाएंगे. जंगल पर निर्भर कर जीने वाले आदिवासी तितर-बितर हो जाएंगे. उत्खनन वाले इलाके में कारखाने से निकलने वाले व्यर्थ पदार्थों से पर्यावरण के लिए गंभीर नुकसान होगा. पोस्को के लिए हीराकुड़ डैम से काफी मात्रा में पानी दिया जाना है. इससे उसकी बिजली उत्पादन की क्षमता मार खाएगी. खरीफ और रबी फसलों के लिए किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा जिससे किसानों को भारी नुकसान होगा.

पोस्को को कारखाने के निर्माण के लिए 4 हजार एकड़, अन्य जरूरतों के लिए 1500 एकड़, उत्खनन कार्य के लिए 500 एकड़ जमीन दी जाएगी. उस जमीन में बसे हुए लोगों को भगा दिया जाएगा. वाजिब मुआवजा, पुनर्वास के लिए माकूल जमीन के लिए जनता आन्दोलित होती है तो सरकार लाठियां और गोलियां खिलाने के लिए तैयार है. हमारे देश में विदशी लुटेरी कम्पनियों के साथ अब तक हुए करारों में यह सबसे बड़ा है. यहां से पोस्को 30 प्रतिशत कच्चामाल ब्राजील को निर्यात कर वहां भी इस्पात का उत्पादन करने वाली है.

केन्द्र सरकार की पंचवर्षीय योजना के तहत इस्पात उत्पादन की योजना के लिए 110 मिलियन टन लौह अयस्क की जरूरत है. एक टन इस्पात तैयार करने के लिए 1.6 टन लौह अयस्क की जरूरत होती है. हरेक इस्पात कारखाना 40 साल की उत्पादन योजना से बनाया जाता है. टाटा की स्टील कम्पनी टिस्को 100 साल से ज्यादा तथा राउरकेला 45 साल से ज्यादा उत्पादन करेंगी. पोस्को को मिलाकर इस वर्ष कुल 37 स्टील कम्पनियों के साथ करार किए गए हैं. 37 स्टील कम्पनियां 1,18,000 करोड़ रुपए की पूंजी लगाकर 477 लाख टन उत्पादन क्षमता वाले इस्पात कारखाने लगाने जा रही हैं.

26 अक्टूबर 2005 को और 3 कम्पनियों के साथ करार किए गए. कुल 40 कम्पनियों के लिए 560 लाख टन लौह अयस्क की जरूरत है. 40 साल तक सभी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को कच्चा लौह अयस्क 56 X 1.6 X 40 = 438 करोड़ टन की जरूरत होगी. उड़ीसा प्रदेश में करीब 417.7 करोड़ टन के भण्डार हैं. साफ जाहिर है, 40 साल बाद यहां कुछ भी लोहा नहीं बचेगा. 45 सालों में राउरकेला संयंत्र द्वारा 18 लाख टन और 3 स्पंज आयरन कारखानों द्वारा 70 लाख टन पिग आयरन का उत्पादन कर सकेंगे, जबकि यह पूरी मात्रा पोस्को द्वारा एक साल में किए जाने वाले उत्पादन के बराबर नहीं हो सकती. दरअसल वर्तमान में इस्पात

(शेष पेज 10 में....)

कलिंगनगर हत्याकाण्ड – बड़े व विदेशी पूंजीपतियों के हित में और आदिवासियों के खिलाफ उड़ीसा सरकार की जघन्य कार्यवाही

टाटा जैसै बड़े पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए आदिवासियों को उजाड़ने और उनका सफाया करने पर तुली लुटेरी सरकारों के खिलाफ संघर्ष तेज करो !!

2 जनवरी 2006 को उड़ीसा के जाजपुर जिले के कलिंगनगर कस्बे में भारत के बड़े पूंजीपतियों में से एक टाटा की टिस्को कम्पनी के हित में उड़ीसा सरकार ने अपनी पुलिस के जरिए आदिवासियों के खिलाफ एक बर्बर व पाशविक हत्याकाण्ड को अंजाम दिया. टाटा द्वारा प्रस्तावित इस्पात संयंत्र के निर्माण का वहां की आदिवासी जनता इसलिए विरोध कर रही है क्योंकि उन्हें वादे के मुताबिक वाजिब मुआवजा नहीं दिया गया, न ही उन्हें नौकरी दी गई. इस मांग से विरोध प्रदर्शन कर रहे आदिवासियों पर पुलिस बलों ने सोची–समझी साजिश के तहत बर्बरतापूर्ण तरीके से गोलियां बरसाईं और करीब 17 आदिवासियों की जघन्य हत्या की और दर्जनों को घायल किया. खबर है कि मारे गए लोगों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती है क्योंकि आदिवासी अपने कई भाई–बन्धुओं की लाशें अपने साथ उठा ले गए थे. आदिवासियों ने आत्मरक्षा की खातिर पुलिस के इस बर्बर हमले का जवाब अपने परम्परागत तीर–धनुषों से दिया जिसमें एक पुलिस जवान मारा गया और कई अन्य घायल हो गए. दरअसल 3–4 महीने पहले भी वहां की आदिवासी जनता ने इसी तरह का विरोध प्रदर्शन किया था. तब भी उनकी मांग यही थी. और तब भी पुलिस ने इसी तरह पाशविकता का नंगा प्रदर्शन करते हुए लाठीचार्ज किया और कई आदिवासियों को गिरफ्तार भी किया था. वर्तमान हत्याकाण्ड के बाद आदिवासियों ने इस संयंत्र के निर्माण का सिरे से विरोध करते हुए अपने आन्दोलन को तेज किया. मारे गए अपने साथियों की लाशें सड़क पर रखकर हजारों आदिवासी इकट्ठे हुए थे और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को वहां आने की मांग की थी. लेकिन आदिवासियों के खून के प्यासे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने न तो इसके लिए माफी मांगी, न ही वहां जाकर जनता से पूछ–परछ की.

कलिंगनगर हत्याकाण्ड के विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन

दरअसल बड़े पूंजीपतियों और विदेशी कम्पनियों के मुनाफों के लिए आदिवासियों को उजाड़ने या मार डालने की यह कहानी नई नहीं है. तथाकथित आजादी के बाद से अब तक बड़ी परियोजनाओं के नाम से देश भर में करीब एक करोड़ आदिवासियों को विस्थापित किया जा चुका है. और उनमें से बहुत कम लोगों को दोबारा बसाया गया. 'विकास' के नाम पर जारी इस विनाशलीला में सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है आदिवासियों को. उनके जल–जंगल–जमीन के साथ–साथ उनकी संस्कृति को भी तबाह किया जा रहा है. कलिंगनगर काण्ड इसी दुष्चक्र की एक कड़ी है.

छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी विभिन्न परियोजनाओं के नाम पर अभी तक हजारों आदिवासियों को विस्थापित किया जा चुका है. 2002 में नगरनार में एनएमडीसी द्वारा प्रस्तावित स्टील प्लान्ट के बहाने सैकड़ों लोगों को विस्थापित किया गया था. उन्हें भी मुआवजा व नौकरी देने का वादा तो किया गया था पर अमल कुछ नहीं हुआ. उनके खिलाफ पुलिस ने लाठी और गोली का प्रयोग कर दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया था. अभी–अभी रमन सिंह सरकार ने टाटा और एस्सार कम्पनियों के साथ समझौता करके बस्तर के आदिवासियों को बड़े पैमाने पर विस्थापित कर उनके जल, जंगल और जमीन को हड़पने की साजिशें तेज कीं. लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के बेलर के आसपास की जनता ने विरोध का रास्ता अपनाया हुआ है. लेकिन टाटा जैसे बड़े पूंजीपतियों से मोटी रकम दलाली के तौर पर लेने वाले महेन्द्र कर्मा, बलिराम कश्यप, केदार कश्यप जैसे दलाल जनता को बहला–फुसलाकर दबाने की कोशिश कर रहे हैं. दलाल रमन सिंह की सरकार ने टाटा से जो एमओयू किया उसे उजागर करने से इनकार कर यह स्पष्ट किया कि दरअसल इसके पीछे आदिवासियों को बड़े पैमाने पर उजाड़ने की बहुत बड़ी साजिश है. एस्सार पाइप लाइन के जरिए बस्तर की जल सम्पदा को जबर्दस्त नुकसान होने वाली है. इसके खिलाफ आन्दोलनरत जनता को भी दलाल नेता दबा रहे हैं.

दूसरी तरफ पश्चिम बस्तर इलाके में चल रहा तथाकथित 'जन जागरण' अभियान या 'सलवा जुडूम' को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए. इसे जनता का सस्फूर्त आन्दोलन की संज्ञा देकर बाहरी दुनिया को वे भले ही दिग्भ्रमित कर सकते हों पर बस्तर की जनता को अच्छी तरह मालूम है कि आदिवासियों का विरोधी कौन हैं और हितैषी कौन. सरकार द्वारा संचालित इन छद्म अभियानों का एक प्रमुख लक्ष्य टाटा,

एस्सार, जिन्दल जैसे बड़े पूंजीपतियों व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बस्तर की जल, जंगल व जमीन को खुल्लमखुल्ला व बेरोकटोक लूटने की सुविधा मुहैया कराना है. इस राह में सबसे बड़ा रोड़ा है क्रान्तिकारी आन्दोलन, जिसका आधार है बस्तर का आदिवासी अवाम. इसीलिए वे 'सलवा जुडूम' के नाम पर मीडिया के जरिए झूठी खबरें फैलाकर तथा नक्सलवादी या माओवादी आन्दोलन के खिलाफ दुष्प्रचार मुहिम छेड़कर आदिवासियों का सफाया कर रहे हैं. इस हमले के दौरान जून 2005 से लेकर अब तक पुलिस, अर्ध सैनिक बलों और सलवा जुडूम गुण्डावाहिनी ने 150 से ज्यादा लोगों की हत्या की, जिसमें महिलाओं की संख्या एक दर्जन से ज्यादा है. दर्जनों को गोलियों से घायल किया. दर्जनों महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया और इनमें से कुछ की हत्या भी की. और कई ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में अभी तक कोई अता-पता नहीं है. कइयों को तथाकथित राहत शिवरों में मार डाला गया और लाशें इंद्रावती नदी में बहा दी गई हैं. अभी तक 100 से ज्यादा गांवों के 2,000 से ज्यादा घरों को जला कर तबाह कर दिया गया है. एक अनुमान के मुताबिक 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की सम्पत्ति तहस-नहस कर दी गई है.

कलिंगनगर हत्याकाण्ड के विरोध में आदिवासियों का प्रदर्शन

बस्तर में जून 2005 से 'सलवा जुडूम' के नाम पर जो भी हो रहा है और अभी 2 जनवरी 2006 को उड़ीसा के कलिंगनगर में टाटा के हित में सरकार ने जो कुछ भी किया है – इन दोनों में एक समानता है. खासकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड आदिवासी बहुल राज्य हैं जहां खनिज सम्पदा के समृद्ध भण्डार निक्षिप्त हैं. इन पर बड़े दलाल पूंजीपतियों और विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की निगाहें जमी हुई हैं. सच्चाई यह भी है कि इन तीनों राज्यों के बहुतेरे हिस्सों में आदिवासी भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व में संगठित हो चुके हैं या हो रहे हैं. वे सामन्तवाद, दलाल पूंजीवाद और साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंककर असली लोकतंत्र की स्थापना करने के लक्ष्य से लड़ रहे हैं. इलाकावार राजसत्ता हासिल करने के रास्ते पर चलते हुए आदिवासी गांव स्तर पर अपनी नई जनतांत्रिक राजसत्ता के संगठनों का निर्माण कर रहे हैं. इससे बौखलाए हुए लुटेरे शासक वर्ग आदिवासियों की हत्या करवा रहे हैं. चाहे उड़ीसा के कलिंगनगर हो या फिर छत्तीसगढ़ के बस्तर, सरगुजा या झारखण्ड ही क्यों न हो, आज आदिवासियों के सामने एक ही रास्ता है – अपने जल, जंगल व जमीन के साथ-साथ अपनी संस्कृति व आत्मसम्मान को बचाना है तो उन्हें भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व में जारी जनयुद्ध में शामिल होना चाहिए. जनयुद्ध के जरिए ही वे दलाल व विदेशी पूंजीपतियों व साम्राज्यवादियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर सकते हैं.

देश की लुटेरी सरकारें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के मुनाफे के लिए मजदूरों और किसानों पर आए दिन हमले कर रही हैं. जहां खनिज सम्पदा के भण्डार हैं वहां के आदिवासियों को खासतौर पर निशाना बनाया जा रहा है. देश के तमाम देशभक्तों को चाहिए कि वे लुटेरी सरकारों की जन विरोधी, मजदूर विरोधी व आदिवासी विरोधी कार्रवाइयों के खिलाफ उठ खड़े हो जाएं. ✶

(..... पेज 7 का शेष)

मवेशियों और लोगों को हांकते हुए ला रहे थे. इसके अलावा लोगों को हथियार पकड़ने को प्रेरित किया जा रहा है. ग्राम सुरक्षा कमेटियों का निर्माण किया जा रहा है. समूचा समाज ही सैन्यीकृत होता जा रहा है.

9. हालांकि छत्तीसगढ़ को एक कबीलाई राज्य कहा जाता है, पर यहां आदिवासी समाज और संस्कृति को बुरी तरह छिन्न-भिन्न किया जा रहा है. लोगों को उनकी पवित्र समझी जाने वाली मिट्टी से जबरन दूर किया जा रहा है. समूचा सामाजिक ताना-बाना ही तहस-नहस किया जा रहा है.

हम मांग करते हैं कि –

1. बस्तर/दन्तेवाड़ा में समाज को सैन्यीकृत कर नक्सल विरोधी ऑपरेशन के तहत आदिवासियों को एक-दूसरे के खिलाफ लड़ाना तथा जनता का ढाल की तरह इस्तेमाल करना बन्द करो.
2. सलवा जुडूम/सुरक्षा बलों द्वारा संयुक्त रूप से की गई तमाम हत्याओं, जिन्हें रिकॉर्ड नहीं किया गया है, पर एक न्यायिक जांच बिठाई जाए.
3. भाकपा (माओवादी) उन तमाम लोगों के ब्यौरे पेश करे जिनकी उन्होंने हत्या की है. ✶

(..... पेज 8 का शेष)

का उत्पादन देश की जरूरतों की बजाए बड़ी कम्पनियों के मुनाफे के लिए हो रहा है. उड़ीसा की प्राकृतिक सम्पदाओं को इजारेदार कम्पनियों के हवाले करने का मतलब साम्राज्यवादी लूट के लिए उड़ीसा प्रदेश के दरवाजे खोलना है. भविष्य में हमें अपनी जरूरतों के लिए विदेशों से आयात पर निर्भर करना पड़ेगा. असीम प्राकृतिक सम्पदाओं से समृद्ध उड़ीसा साम्राज्यवादी इजारेदार कम्पनियों की लूटखसोट के चलते बेहद गरीबी, अकाल आदि समस्याओं से जूझ रहा है. विकास के मामले में यह राज्य देश में 19वें स्थान पर है.

जापान जैसे साम्राज्यवादी देश बेहद सस्ते में कच्चा लौह अयस्क का आयात कर मशीनों और मशीनों के पुरजों का उत्पादन कर बेहद ऊंचे दामों पर गरीब देशों को बेचकर मोटी रकम कमा रहे हैं. उड़ीसा प्रदेश गरीबी से तभी मुक्त होगा जब वहां की जनता अपनी प्राकृतिक सम्पदाओं पर अपना अधिकार कायम कर लेती. जब तक उड़ीसा साम्राज्यवादियों के शिकंजे से बाहर नहीं आएगा तब तक उसका चौमुखी विकास सम्भव नहीं होगा. दलाल नवीन पटनायक के लुटेरे शासन के खिलाफ संघर्ष कर उड़ीसा की जनता को एक मिसाल कायम करनी चाहिए. ✶

हजारों लोगों को उजाड़ने और तबाह करने वाले टाटा इस्पात संयंत्र (बेलर–लोहंडीगुडा) का विरोध करो !

'विकास' के नाम पर जनता के 'विनाश' पर तुली सरकार की ढोंगी नीतियों का विरोध करो!!

जैसा कि सभी जानते हैं कि भारत के बड़े पूंजीपति टाटा की कम्पनी टिस्को बस्तर में करीब 10 हजार करोड़ रुपए की लागत से भारी–भरकम इस्पात संयंत्र खोलने की तैयारियां कर रही है. लोहंडीगुड़ा ब्लॉक के बेलर में प्रस्तावित इस इस्पात संयंत्र के स्वागत में जहां रायपुर में बैठे सत्ताधारियों से लेकर जगदलपुर–दन्तेवाड़ा में मौजूद दलाल राजनेता, लालची व्यापारी, भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारी तक अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, वहीं बेलर, कुम्हली, दाबपाल और उनके आसपास के गांवों की जनता अपनी आसन्न तबाही और बर्बादी को लेकर बेहद चिन्तित है. बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों का पक्षधर मीडिया (अखबार, रेडियो, टीवी आदि) हमेशा की तरह इस प्लान्ट से भी ''बस्तरियों की तकदीर बदलने'' के खोखले दावों के साथ झूठा प्रचार कर रहा है. टाटा से दलाली खा चुके नेता, सेठ और अफसर 'नागरिक समिति' के नाम से जनता को छलने के लिए झूठे वायदों का अंबार लगा रहे हैं. बस्तर के अव्वल नम्बर दलाल महेन्द्र कर्मा, बलिराम कश्यप आदि नेता जनता को दिग्भ्रमित करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं. वहीं कुछ भाजपाई व कांग्रेसी नेता दबे सुर में इस संयंत्र का विरोध करने का दिखावा कर रहे हैं जिनकी ईमानदारी बेहद संदेहास्पद है. ये टाटा से मोटी रकम दलाली के बतौर हासिल करने के बाद अपनी जुबान बदल सकते हैं, बस्तरिया जनता को इस प्रकार का काफी कड़वा अनुभव रहा है.

लोगों को याद होगा, करीब 4 साल पहले नगरनार स्टील प्लान्ट को लेकर भी ठीक इसी प्रकार का माहौल बनाया गया था. बस्तर में विकास की गंगा बहाने के बयान दिए गए थे. जब स्थानीय जनता ने विस्थापन से बचने के लिए उसका विरोध किया था तो उन्हें लाठी और गोली के दम पर दबाया गया था. सैकड़ों लोगों को जेल में ठूंसा गया था और बुरी तरह मारा–पीटा भी गया था. सैकड़ों लोग अपनी पुरखों की जमीन से हाथ धोकर आज भी दर–दर भटक रहे हैं. अब वहां न तो कोई प्लान्ट लगा है, न ही किसी को रोजगार मिला है, जैसा कि नेताओं और अधिकारियों ने आश्वासन दिया था. उस वक्त भी बलिराम कश्यप, महेन्द्र कर्मा इसी प्रकार बिचौलियों की तरह काम किया था. विरोध करने वाले लोगों को दौड़ा–दौड़ाकर पीटने के जघन्य काण्ड का बलिराम कश्यप ने खुद नेतृत्व किया था. 'ग्राम स्वराज' की धज्जियां उड़ाकर 'ग्राम सभा' के फैसलों को नेस्तनाबूद किया था. यही सब अब बेलर में दोहराने की फिराक में हैं ये सारे ढोंगी आदिवासी नेता.

दरअसल इस संयंत्र से स्थानीय जनता को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उन्हें अपनी पुरखों की जमीन, खेति–बाड़ी और अपनी जीविका के तमाम साधनों से वंचित होना पड़ेगा. उन्हें नौकरी देने की बात की जा रही है, पर सच्चाई यह है कि उन्हें सिर्फ ''मजदूर'' या ''कुली'' बनाया जाएगा. बेलर की एक महिला के शब्दों में कहें तो ''जमीन रहने से दो पायली धान से भी जी सकते हैं, पर जमीन छिन जाने से हमारी जिन्दगी ही आफत में फंस जाएगी.'' इसके पहले बैलाड़ीला और नगरनार परियोजनाओं से भी स्थानीय लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ था. बैलाड़ीला खदानों में स्थानीय आदिवासियों को कुली, वाचमैन, खलासी, दिहाड़ी मजदूर के अलावा कोई दूसरा काम नहीं मिला. वहां की आदिवासी महिलाएं बाबू लोगों के घरों में बरतन मांजकर या नौकरानी व रखैल बनकर जीवन बिता रही हैं. आदिवासी पुरुष लकड़ी बेचकर जी रहे हैं या शराब बेचने को मजबूर हैं. क्या इसी को ''विकास'' कहेंगे?

राष्ट्रीय सलाह मण्डल (एनएसी) ने एक रिपोर्ट में कहा है कि पिछले 50 सालों में विकास परियोजनाओं के नाम पर देश भर में 90 लाख से ज्यादा आदिवासियों को विस्थापित किया जा चुका है. राउरकेला, बोकारो, नर्मदा घाटी, कलिंगनगर, आदि कितने ही उदाहरण गिने जा सकते हैं. उनमें से बहुत कम लोगों को दोबारा बसाया गया है, बाकी लाखों लोग शहरों व कस्बों में रिक्षा चलाकर या लकड़ी बेचकर या भवन निर्माण में मजदूरी करके या भीख मांगते हुए जीने को मजबूर हैं. आदिवासी महिलाएं दिन–ब–दिन बड़े पैमाने पर वेश्यावृत्ति में धकेल दी जा रही हैं. बेलर में भी यही कहानी दोहराई जाएगी, इसकी पूरी सम्भावनाएं हैं.

भारत का बड़ा पूंजीपति टाटा यहां सस्ते में उपलब्ध बेशकीमती लोहे का इस्तेमाल कर करोड़ों रुपए कमाने के चक्कर में है. यानी वह अपने स्वार्थ के लिए यहां कारखाना लगाना चाहता है. इसके बदले स्थानीय जनता की जिन्दगी को तबाह करने के लिए और यहां तक कि उनकी हत्या करने के लिए भी वह नहीं हिचकिचाएगा. हाल ही में उड़ीसा के कलिंगनगर में उसने पुलिस बलों को उकसाकर 17 आदिवासियों की निर्मम हत्या करवाई. यहां पर भी टाटा के तलवे चाटने वाले शासन–प्रशासन और दलाल राजनेता पहले झूठे आश्वासनों या प्रलोभनों से जनता को 'समझाइश' देने की कोशिश करेंगे और फिर जनता नहीं सुनती है तो बाद में घोर दमन करने से भी नहीं चूकेंगे.

खनिज सम्पदाओं से सम्पन्न छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखण्ड राज्यों में सरकारें बड़े पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के मुनाफों के लिए स्थानीय जनता का तीव्र दमन कर ही रही हैं. 'सलवा जुडूम', 'सेन्दरा', 'जन जागरण' अभियान आदि सभी जुल्मी अभियानों का लक्ष्य एक ही है – स्थानीय जनता का सफाया करना और बड़े व विदेशी पूंजीपतियों की लूटखसोट के लिए रास्ता साफ करना. एक

तरफ छोटे व मध्यम दर्जे के इस्पात व लोहा कारखानों में आए दिन ताले लग रहे हैं. उन्हें सरकारें कच्चामाल और बिजली की आपूर्ति ठीक से नहीं करवा रही हैं. वहीं बड़े पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए लाल कालीन बिछा रही हैं. सरकार 25 पैसा प्रति किलो के नाम मात्र के दाम से जापानी साम्राज्यवादियों को बैलाड़ीला का बेशकीमता लोहा बेच रही है. दूसरी तरफ देशीय छोटे पूंजीपतियों को बेहद महंगे दाम पर बेच रही हैं. इससे साफ जाहिर हो जाता है कि सरकार बड़े व विदेशी पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए प्रतिबद्ध है न कि देशीय व छोटे उद्योगपतियों के हितों के प्रति.

हाल ही में बेलर में टाटा संयंत्र को लेकर जब छत्तीसगढ़ विधानसभा में जब चर्चा छिड़ी थी तो रमन सरकार ने टाटा के साथ हुए एमओयू को सार्वजनिक करने से साफ इनकार किया. इसके बावजूद उसने दावा किया कि इससे बस्तरिहों की भलाई होगी और लोगों का ठीक-ठाक पुनर्वास किया जाएगा. खुद को 'लोकतांत्रिक' तरीके से चुनी हुई बताने वाली सरकार की देशद्रोहपूर्ण व जन विरोधी चरित्र को समझने के लिए इससे बढ़कर क्या उदाहरण चाहिए?! सरकार इस करार को जनता के सामने रखने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी वह जनता से इससे होने वाले फायदों पर विश्वास करने की उम्मीद रखती है!! हमारे तथाकथित 'विपक्षी' नेता इस पर जरा भी आपत्ति नहीं करते हैं. सरकार के इस अड़ियल रवैये से छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि इस करार (एमओयू) में बस्तर की जनता को बड़े पैमाने पर विस्थापित करने और विस्थापित जनता के समुचित पुनर्वास की बाध्यता से टाटा को मुक्त रखने के प्रावधान जरूर होंगे, तभी तो वह इस तरह एमओयू को सार्वजनिक करने से इनकार कर रही है.

इससे बस्तर के चौमुखी विकास होने के खयाली पुलाव पकाने वालों को सबसे पहले समझना चाहिए कि आखिर 'विकास' का मतलब क्या है. बस्तर एक आदिवासी बहुल इलाका है, जहां की अत्यधिक आबादी दूर-दराज के छोटे-छोटे गांवों में रहकर मुख्य रूप से खेतीबाड़ी करके जीवन चलाती है. इसके अलावा वनपजों पर भी यहां की अत्यधिक आदिवासी जनता काफी हद तक निर्भर करती है. ऐसे में 'बस्तर विकास' का मतलब 'बस्तर के किसानों का विकास' ही होना चाहिए. लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि 58 सालों की तथाकथित आजादी के बाद भी बस्तर में ले-देकर 2 प्रतिशत जमीन को ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो पाई है. सरकार की तमाम सिंचाई परियोजनाएं कागजों में ही सिमटकर रह गई हैं. बस्तर में शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं में बदहाली का आलम यह है कि यह विश्व रिकॉर्ड भी कायम कर ले तो आश्चर्य नहीं होगा. आदिवासी आए दिन बीमारियों से बेमौत मरते हैं. इन बुनियादी बातों पर कोई ध्यान न देने वाले शासक टाटा, एस्सार, जिन्दल जैसे बड़े पूंजीपतियों की जूठन खाने के लिए हजारों आदिवासियों को तबाही की गर्त में धकेलने पर उतारू हैं.

ऐसा नहीं है कि बस्तर में कोई उद्योग लगना ही नहीं चाहिए. लेकिन स्थानीय जनता की जीवन शैली व संस्कृति को तहस-नहस करने की कीमत पर कतई नहीं चाहिए. उनके पेट पर लात मारकर भगा देने वाला औद्योगिक विकास नहीं चाहिए. औद्योगीकरण का लक्ष्य यहां उपलब्ध मानव संसाधनों का सुचारू रूप से इस्तेमाल करते हुए, स्थानीय आदिवासी जन समुदायों और उनके जल, जंगल व जमीन को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला होना चाहिए. ऐसा औद्योगिक विकास होना चाहिए जिससे कि यहां पर कृषि विकास को बढ़ावा मिले. यहां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध वनोपजों का सही ढंग से इस्तेमाल हो. मशीनीकृत या उच्च तकनीक वाले उद्योग नहीं चाहिए, बल्कि यहां के अनपढ़ या कम पढ़े-लिखे नौजवानों को भी बड़ी संख्या में रोजगार मिल सके, ऐसे छोटे व कम तकनीक वाले उद्योग चाहिए. औद्योगिक विकास से कृषि विकास को बल मिलना चाहिए. चूंकि किसानों की क्रयशक्ति बढ़ने से ही उद्योगिक विकास को गति मिल सकती है, इसलिए कृषि क्षेत्र में व्यापक भूमि सुधारों की नितांत आवश्यकता है. सबसे अव्वल तो यहां की सम्पदाओं को बड़े व विदेशी पूंजीपतियों को लूटकर ले जाने की इजाजत कतई नहीं देनी चाहिए. विदेशी पूंजीपतियों (साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों) के साथ सम्बन्ध न रखते हुए, स्थानीय जनता के जीवन व पर्यावरण को कोई खास नुकसान न करते हुए अगर कोई भी देशी पूंजीपति दण्डकारण्य में कारखाना खोलना चाहेगा उसका स्वागत किया जाएगा.

कुछ लोग यह तर्क देकर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के मुनाफे के एवज में जनता को उजाड़ने की साजिशों को जायज ठहरा रहे हैं कि कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ता है. लेकिन 'आजाद' भारत के 58 सालों के इतिहास पर नजर डाले तो यह सच्चाई साफ समझी जा सकती है कि हमेशा पाने वाले बड़े व विदेशी पूंजीपति ही होते हैं और खोने वाले आदिवासी और अन्य गरीब तबके ही होते हैं. अगर जनता को सचमुच ही फायदा होगा तो वह उसके बदले कुछ खोने के लिए भी खुद-ब-खुद तैयार होती है, बशर्तेकि फायदा व्यापक और ज्यादा होना चाहिए और नुकसान कम. लेकिन बस्तर में ही नहीं, पूरे भारत में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ. हर जगह नुकसान बेहद ज्यादा और फायदा न के बराबर. खासतौर पर बड़े उद्योगों और बड़ी परियोजनाओं का हर जगह यही अनुभव रहा.

इसीलिए बस्तर की जनता बड़े उद्योगों और बड़ी परियोजनाओं का विरोध कर रही है. उन्हें विनाश की ओर ले जाने वाली खदानों, रेल लाइनों व सड़कों का वे एक सुर में विरोध कर रहे हैं जिन्हें सरकार 'विकास' योजनाओं के रूप में चित्रित करती है. देश में जब तक साम्राज्यवादियों की जूतियां चाटने वाली सरकारें रहेंगी तब तक जनता के वास्तविक 'विकास' की उम्मीद ही हम नहीं कर सकते हैं. अगर हमें सही विकास चाहिए तो सबसे पहले बड़े जमींदारों व बड़े पूंजीपतियों की शोषणकारी राज्यव्यवस्था को उखाड़कर फेंक देना होगा जिसे कि साम्राज्यवादियों का समर्थन हासिल है. और मजदूर-किसान एकता के आधार पर तमाम शोषित तबकों की नव जनवादी राज्यव्यवस्था का निर्माण करना होगा, जोकि आज दण्डकारण्य में ग्राम स्तर पर शुरू हो चुका है. आइए, हम सब बस्तरिहा जनता मिलकर टाटा के प्रस्तावित कारखाने का विरोध करेंगे. जनता के सच्चे और बुनियादी विकास को हम खुद लड़कर हासिल करेंगे. ★

श्रद्धांजली

वीर शहीद कॉमरेड रामदास अमर रहें !

कॉमरेड रामदास (21) का जन्म बस्तर जिला, तहसील नारायणपुर, पंचायत कच्चापाल के ग्राम इरकभट्टी में 1985 में हुआ था. बहुत ही गरीब आदिवासी किसान घर में जन्मे कॉ. रामदास का नाम उनके माता-पिता ने बड़े प्यार से बुधराम रखा था. बुधराम बचपन से ही बड़ा नटखट और जिद्दी स्वभाव का लड़का हुआ करता था. बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु होने के कारण घर की स्थिति और खराब हो गई थी. कॉमरेड बुधराम को गांव की आश्रमशाला में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने चौथीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी की थी. बाद में पढ़ाई छोड़कर उन्होंने मां-बहनों के साथ घर के काम में हाथ बंटाना शुरू किया. वे कुल 5 भाई-बहन थे जिनमें चौथा नम्बर कॉमरेड बुधराम का था. जवान होते ही उनका विवाह हो गया और उनके दो बच्चे भी हो गए.

कॉमरेड रामदास

गांव में रहकर उन्होंने डीएकेएमएस की सदस्यता ली थी. संगठन के कामकाज में उनकी सक्रियता और प्रतिबद्धता को देखकर उन्हें कमेटी सदस्य चुन लिया गया था. गांव के पटेल, सरपंच आदि परम्परागत मुखियागण ने जब जन संगठनों के खिलाफ माहौल बनाया था, तब वह कॉमरेड बुधराम ही थे जिन्होंने इसकी पूरी तहकीकात कर संगठन अध्यक्ष को रिपोर्ट सौम्प दी. बाद में संगठन के नेतृत्व ने समस्या को जनता के सामने रखकर हल कर दिया. जनवरी 2003 में कॉमरेड बुधराम सरकार के शोषणकारी चरित्र तथा उसकी दमनकारी नीतियों को अच्छी तरह समझकर पीएलजीए का सैनिक बन निकला. पीएलजीए दस्ते में शामिल होने के बाद उन्होंने अपना नाम 'रामदास' बदला. उनकी बहादुरी और मेहनती स्वभाव से प्रभावित होकर पार्टी ने उन्हें पलटन-1 में भेजा. बहुत जल्द ही उन्होंने साथी सदस्यों का विश्वास हासिल किया. बचपन का उनका जिद्दी स्वभाव वर्ग दुश्मनों के प्रति सख्त नफरत में तब्दील हो गया. घर के कामकाज में हाथ बंटाते हुए उन्होंने जिस प्रतिबद्धता से अपनी जिम्मेदारी निभाई थी, उतनी ही प्रतिबद्धता और लगन के साथ जनता की सेवा करना शुरू किया. पार्टी व पीएलजीए का अनुशासन पालन करने में वह कोई कोताही नहीं करते थे. कुछ ही महीनों में कुत्तुल, कोहकामेट्टा, कुंदला, सोनपुर आदि क्षेत्रों में वह शोषित आदिवासियों का चहेता बन गए.

माड़ डिवीजन में 2006 जनवरी से सरकार ने 'सलवा जुडूम' शुरू करने के प्रयास शुरू किए. इस जुल्मी अभियान को नाकाम करने के लिए माड़ डिवीजन की जनता, जन संगठन, जन मिलिशिया, पीएलजीए दस्ते, पार्टी और जनताना सरकार की तमाम इकाइयों ने कमर कस ली. जन विरोधियों व पुलिस के दलालों के नापाक मंसूबों पर पानी फेरते हुए माओवादी जनयुद्ध का परचम माड़ की पहाड़ियों पर और बुलन्द कर रखा है. ऐसे माहौल में 1 फरवरी 2006 को जब गोला बारूद की जांच-परख चल रही थी, तब दुर्भाग्य से लोहे का एक टुकड़ा छिटककर लगने से कॉमरेड रामदास को शहादत हासिल हुई. इस तरह माड़ की आदिवासी जनता ने अपना लाड़ला बेटा खोया. पीएलजीए ने एक होनहार और अदम्य साहसी सैनिक गंवाया. यह खबर सुनते ही कुतुल, कोहकामेट्टा, परालकोट आदि इलाकों में जनता, जन मुक्ति गुरिल्ला सेना के कतार, जन संगठन और जनताना सरकार की इकाइयां शोक में डूब गए. भाकपा (माओवादी) की डिवीजनल कमेटी ने उन्हें श्रद्धांजली पेश करते हुए उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की. आइए, इस बहादुर और जन योद्धा की शहादत को सम्मान पेश करें.

कॉमरेड भीमाल
(माड़िवी देवा)
मलिंगेर एलजीएस कमाण्डर
दक्षिण बस्तर डिवीजन

कॉमरेड नंदाल
(सोड़ी हिड़मा)
एक्शन टीम सदस्य
दक्षिण बस्तर डिवीजन

कॉमरेड कोवाल
जनताना सरकार अध्यक्ष
गांव मनकेली
पश्चिम बस्तर डिवीजन

कॉमरेड कुरसम लक्के
केएएमएस कार्यकर्ता
गांव पेद्दा कोरमा
पश्चिम बस्तर डिवीजन

(इन सभी कॉमरेडों की जीवनियों पर रिपोर्टें 'प्रभात' के पिछले अंक (जुलाई-दिसम्बर 2005) में छपी थीं. - सम्पादक)

जन नेता कॉमरेड बिचंगा को लाल सलाम !

दक्षिण गड़चिरोली के अहेरी तहसील के देशीलपेट रेंज, बिडारघाट गांव में करीब 45 साल पहले एक गरीब आदिवासी परिवार में कॉमरेड वेलादी बिचंगा का जन्म हुआ था. वह 1981 में पार्टी के सम्पर्क में आए थे. तब से गुरिल्ला दस्तों को खाना खिलाते हुए धीरे-धीरे पार्टी की क्रान्तिकारी राजनीति से प्रभावित हो गए. 1982 में उस गांव में डीएकेएमएस की स्थापना हुई. संगठन के नेतृत्व में लोगों ने जंगल काटकर जमीन काश्त की. इसके बाद वन विभाग वालों ने वासलनार दरोगा के नेतृत्व में गांव पर हमला कर लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए थे. दमन की परवाह न करते हुए गांव के लोगों ने करीब 20 साल तक धैर्य के साथ कोर्ट-कचहरियों का चक्कर काटा. करीब 25 सालों से जारी सरकारी दमन और क्रान्तिकारी आन्दोलन में आए कई उतार-चढ़ावों के बावजूद कॉमरेड बिचंगा क्रान्तिकारी राजनीति के पक्ष में दृढ़तापूर्वक डटे रहे. वन विभाग वालों के खिलाफ लड़ी गई लम्बी लड़ाई के बाद आखिरकार लोगों ने जीत हासिल की, जमीन पर उन्हें हक मिल गया. इस संघर्ष का नेतृत्व कॉमरेड बिचंगा ने ही किया था. घर में बीवी-बच्चों को छोड़कर वह पार्टी के काम पर 10-10 दिनों तक बाहर रहते थे. उनकी पत्नी ने इस पर कभी कोई आपत्ति नहीं की. कॉमरेड बिचंगा के क्रान्तिकारी जीवन का उन्होंने भरपूर समर्थन किया.

देशलीपेटा रेंज के प्रथम डीएकेएमएस अधिवेशन में कॉ. बिचंगा को कार्यकारिणी में चुन लिया गया था. इस दौरान उन्हें तीन बार पुलिस ने गिरफ्तार कर यातनाएं दीं और झूठे मामलों में फंसाया था. 1991 में महाराष्ट्र सरकार ने क्रान्तिकारी आन्दोलन के खिलाफ भीषण दमन अभियान चलाया था. जन संगठन के कुछ नेताओं ने शत्रु दमन से डरकर दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण किया था. पर कॉमरेड बिचंगा ने पार्टी का साथ कभी नहीं छोड़ा. जनता को क्रान्तिकारी राजनीति समझाते हुए उनका ढाढ़स बंधाया था. 1991 में भूमिगत रहकर जनता को संगठित करते समय एक दलाल की सूचना पर कॉमरेड बिचंगा को पुलिस ने पिट्टेवाई गांव में गिरफ्तार किया था. एक महीने तक उन्हें क्रूर यातनाएं देकर बाद में टाडा अधिनियम के तहर नागपुर जेल भेज दिया था. 12 साल का लम्बा और कठोर जेल जीवन बिताकर वे 2003 में जमानत पर रिहा हो गए थे. जेल जाने के पहले उनके तीन छोटे-छोटे बच्चे थे जो उन्हें ठीक से पहचानते भी नहीं थे. उन्हें उतने साल इसलिए जेल में सड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें कोई जमानत देने वाले नहीं थे. रिहाई के बाद वे एक तरफ अदालतों का चक्कर काटते हुए ही पार्टी के सम्पर्क में रहे थे. 31 दिसम्बर 2005 को जब वह अपने खेत पर काम कर रहे थे तब पुलिस ने उन्हें फिर गिरफ्तार किया जोकि उनकी आखिरी गिरफ्तारी थी. 3 दिन बाद पुलिस ने दो अन्य संगठन सदस्यों के साथ कन्नेली के जंगलों में ले जाकर उनकी निर्मम हत्या की. अगले दिन मुठभेड़ की कहानी गढ़कर अखबारों में खबरें छपवाईं. यह कहकर झूठा प्रचार किया कि उनके पास रायफल, हथगोले और क्रान्तिकारी साहित्य पकड़ा गया, जोकि एक सफेद झूठ है. एसपी शिरीष जैन ने इनकी जघन्य हत्या सिर्फ इसलिए करवाई क्योंकि पुलिस के गिरते मनोबल को वह ऊपर उठाना चाहता था. लेकिन पुलिस की इस कायरतापूर्ण कार्रवाई का जिले की समूची जनता ने घोर निंदा की. सभी वर्गों की जनता ने पुलिस की झूठी मुठभेड़ों के खिलाफ आवाज उठाई.

जब दण्डकारण्य आन्दोलन अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है, ऐसे में करीब 25 सालों से अनेक मुश्किलें झेलकर भी क्रान्तिकारी आन्दोलन के साथ दृढ़तापूर्वक जुड़े रहने वाले कॉमरेड बिचंगा की शहादत हमारे लिए एक दुखद घटना है. अपने 25 सालों के लम्बे क्रान्तिकारी जीवन में दुश्मन के हाथों अनगिनत तकलीफों को सहकर भी अपनी आखिरी सांस तक माओवादी जनयुद्ध का परचम बुलन्द रखने वाले आदर्शवान कॉमरेड बिचंगा को समूचे दण्डकारण्य की शोषित जनता हमेशा याद रखेगी. 'प्रभात' कॉमरेड बिचंगा के शोक संतप्त परिवार जनों, रिश्तेदारों व दोस्तों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करती है.

कॉमरेड्स गीता और सुनीता के मृत शरीर

कॉमरेड्स गीता और सुनीता को लाल सलाम !

गड़चिरोली जिले के टिप्पागढ़ इलाके का गांव चारवाही की शुरू से ही क्रान्तिकारी परम्परा रही है. इसी गांव में कॉमरेड्स गीता और सुनीता का जन्म गरीब परिवारों में हुआ था. गीता 8वीं तक और सुनीता 5वीं तक पढ़ी थीं. गरीबी के कारण दोनों को भी आगे पढ़ने का मौका नहीं मिला. गड़चिरोली जिले में जारी क्रान्तिकारी आन्दोलन से प्रेरित होकर दोनों बाल संगठन में शामिल हुई थीं. बाद में उनकी सक्रियता और निर्भीकता को देखकर उन्हें जन सुरक्षा दस्ता में लिया गया. एक साल बाद गीता को पार्टी सदस्यता दी गई जबकि सुनीता को सिर्फ इसलिए नहीं दी गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी. हालांकि पार्टी की क्रान्तिकारी राजनीति के प्रति दोनों ही बराबर समर्पित थीं. पार्टी जो भी कार्यक्रम लेती और उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौम्पती तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के पूरा करती थीं. दमन के खिलाफ बन्द को सफल बनाना हो या शराबखोरी खिलाफ चलाए गए आन्दोलन हो, हरेक गतिविधि में उन्होंने सक्रियता के साथ भाग लिया. पिछले साल गर्मियों में अकाल की समस्या को लेकर जुलूस निकाले गए थे. उनमें इन दोनों युवा कार्यकर्ताओं ने पहलकदमी के साथ भाग लिया था. 28 जुलाई 2005 शहीद सप्ताह के दौरान उन्होंने प्रचार दलों में शामिल होकर गांव-गांव में शहीदों के आदर्शों के बारे में प्रचार किया. जब वे बन्दहूर गांव के पास स्थानीय सांगठनिक दस्ते (एलओएस) के साथ मिलने गई थीं, तभी मुखबिर की सूचना पर दस्ते पर पुलिस ने हमला कर फायरिंग की. इस फायरिंग में दस्ते के गुरिल्ला जवाबी फायरिंग करते हुए वहां से निकल गए. लेकिन कॉमरेड्स गीता और सुनीता को वहां से निकलने का मौका नहीं मिला तो पुलिस ने उन्हें

पकड़ लिया. उन्होंने शायद यह सोच लिया होगा कि चूंकि वे दस्ता के सदस्य तो नहीं हैं, इसलिए पुलिस उन्हें कुछ नहीं करेगी. लेकिन पिछले कुछ महीनों से पीएलजीए के हाथों एक के बाद एक लगातार लग रहे झटकों से बौखलाए कायर पुलिस बलों ने इन युवतियों के साथ सामूहिक बलात्कार कर दोनों की गोली मारकर हत्या की. बाद में उसने ''मुठभेड़ में दो महिला नक्सलियों के मारे जाने'' की खबरें फैला दीं. वास्तव में वे दोनों निहत्थी थीं और पुलिस ने उनकी निर्मम हत्या की. इस हत्या के खिलाफ गड़चिरोली जिले की जनता में गुस्से की लहर फैल गई. सभी ने पुलिस की इस दरिंदगी की घोर निंदा की. 'प्रभात' इन दोनों युवा कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजली देती है.

बीमारी के कारण शहीद हए कॉमरेड्स बुधनी, बुधराम, केये और सुनीला को लाल सलाम!

माड़ डिवीजन के क्रान्तिकारी आन्दोलन ने पिछले साल (2005) के जुलाई-सितम्बर महीनों में चार कार्यकर्ता खोए. बीमारी के चलते इन चारों कॉमरेडों की असमय मृत्यु हुई. वे चारों कॉमरेड अपने गांवों में रहकर जन संगठनों व जन मिलिशिया की गतिविधियों में भाग लिया करते थे. लुटेरी सरकार द्वारा दशकों से बरती जा रही लापरवाही के चलते इस इलाके में चिकित्सा सुविधाओं का पूर्ण अभाव है. इसी कारण हर साल सैकड़ों लोग यहां पर बेमौत मारे जाते हैं. अगर हर गांव में प्राथमिक चिकित्सा की मामूली सुविधाएं भी होतीं तो हर साल कई लोगों को बचाया जा सकता है. लेकिन इन मौतों से लुटेरी सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगती. इस स्थिति को देखकर हम यह महसूस कर सकते हैं कि इस क्षेत्र की जनता को क्रान्ति की कितनी ज्यादा जरूरत है. सिर्फ क्रान्तिकारी जन राजसत्ता ही जनता की इस दशा को बदल सकती है. बहरहाल, आइए, इन चारों कॉमरेडों की जीवनी पर सरसरी नजर डाली जाएं.

कॉमरेड बुधनी का जन्म माड़ डिवीजन के कुत्तुल इलाका इरकभट्टी गांव के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था. 1987 में वह इस गांव में गठित केएएमएस में शामिल हुई थीं. कॉमरेड बुधनी ने अपने गांव की महिलाओं को संगठन में गोलबन्द किया ही, आसपास के अन्य गांवों की महिलाओं को भी उन्होंने संगठित किया. पितृसत्तात्मक दमन के शिकार महिलाओं को एकजुट कर उनकी समस्याओं को हल करने में उन्होंने काफी प्रयास किया. सितम्बर 2005 में कॉमरेड बुधनी अचानक बीमार पड़ गईं और समुचित इलाज न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई. आसपास के गांवों के डीएकेएमएस और केएएमएस कार्यकर्ताओं ने एक शोकसभा का आयोजन कर कॉमरेड बुधनी को श्रद्धांजली पेश की. पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया.

कॉमरेड बुधराम भी इरकभट्टी गांव के निवासी थे. वह डीएकेएमएस के सक्रिय सदस्य थे. पिछले 3 सालों से वह तपेदिक से जूझ रहे थे. दुश्मन द्वारा जारी भीषण दमन के चलते उन्हें इलाज करवाने का मौका ही नहीं मिला. इसी कारण से पिछले जुलाई 2005 में उनकी मृत्यु हुई. गांव की जनता और जन संगठन कार्यकर्ताओं ने पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया और क्रान्तिकारी आन्दोलन में उनके योगदान को याद किया.

कॉमरेड केये परालकोट इलाके के गुडरापारा गांव के निवासी थे. 1995 से वह क्रान्तिकारी आन्दोलन से जुड़े हुए थे. जनता में अच्छी छवि और क्रान्ति के प्रति निष्ठा की बदौलत वह गांव में डीएकेएमएस का अध्यक्ष चुन लिए गए थे. जन संगठन की अगुवाई करते हुए उन्होंने कई प्रचार कार्यक्रमों व संघर्षों में भाग लिया. दुश्मन के खिलाफ पीएलजीए और जन मिलिशिया द्वारा की गई फौजी कार्रवाइयों में भी उन्होंने भाग लिया. 4 अगस्त 2005 को मलेरिया बीमारी के चलते उनकी असमय मृत्यु हुई. गांव के संगठन सदस्यों ने उनकी यादगार में एक शोकसभा का आयोजन किया जिसमें कॉमरेड केये को श्रद्धांजली पेश की गई.

कॉमरेड सुनीला का जन्म माड़ डिवीजन के परालकोट इलाके के सितरम गांव के एक गरीब आदिवासी परिवार में हुआ था. 2004 में वह सीएनएम (चेतना नाट्य मंच) में भर्ती हुई थी. उसने गांवों में घूमकर गलत रीति-रिवाजों के खिलाफ जनता में अलख जगाया. वह एक बढ़िया कलाकार थी. एक साल के अन्दर ही उसने कई गीत और नृत्य सीखे. उसके नाच-गाने को देखने और सुनने के लिए जनता काफी उत्सुक होती थी. 28 जुलाई 2005 के दिन अपने गांव में आयोजित कार्यक्रम में उसने सांस्कृतिक प्रदर्शन दिए थे. बाद में वह अपने घर जाकर सोई थी. नींद में ही उसे सांप काटा. तुरन्त बाद उसकी मौत हो गई. उसे बचाने की कोशिश करने का मौका भी नहीं था. बाद में सीएनएम, केएएमएस और डीएकेएमएस कार्यकर्ताओं ने पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया और शोकसभा आयोजित की.

कॉमरेड्स मन्नी, महेश और सत्ती को लाल सलाम !!

माड़ डिवीजन के इंद्रावती इलाके के (भैरमगढ़ ब्लॉक) एहकेल गांव में 14 नवम्बर 2005 की सुबह के 8.15 बजे पुलिस व सीआरपी बलों ने एक क्रूरतापूर्ण हमला कर कॉमरेड मन्नी, महेश और सत्ती की हत्या की. इस एकतरफा गोलीबारी में दो अन्य लोग घायल हो गए जो बचकर भाग निकले और दो अन्य घायल महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया. एक मामूली महिला को भी पुलिस ने इस मौके पर गिरफ्तार किया. ये सभी लोग जन संगठनों व जन मिलिशिया के आम सदस्य थे जो जनता की मदद करते हुए खेतों में फसल काट रहे थे. आइए, इन यवा शहीदों की संक्षिप्त जीवनियां जान लें.

कॉमरेड मन्नी (20) : कॉमरेड कुड़ियाम मन्नी का जन्म ऊतला गांव के एक गरीब परिवार में हुआ था. जमीन के अभाव से परेशान इनका परिवार कुछ साल पहले नेलसनार से यहां आकर बसा था. प्रकृति के साथ संघर्ष करके इन लोगों ने रोटी कमाने लायक कुछ जमीन बना ली. 1998 में कॉमरेड मन्नी क्रान्तिकारी आन्दोलन के सम्पर्क में आ गए. 2000 में उनके गांव में गठित बाल संगठन के वे अध्यक्ष चुने गए थे. बाल संगठन के अध्यक्ष के नाते उन्होंने गांव के बच्चों का नेतृत्व किया. बाद में जब वह जवान हो गए तो अन्य जन संगठनों की गतिविधियों में भाग लेने लगे. जन संगठन व पार्टी के नेताओं का वह काफी सम्मान करते थे. दुष्ट मुखियाओं के खिलाफ गांव में किए गए संघर्षों में कॉमरेड मन्नी की सक्रिय भूमिका रही. खुफिया तरीके से वह मुखियाओं की साजिशों का पता लगाकर छापामार दस्ते को बताया करते थे. जनवरी 2004 में वह ग्राम सुरक्षा दस्ते के सदस्य बन गए. इस इलाके में की गई जन मिलिशिया की तमाम गतिविधियों में उन्होंने भाग लिया. जनवरी 2005 में गठित जन मिलिशिया दस्ते में उन्हें सदस्य के रूप में नियुक्त

किया गया. एरिया पार्टी कमेटी ने निर्णय किया था कि 2005 मार्च से जून तक पूरे इलाके में जन कल्याण कार्यक्रम अपनाए जाएं. इसके तहत कुंओं और मकानों का निर्माण, पुराने घरों व जमीनों की मरम्मत आदि कार्यक्रम चलाए गए. इन सभी में कॉ. मन्नी ने उत्साह के साथ भाग लिया. इन कार्यक्रमों के दौरान जनता की नजरों में जन मिलशिया दस्ते का सम्मान और ज्यादा बढ़ गया. कॉमरेड मन्नी की मृत्यु की खबर सुनकर ऊतला और आसपास के सभी गांवों में जनता ने आंसू बहाए. उनकी हत्या का बदला लेने का संकल्प लिया.

कॉमरेड महेश (20) : कॉ. महेश बोगामी का जन्म बेलनार गांव का पारा कोडेम में हुआ था. इनके पिता गायता (पटेल) थे. कुछ साल पहले दन्तेवाड़ा इलाके से इनका परिवार यहां आकर बस गया था. जब उनके पिता जिन्दा थे तब उनका परिवार एक सामन्ती परिवार हुआ करता था. पिता की मृत्यु के बाद वे मध्यम वर्ग में आ गए. पांच भाइयों में से कॉमरेड महेश सबसे बड़े थे. बचपन से ही उनका लगाव क्रान्तिकारी आन्दोलन की तरफ था. बाल संगठन का अध्यक्ष बनकर उन्होंने गांव के बच्चों को बुरी आदतों से दूर रखा था. 2003 में इस इलाके में गठित सीएनएम दस्ते में उन्हें डिप्यूटी कमाण्डर बनाया गया था. क्रान्तिकारी गीतों व नृत्यों से इलाके की जनता में कॉमरेड महेश की अच्छी छवि बन गई. नाच-गानों में ही नहीं, बल्कि युद्ध कला में भी उन्होंने खुद को सक्षम बनाने की कोशिश की. केन्द्र-राज्य सरकारों द्वारा दण्डकारण्य आन्दोलन के खिलाफ छेड़े गए 'सलवा जुडूम' दमन अभियान को हराने हेतु पार्टी के आह्वान के मुताबिक महेश ने मिलिशिया दस्ते में शामिल होकर जन दुश्मनों व पुलिस बलों के खिलाफ किए गए कई हमलों में भाग लिया. सलवा जुडूम के डर से भागे हुए लोगों की फसलें काटकर सुरक्षित रखने के पार्टी के फैसले के मुताबिक एहकेल में 14 नवम्बर 2005 को जब जन मिलिशिया सदस्य फसल काट रहे थे तब पुलिस बलों ने उन पर गोलियां बरसाईं. इसमें कॉमरेड महेश की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई. 16 नवम्बर को बेलनार गांव में आयोजित शोक सभा में सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर कॉमरेड महेश को श्रद्धांजली पेश की.

कॉमरेड महेश बोगामी

कॉमरेड सत्ती (20) : कॉ. सत्ती का जन्म भी बेलनार के कोडेम पारा में हुआ था. वह बेहद गरीब परिवार में पला-बढ़ा था. सत्ती जब छोटा था तभी उसके सिर से पिता का साया हट गया था. मां ने कई मुश्किलें झेलकर उसे पाल-पोसकर बड़ा किया. उनका मूल गांव कवुर था. जीने के लिए कोई जरिया नहीं था इसलिए उनका परिवार 20-25 साल पहले यहां आकर बसा था. 1989-90 के आसपास इस इलाके में क्रान्तिकारी गतिविधियां शुरू हुईं. 2003 में सत्ती गांव के सुरक्षा दस्ते में भर्ती हो गया था. पोल्लेवाया रेंज में जन संगठनों की अगुवाई में किए गए जमीन संघर्षों व जन दुश्मनों को दण्डित करने की कार्रवाइयों में कॉमरेड सत्ती ने उत्साह के साथ भाग लिया. जनता की सेवा करने की स्फूर्ति कॉमरेड सत्ती के मन में कूट-कूटकर भरी हुई थी. बस्तर के सामन्ती मुखिया महेन्द्र कर्मा की अगुवाई में आदिवासी जनता के खिलाफ छेड़े गए जुल्मी सलवा जुडूम को नाकाम करने के लिए कॉ. सत्ती ने बाकी साथियों के साथ इंद्रावती नदी के तट पर मोर्चा सम्भालकर दिन-रात संतरी ड्यूटी किया. सलवा जुडूम के डर से भागने वाले लोगों का सत्ती ने ढाढ़स बंधाकर रोका. दर्जनों गांवों में जनता की फसलें काटने और अनाज को सुरक्षित रखने में उन्होंने जनता की जिस तत्परता से मदद की वह काफी सराहनीय रही. 16 नवम्बर को बेलनार में आयोजित शोकसभा में जनता ने इस युवा क्रान्तिकारी की शहादत को पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजली दी.

कॉमरेड सत्ती बोगामी

कॉमरेड्स दुकारू और बुधरू को लाल सलाम !

माड़ डिवीजन के इंद्रावती इलाके के डुंगा गांव (नारायणपुर तहसील, ओरछा ब्लॉक) के कॉमरेड दुकारू 1999 से क्रान्तिकारी आन्दोलन के साथ जुड़े थे. 1999 में गांव में गठित डीएके एमएस की कार्यकारिणी में उनका चुनाव किया गया था. जन संगठनों की अगुवाई में गांव में चलाए गए कई कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी रही. कई सभा-सम्मेलनों में उन्होंने भाग लिया. 29 नवम्बर को जब वह अपने खेत में फसल काट रहे थे तब नगा पुलिस बलों व सलवा जुडूम गुण्डावाहिनी ने घेरकर पकड़ लिया और रात भर बुरी यातनाएं देकर अगले दिन चाकुओं से गला काटकर उनकी निर्मम हत्या की.

कॉमरेड दुकारू

कॉमरेड बुधरू डुंगा से थोड़ी ही दूर पर स्थित वेड़मा गांव के निवासी थे. वह एक आम गरीब किसान थे जोकि मानसिक रूप से विक्षिप्त थे. उन्हें छापामार दस्ते ने दवाई दी थी जिससे कुछ समय तक ठीक रहे. उनकी पत्नी 5 साल पहले चल बसी थी. उनके दो बच्चे हैं. पिछले एक साल से वह फिर विक्षिप्त होकर इधर-उधर भटकते रहते थे. ऐसे आदमी को नगा पुलिस व सलवा जुडूम गुण्डों ने निर्मम तरीके से मार डाला. एक पागल को मारकर उन्होंने खुद को पागल कुत्ते साबित किए. ऐसी हत्याओं से जनता के दिलों में नफरत की जो आग सुलग रही है, उसमें झुलसकर नगा पुलिस वालों व गुण्डों को एक न एक दिन पागल कुत्तों की तरह मरना ही पड़ेगा. ✶

कॉमरेड बुधरू

आतंकी नगा पुलिस पर पीएलजीए का शानदार हमला

9 मरे और 9 घायल

6 फरवरी का दिन फिर एक बार यादगार दिन साबित हुआ. ज्ञात हो कि इसी दिन 2004 में पीएलजीए ने कोरापुट हमलों को कामयाबी के साथ अंजाम दिया था. फिर इस वर्ष 2006 में 6 फरवरी वीरता और पराक्रमता का दिन साबित हुआ. दक्षिण बस्तर के कोंटा के नजदीक भेज्जी और कोत्ताचेरुवु के बीच पीएलजीए के लाल योद्धाओं ने एक जबर्दस्त बारूदी सुरंग का विस्फोट कर नगा बटालियन की एक गाड़ी उड़ा दी. इस हमले में 9 आतंकी नगा बल वहीं का वहीं कुत्ते की मौत मरे, जबकि 9 बुरी तरह घायल हो गए. इस शानदार हमले की अहमियत इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि पिछले 9 महीनों से जारी जुल्मी 'सलवा जुडूम' के दौरान बस्तर के आदिवासी अवाम को इन्हीं नगा जवानों ने सबसे ज्यादा आतंकित किया. इन्होंने कई निर्दोष लोगों की हत्या की, लोगों के घर जला दिए, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं की तो कोई हिसाब नहीं है. शासन-प्रशासन और पूंजी के तलवे चाटने वाली मीडिया ने नगा बलों की ढोंगी 'शूरता' के बारे में जान-बूझकर कई झूठे किस्से गढ़ दिए ताकि लोगों के दिल में दहशत भर जाए. उनके बारे में सुनियोजित ढंग से मीडिया में यह प्रचारित किया गया कि वे नक्सलियों से सीधी टक्कर लेकर मात दे सकते हैं तथा जंगल-पहाड़ों में लड़ने में उन्हें महारथ हासिल हैं... आदि-आदि. याद रहे 2003 में जब बस्तर में पहली बार सीआरपीएफ को उतारा गया था तब भी ऐसी ही कहानियां गढ़ी गई थीं. पर 2-3 महीनों के अन्दर ही उनकी 'बहादुरी' की पोल तब खुल गई जब वे पीएलजीए और जनता के हमलों में कुत्तों की तरह मारे जाने लगे थे. हालांकि नगा पुलिस बल को लेकर यह मिथक कुछ ज्यादा समय तक बना रहा कि उनकी कोई सानी नहीं है. लेकिन जनता की ताकत और पहलकदमी पर भरोसा रखने वाली पीएलजीए ने इस मिथक को इस अंदाज में तोड़ दिया कि रायपुर से लेकर कोहिमा और दिल्ली तक इसकी गूंजी सुनाई दी. जैसा कि सभी जानते है, पीएलजीए जनता की सेवा करती है. वह विश्वास करती है कि जनता ही इतिहास का निर्माता है. जनता की अद्भुत सृजनशीलता को न सिर्फ पीएलजीए सर्वोच्च मान्यता देती है, बल्कि उसे और ज्यादा उभारती है. इसी परम्परा को जारी रखते हुए पीएलजीए के बहादुर कमाण्डरों और जांबाज योद्धाओं, जिनमें नव गठित 'कोया भूमकाल मिलिशिया' के लाल सिपाही भी शामिल हैं, ने जनता की सक्रिय मदद व सहयोग से नगा पुलिस के सम्बन्ध में पक्की खुफिया सूचना इकट्ठी करके ऐसा धमाका किया कि आतंकी नगा पुलिस वालों के चीथड़े उड़ जाएं. उन्होंने पिछले 9 महीनों से दर्जनों मां-बहनों के साथ बलात्कार जो किया था, बीसियों मासूम लोगों का खून जो बहाया था, जिससे हजारों लोगों के दिल में उनके प्रति नफरत और आक्रोश की जो आग सुलगती रही थी.... इन सबका शानदार ढंग से बदला लिया गया. आइए... इस शूरतापूर्ण कारनामे को अंजाम देने वाले तमाम पीएलजीए योद्धाओं और दक्षिण बस्तर डिवीजन की संघर्षशील जनता का लाल अभिनन्दन करें.

कुछ अन्य कार्रवाइयां

विभिन्न प्रसार माध्यमों के जरिए हमें मिली पीएलजीए की जवाबी कार्रवाइयों सम्बन्धी संक्षिप्त रिपोर्टें इस प्रकार हैं -

- 29 की रात पीएलजीए योद्धाओं और 'कोया भूमकाल मिलिशिया' के लाल सैनिकों ने गंगलूर पुलिस थाने के परिसर में मौजूद तथाकथित 'राहत शिविर' पर हमला करके 8 लोगों को मार डाला और कुछ अन्य लोगों को घायल किया. ये तमाम लोग सरकार द्वारा संचालित 'सलवा जुडूम' में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले 'विशेष पुलिस अधिकारी' और मुखबिर थे. अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ एक महिला समेत पीएलजीए के तीन कॉमरेड शहीद हुए.

- 16 दिसम्बर 2005 को दक्षिण बस्तर डिवीजन के भेज्जी हाट बाजार में पीएलजीए के योद्धाओं ने दो सशस्त्र पुलिस वालों पर हमला कर उनकी दो एसएलआर रायफलें छीन लीं. पुलिस वाले जब खरीदारी कर रहे थे तब पीएलजीए योद्धाओं ने चाकुओं से उन पर वार किया. इस हमले में एक पुलिस वाला मारा गया और एक घायल हो गया. इस

आरा पुलिस चौकी पर पीएलजीए का कामयाब हमला

2 मरे, 12 घायल - सारे हथियार जब्त

6 फरवरी 2006 को छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में पीएलजीए ने एक धमाका किया. एक तरफ लुटेरे शासक वर्ग 'सलवा जुडूम' को उत्तर छत्तीसगढ़ के सरगुजा और जशपुर जिलों में फैलाने के खयाली पुलाव पकाने में मशगूल थे, तो पीएलजीए ने जशपुर जिले के आरा पुलिस चौकी पर हमला कर उनके मुंह बन्द करा दिया. बड़े ही सुनियोजित तरीके से पीएलजीए के बीसियों लाल सैनिकों ने अपने बहादुर कमाण्डरों की अगुवाई में चौकी पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया. हालांकि पुलिस वालों को काबू करने में कुछ समय जरूर लगा. दो जवान मारे गए थे और 12 घायल हुए थे, तब जाकर सबों ने पीएलजीए के सामने घुटने टेक दिए. पीएलजीए ने अपनी नीति के मुताबिक आत्मसमर्पण करने वाले सभी पुलिस कर्मियों की जान बख्श दी. चौकी से 18 हथियार उठा लिए जिनमें एक ग्रेनेड लॉन्चर, कुछ एसएलआर और एके-47 शामिल हैं. कायर पुलिस महानिदेशक ओपी राठौर ने पीएलजीए के हाथों मिली इस करारी हार को छिपाने के लिए यह बेतुकी दलील दी कि पुलिस वालों के पास गोलियां खत्म हो गई थीं इसलिए वे ज्यादा देर नहीं लड़ सके. छत्तीसगढ़ के उत्तरी और दक्षिणी भागों में एक ही दिन हुए दो (दन्तेवाड़ा जिले में नगा जवानों पर हुए हमले को मिलाकर) कामयाब हमलों ने न सिर्फ दण्डकारण्य और छत्तीसगढ़ बल्कि समूचे देश की मेहनतकश जनता को बेहद उत्साहित किया. देश के चारों तरफ संघर्षशील जनता ने पीएलजीए की जय-जयकार की. ✶

अप्रत्याशित हमले से बौखलाए पुलिस वालों ने स्थानीय जनता पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं जिसमें एक सेल्समेन रत्नू की मौत हुई जबकि कुछ अन्य घायल हो गए.

- 17 दिसम्बर 2005 को उत्तर बस्तर के काकनार इलाके में नगा पुलिस वालों ने एक गांव पर हमला करके कॉमरेड जल्मा की हत्या की. कॉमरेड जल्मा स्थानीय जन नेता थे. वह किसी काम पर दूसरे गांव जा रहे थे तो रास्ते में नगा पुलिस वालों ने उन्हें दौड़ाकर गोली मार दी. इसके तुरन्त बाद पीएलजीए के सैनिकों ने गांव पर नगा पुलिस के मुकाम पर हमला कर एक नगा जवान को मौत के घाट उतारकर कॉमरेड जल्मा की हत्या का बदला ले लिया. इस जवाबी हमले के बाद नगा बल दुम दबाकर भाग गए. गौरतलब है बस्तर में नगा जवानों की तैनाती के बाद से पीएलजीए के हाथों नगा पुलिस वालों के मरने की यह सबसे पहली घटना थी.

- 24 नवम्बर को गड़चिरोली डिवीजन के मल्लमपोड्डूर के नजदीक पीएलजीए सैनिकों ने दुश्मन के एक काफिले पर घात लगाकर हमला किया. इस हमले का उद्देश्य दुश्मन को हैरान-परेशान कर उसके तथाकथित जन जागरण मेळावों को नाकाम करना था. दुश्मन ने इस हमले से बौखलाकर पागलों की तरह सैकड़ों गोलियां चलाईं. कोई हताहत नहीं हुए.

- इसी महीने में ताड़िगामा में दुश्मन के प्रस्तावित 'जन जागरण' मेळावा और सामूहिक विवाह के खिलाफ जन मिलिशिया ने रात में धावा बोलकर दुश्मन के माइक सेट, डेक, आदि सारे सामान जला डाले.

- 2 दिसम्बर को गड़चिरोली के भामरागड़ इलाके में पीएलजीए सैनिकों ने दुश्मन के लिए जा रही रसद पर कब्जा किया. 1 क्विन्टल से ज्यादा सामान पीएलजीए सैनिकों ने छीन लिया. इस घटना के बाद बौखलाए पुलिस बलों ने जगह-जगह छापेमारी की पर कुछ हासिल नहीं हुआ.

- फरवरी के आखिरी सप्ताह में भैरगढ़ इलाके के बोदली के पास हुई एक मुठभेड़ में एक नगा पुलिस मारा गया और एक घायल हो गया. इस में पीएलजीए के दो कॉमरेडों के शहीद होने की खबरें आई हैं.

- 28 फरवरी को दक्षिण बस्तर डिवीजन के दरभागुड़ा के पास 'कोया भूमकाल मिलिशिया' ने सलवा जुडूम के तहत गांवों में आतंक मचाकर लौट रहे गुण्डों के काफिले पर हमला कर 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया. कई अन्य को घायल किया. इस घटना को लेकर लुटेरे शासक वर्गों ने ''आदिवासियों पर नक्सली हमला'' बताते हुए खूब हायतौबा मचाई. लेकिन सच्चाई यह है कि आदिवासी जनता पर लुटेरे शासक वर्गों द्वारा बड़े पैमाने पर किए जा रहे हमलों के जवाब में ही इस घटना को अंजाम दिया गया. इसकी जिम्मेदारी खुद रमन सिंह और महेन्द्र कर्मा की है. दर्जनों लोगों की हत्या करते हुए, दर्जनों गांवों को जलाते हुए, बेहद लूटपाट मचाने वाले आतंकी गुण्डों को यह सजा इसलिए दी गई ताकि शोषित आदिवासी जनता को बचाया जा सके.

- 4 मार्च 2006 को बस्तर जिले के बेनूर में पीएलजीए की एक एक्शन टीम ने एक पुलिस वाले का सफाया कर उसकी रायफल छीन ली.

- 5 मार्च 2006 को पीएलजीए की एक पलटन ने दन्तेवाड़ा के निकट भांसी रेलवे स्टेशन पर हमला कर एक माल गाड़ी की इंजन को विस्फोट से उड़ा दिया. ड्राइवर से दो वाकीटाकी सेटों को भी जब्त किया गया. बैलाड़ीला से जापानी साम्राज्यवादियों को लौह अयस्क के निर्यात के विरोध में इस घटना को अंजाम दिया गया.

- 6 मार्च को 'कोया भूमकाल मिलिशिया' के 4 हजार सैनिकों ने बासागूड़ा कस्बे पर धावा बोलकर सलवा जुडूम में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले 4 जन विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया और 10 अन्य को घायल किया. 5 लोगों को गिरफ्तार किया. लुटेरे शासक वर्गों द्वारा जारी नक्सलवादियों के पैर उखड़ने के दावों को झूठा साबित करते हुए हजारों जनता ने इस बड़ी कार्रवाई में भाग लिया. गौरतलब है कि इस कस्बे में पुलिस थाना और सीआरपीएफ का कैम्प भी मौजूद है पर जनता ने उन्हें अपने बैरकों में ही रहने पर मजबूर कर दिया. ✶

बैलाड़ीला बारूद डिपो पर पीएलजीए का हमला

8 जवान मरे, 9 घायल - हथियार और गोलाबारूद जब्त

इस वर्ष 10 फरवरी - ऐतिहासिक भूमकाल की वर्षगांठ बस्तर की संघर्षशील आदिवासी जनता ने बड़े उत्साह के माहौल में मनाया. इस उत्साह का कारण था पीएलजीए द्वारा नवगठित 'कोया भूमकाल मिलिशिया' की व्यापक भागीदारी के साथ बैलाडीला बारूद डिपो पर किया गया सफल हमला. 9 फरवरी 2006 की रात के 8 बजे दर्जनों पीएलजीए लाल योद्धाओं ने अपने बहादुर कमाण्डरों की अगुवाई में बैलाडीला के हिरोली बारूद डिपो पर धावा बोल दिया. ज्ञात हो कि बैलाडीला में एनएमडीसी (राष्ट्रीय खनिज विकास निगम) द्वारा लौह अयस्क का उत्खनन किया जाता है. यहां से बेशकीमती लौह अयस्क बेहद सस्ते में जापानी साम्राज्यवादियों को बेचा जाता है. इस डिपो की सुरक्षा के लिए सीआइएसएफ (केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल) के जवान तैनात किए गए थे. पीएलजीए ने इस अर्ध सैनिक टुकड़ी पर हमला कर 8 जवानों को मौत के घाट उतार दिया और 9 को घायल किया. उनसे 17 एसएलआर रायफलें छीन लीं. खबरों के मुताबिक बारूद डिपो से 20 टन बारूद भी पीएलजीए ने अपने कब्जे में लिया. अखबारों को जारी एक बयान में पार्टी के पश्चिम बस्तर डिवीजनल कमेटी सचिव कॉमरेड गणेश ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई 'सलवा जुडूम' के नाम पर आदिवासी जनता पर जारी पाशविक हमले के खिलाफ थी. उन्होंने यह भी बताया कि इस 'ऑपरेशन आकाश' को महज 20 मिनटों में पूरा किया गया. पिछले 9 महीनों से 'सलवा जुडूम' के नाम से सरकारी बलों द्वारा जारी फासीवादी हमलों के बीचोबीच इस हमले को शानदार ढंग से अंजाम देकर पीएलजीए ने अपनी लड़ाकू क्षमता का उम्दा प्रदर्शन किया. इसके साथ-साथ उसने शासक वर्गों की इस बकवास को भी रद्दी के टोकरे में पहुंचा दिया कि बस्तर के आदिवासियों ने अब माओवादियों के खिलाफ आन्दोलन शुरू किया है. इस हमले में सैकड़ों आदिवासियों ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में अपना योगदान देकर यह साबित किया कि हत्या और आतंक के बल पर उन्हें दबाया नहीं जा सकता. ✶

सभा-सम्मेलन

गांव-गांव में उत्साह के साथ मनाई गई दण्डकारण्य जनयुद्ध की 25वीं वर्षगांठ व पीएलजीए की 5वीं वर्षगांठ

भाकपा (माओवादी) दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के आहवान पर 2005 दिसम्बर 2 तारीख से 31 तारीख तक दण्डकारण्य के गांव-गांव में जनयुद्ध की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई. इस मौके पर कई जगहों पर छोटी-बड़ी आमसभाएं आयोजित की गईं जिनमें हजारों लोगों ने भाग लिया. खासकर पश्चिम बस्तर डिवीजन में जारी भीभत्सपूर्ण 'सलवा जुडूम' दमन अभियान के बीचोबीच भी जनता ने इन आयोजनों को कामयाबी दिलाई. पीएलजीए ने इन आयोजनों को सफल बनाने हेतु सुरक्षा के सारे कदम उठाए. इन कार्यक्रमों में भाग लेकर जनता ने दण्डकारण्य में जारी जनयुद्ध को नई ऊंचाइयों तक विकसित कर इस क्षेत्र को आधार इलाके में तब्दील करने का संकल्प दोहराया. पेश हैं कुछ डिवीजनों के आयोजनों सम्बन्धी रिपोर्टें -

गड़चिरोली डिवीजन

भामरागड़ एरिया में 25वीं वर्षगांठ के सम्बन्ध में पोस्टर, पामफ्लेट आदि के जरिए व्यापक प्रचार अभियान चलाया गया. 25 दिसम्बर को इस इलाके के एक गांव में सभा आयोजित की गई जिसमें 210 लोगों ने भाग लिया. सभा के प्रारम्भ में झण्डा फहराकर पेद्दि शंकर से लेकर आज तक दण्डकारण्य आन्दोलन में शहीद हुए तमाम वीरों को श्रद्धांजलि दी गई. इस मौके पर जन संगठनों के पुराने नेताओं ने सभा को सम्बोधित किया. उन्होंने कहा कि सरकार चाहे लोगों को जेल में डाले या मार डाले यह लड़ाई नहीं रुकेगी. उन्होंने अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए कहा कि पार्टी के आने के बाद ही जनता ने संघर्ष की बदौलत कई उपलब्धियां हासिल की हैं. जनता भी बुजुर्ग लोगों के इन वक्तव्यों से काफी खुश हुई. उसके बाद पार्टी के अन्य नेताओं ने जनता को सम्बोधित किया. उन्होंने अपने भाषणों में जोर दिया कि पिछले 25 बरसों की लड़ाई के फलस्वरूप जो कुछ भी हासिल किया गया उसे बचाना है और दण्डकारण्य को आधार इलाके में तब्दील करना है तो जन सेना को मजबूत बनाना हमारा सबसे मुख्य कर्तव्य है. पूरे इलाके में नौजवानों में यह संदेश फैलाया गया कि वे बड़ी संख्या में पीएलजीए में भर्ती होकर देश की मुक्ति के लिए संघर्ष करें. गौरतलब है कि ये आयोजन पुलिस के गहन गश्त और खोजबीन अभियानों के बीचोबीच सम्पन्न हुए, जिसने दण्डकारण्य आन्दोलन की 25वीं वर्षगांठ को नाकाम करने के लिए एड़ी-चोटी एक कर रखी थी.

गड़चिरोली के एक गांव में 25वीं वर्षगांठ सभा

गट्टा इलाके में दण्डकारण्य संघर्ष की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर बड़े पैमाने पर पोस्टर, बैनर, आदि के जरिए प्रचार अभियान चलाया गया. पुलिस थाना वाले गांवों में भी पोस्टर, दीवार-लेखन आदि किए गए. एक स्वागत कमेटी का निर्माण किया गया. इस कमेटी की अगुवाई में 26 दिसम्बर को कुंजेमरका गांव में एक सभा आयोजित की गई. इस दौरान उपस्थित लोगों ने जोर शोर से नारे लगाए. स्वागत कमेटी सदस्य कॉमरेड पाण्डू ने झण्डा फहराया. सभा को सम्बोधित करते हुए स्वागत कमेटी अध्यक्ष कॉमरेड रैनू ने कहा कि पार्टी के आने से पहले यहां आदिवासियों को जंगल पर कोई अधिकार नहीं था. पेपरमिल और फारेस्ट वाले लोगों का बेहद शोषण करते थे. पार्टी के आने के बाद, लोगों के जन संगठनों में संगठित होने के बाद शोषण के खिलाफ संघर्षों का सिलसिला चल पड़ा. सभा के दौरान सीएनएम कॉमरेडों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए. इस सभा में कुल करीब 500 लोगों ने भाग लिया.

अहेरी इलाके के 11 गांवों में आयोजित सभाओं में कुल 400 लोगों ने भाग लिया. पूरे इलाके में बैनरों एवं पोस्टरों के जरिए प्रचार किया गया. सिरोंचा इलाके में दो जगहों पर सभाएं हुईं जिनमें कुल 165 लोगों ने भाग लिया.

कसनसूर इलाके के एक गांव में 2 दिसम्बर 2005 को एक सभा आयोजित की गई. दण्डकारण्य संघर्ष की 25वीं वर्षगांठ और पीएलजीए की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित इस सभा में करीब 300 स्त्री-पुरुषों ने भाग लिया. इसके पहले इस इलाके में पोस्टरों व बैनरों के जरिए बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान चलाया गया.

एटापल्ली इलाके के कोटमी गांव में 12 दिसम्बर को आयोजित एक सभा में करीब 3 हजार लोगों ने भाग लिया. इसके पहले कसनसूर, पोटेगांव और सूर्जागढ़ इलाकों में जन मिलिशिया ने करीब 750 पोस्टरों के जरिए खूब प्रचार किया था. इस सभा में सीएनएम कॉमरेडों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए. वक्ताओं ने दण्डकारण्य आन्दोलन के विकासक्रम पर रोशनी डाली. कॉमरेड रैनू ने सभा की अध्यक्षता की.

पेरिमिलि इलाके में एक महीने पहले से ही पोस्टरों व पर्चों से बड़े पैमाने पर प्रचार कार्यक्रम चलाए गए. बाद में दो जगहों पर सभाएं आयोजित की गईं जिनमें कुल 8 गांवों के करीब 250 स्त्री-पुरुषों ने भाग लिया. बाद में 5 जगहों पर सभाएं हुईं जिनमें 700 महिलाओं समेत 2200 लोगों ने भाग लिया. सिरिगुरजा, एरमानार टोला, मिच्चिगुण्डा गांवों की 170 जनता ने एक और सभा में भाग लिया. ग्राम चन्द्रा में रात में एक रैली निकाली गई जिसमें 100 लोगों ने भाग लिया. बुरगी गांव में एक रैली निकाली गई जिसमें 500 लोगों ने भाग लिया. रेकानार टोला, मंगेर, गोड्डेली गांवों के 150 लोगों ने एक जगह

गड़चिरोली के एक गांव में 25वीं वर्षगांठ रैली

सभा की. एक जगह और सभा हुई जिसमें कुल 21 गांवों से 1200 स्त्री-पुरुषों ने भाग लिया. गौरतलब है कि ये सारी सभाएं दुश्मन की आंखों में धूल झोंककर आयोजित की गईं. जनता ने दुश्मन को इन आयोजनों के सम्बन्ध में जरा भी पता लगने नहीं दिया. सभा-स्थलियों को लाल बन्दनवारों, लाल झण्डों व बैनरों से सजाया गया. इन सभाओं को पार्टी और पीएलजीए के नेताओं के अलावा लम्बे समय से आन्दोलन के साथ जुड़े हुए बुजुर्ग ग्रामीणों ने भी सम्बोधित किया. स्थानीय जन संगठन नेताओं ने भी जनता को सम्बोधित किया. बड़े उत्साह के माहौल में पिछले 25 बरसों की लड़ाई के दौरान हासिल उपलब्धियों को बनाए रखते हुए दण्डकारण्य को मुक्तांचल में तब्दील करने के लक्ष्य से आगे बढ़ने के संकल्प के साथ इन सभाओं का समापन हुआ.

माड़ डिवीजन

परालकोट इलाके में दण्डकारण्य जनयुद्ध की 25वीं वर्षगांठ और पीएलजीए की 5वीं वर्षगांठ को एक साथ मनाया गया. 2 दिसम्बर 2005 को गांव कोंगे में सुबह 10 बजे लोगों ने रैली निकाली. रैली गांव की गलियों से गुजरते हुए शहीद स्मारक के पास जा पहुंची, जहां स्थानीय दस्ता कमाण्डर कॉमरेड विमला ने झण्डा फहराकर 25 सालों की लड़ाई में शहीद हुए तमाम वीरों के श्रद्धांजली पेश की. उन्होंने इस मौके पर लोगों का आहवान किया कि शहीदों का अन्तिम लक्ष्य कम्युनिजम को साकार बनाने तक संघर्ष जारी रखें. बाद में स्थानीय सीएनएम कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए. उसके बाद गांव के जन संगठन नेताओं ने भी सभा को सम्बोधित किया.

ग्राम गारपा में 20 दिसम्बर को एक सभा आयोजित की गई. इस सभा में 500 से ज्यादा स्त्री-पुरुषों ने भाग लिया. लोगों ने अपने हाथों में जन संगठनों और पार्टी के झण्डे, पोस्टर, प्लाकार्ड, बैनर आदि लेकर जोर शोर से नारे लगाते हुए रैली निकाली. माहौल ऐसा लग रहा था कि पूरे गांव पर ही लालिमा छा गई हो. डीएकेएमएस, केएएमएस और पीएलजीए के कामरेडों के साथ-साथ कॉमरेड विमला ने सभा को सम्बोधित किया. सीएनएम कॉमरेडों ने क्रान्तिकारी गीत और नृत्य पेश किए. सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक सभा चलती रही. पीएलजीए के सैनिक गांव की चारों तरफ पहरा देकर कार्यक्रम को सुचारू ढंग से अंजाम देने में अपना योगदान दिया. ✶

बात पाठकों की

27-12-2005

'प्रभात' सम्पादक मण्डल को लाल सलाम.

'प्रभात' के जुलाई-दिसम्बर 2005 अंक में 3 रिपोर्टों में गलतियां छपी थीं. गलतियां विषय सम्बन्धी नहीं थीं, बल्कि तारीखें गलत छपी थीं. (1) अकाल रैली धनोरा में 28 जुलाई को सम्पन्न हुई, ऐसा आपने लिखा है. पर दरअसल यह रैली 28 अप्रैल को निकाली गई थी. (2) गड़चिरोली में पीएलजीए द्वारा किए गए एम्बुश में पांच कमाण्डो की मौत वाली रिपोर्ट में घटना की तारीख 3 अप्रैल छपी थी. लेकिन वास्तव में यह एम्बुश 3 जुलाई को हुआ था.(3) बारूदी सुरंग रोधक गाड़ी को ध्वस्त कर 24 जवानों को मार गिराने वाला एम्बुश 3 सितम्बर 2005 को हुआ था, पर 'प्रभात' में साल 2004 छपा था.

किसी-किसी पत्रिका में एक-एक पन्ना गायब था. हमें जो मिली थी उसमें 43-44 पन्ने गायब थे.

क्रान्तिकारी अभिनन्दन के साथ,

स्क्रीन प्रिन्टिंग यूनिट,

चादगांव एरिया, गड़चिरोली डिवीजन.

सम्पादकों का जवाब :

कॉमरेडो लाल सलाम !

आपकी चिट्ठी पढ़कर हमें बहुत खुशी हुई. अपनी गलतियों के लिए हम खेद प्रकट करते हैं. आइंदा रिपोर्टें लिखते समय ऐसी गलतियां न हों, इस पर हम पूरा ध्यान दिया करेंगे. छपाई और बाइंडिंग के दौरान भी हमें अपने काम में और सुधार लाने की जरूरत है. आपने हमारी खामियां बताईं, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया. हम उम्मीद करते हैं कि आप यूं ही 'प्रभात' में छपने वाले लेखों के बारे में भी समय-समय पर अपनी राय जरूर लिखते रहेंगे.

– सम्पादक मण्डल

गड़चिरोली के एक गांव में 25वीं वर्षगांठ सभा

दण्डकारण्य में क्रान्तिकारी जन संगठनों के अधिवेशन सम्पन्न

माड़ डिवीजन

डीएकेएमएस परालकोट रेंज अधिवेशन

परालकोट रेंज डीएकेएमएस अधिवेशन 22-23 दिसम्बर 2005 को सम्पन्न हुआ. इसमें कुल 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इस अधिवेशन में डीएकेएमएस के घोषणा-पत्र व संविधान पर चर्चा हुई. सभी प्रतिनिधियों ने बड़े उत्साह के साथ इस अधिवेशन में भाग लिया. बाद में अधिवेशन ने संगठन की कार्यकारिणी का चुनाव किया.

डीएकेएमएस माड़ डिवीजन प्रथम अधिवेशन

15-17 जुलाई 2005 को डीएकेएमएस माड़ डिवीजन का प्रथम अधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ. इसमें कुल 17 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इस अधिवेशन में मुख्य रूप से लुटेरे वर्गों द्वारा लादे गए जुल्मी सलवा जुडूम अभियान पर चर्चा की गई और व्यापक जन प्रतिरोध के जरिए इसका मुकाबला करने का फैसला लिया गया. इसके अलावा माड़ क्षेत्र में हिन्दू और ईसाई धर्मों की घुसपैठ पर भी चर्चा की गई. इस पर यह फैसला लिया गया है कि आदिवासी जनता में यह प्रचार करना है कि आदिवासी न तो हिन्दू है, न ही ईसाई. उनकी अपनी अलग संस्कृति है, अपनी जीवन शैली है, अपने देव-देवता हैं. शासक वर्ग, खासकर भाजपा सरकार के शासन के दौरान फल-फूल रही हिन्दू धार्मिक संस्थाएं आदिवासियों को हिन्दू बताकर बड़े पैमाने पर झूठा प्रचार कर रही हैं. इसलिए जन जागृति के जरिए इन घिनौनी कोशिशों को नाकाम करने का फैसला लिया गया. इसके अलावा पूरे डिवीजन में संगठन को मजबूत बनाने, संगठन में महिलाओं की सदस्यता बढ़ाने आदि फैसले अधिवेशन ने लिए. संघर्ष को आगे बढ़ाने, लुटेरी सरकार के झूठे सुधारों का विरोध करने और दण्डकारण्य को मुक्तांचल में तब्दील करने के संकल्पों के साथ अधिवेशन सम्पन्न हुआ.

माड़ डिवीजनल सीएनएम प्रथम अधिवेशन

2005 में माड़ डिवीजन सीएनएम का प्रथम अधिवेशन सम्पन्न हुआ. इस अधिवेशन में संगठन के घोषणा-पत्र और संविधान पर बहस हुई.

गड़चिरोली के एक गांव में 28 जुलाई - शहीद दिवस

बहस के बाद प्रतिनिधियों ने सर्व सम्मति के साथ उन्हें पारित किया. इस अधिवेशन में मुख्य रूप से आदिवासी संस्कृति पर हिन्दू मनुवादी संस्कृति के हमलों पर काफी चर्चा हुई. इसके अलावा समाज में और संगठन में मौजूद पितृसत्तात्मक रुझानों को पहचान कर उन्हें दूर करने का फैसला लिया गया. इसके अलावा जनता में शराब, गांजा, लंदा, गुटखा, गुड़ाखू जैसे नशीले पदार्थों के सेवन के खिलाफ प्रचार अभियान चलाने का फैसला लिया गया. साम्राज्यवादी संस्कृति की घुसपैठ के चलते जनता में बढ़ रहे उपभोक्तावाद को भी सांस्कृतिक कर्मी निशाना बनाएं, ऐसा भी फैसला हुआ है.

गड़चिरोली डिवीजन

अहेरी एरिया डीएकेएमएस प्रथम अधिवेशन

18-19 दिसम्बर को गड़चिरोली डिवीजन के अहेरी एरिया में डीएकेएमएस का प्रथम अधिवेशन सम्पन्न हुआ. इसमें कुल 23 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. घोषणा-पत्र और राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा के बाद अधिवेशन ने उन्हें पारित किया. बाद में कुछ अन्य प्रस्ताव भी किए गए जिनमें जंगल बचाओ, सरकारी सुधारों के प्रति जनता के विरोध आदि शामिल हैं. देवुलामर्री, सूर्जागढ़ पहाड़ों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की खदानें खोलने की कोशिशों के खिलाफ भी अधिवेशन ने प्रस्ताव किए. आखिर में अधिवेशन ने 9 सदस्यीय कार्यकारिणी का चुनाव किया.

गड़चिरोली के एक गांव में 28 जुलाई - शहीद दिवस

ऊसूर रेंज (दक्षिण बस्तर) केएएमएस रेंज अधिवेशन – सितम्बर 2004

गट्टा रेंज सीएनएम प्रथम अधिवेशन

11-13 सितम्बर 2005 को गट्टा इलाके में सीएनएम का पहला अधिवेशन सम्पन्न हुआ. इस अधिवेशन में कुल 21 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इस सभा में मुख्य रूप से आदिवासी संस्कृति पर साम्राज्यवादी संस्कृति के हमले के बारे में चर्चा की गई. वक्ताओं ने कहा कि सामूहिकता को अत्यधिक महत्व देने वाली आदिवासी संस्कृति आज खतरे में है. बाजारू, उपभोक्तावादी व महिलाओं को वस्तु के रूप में देखने वाली मुनाफाखोर साम्राज्यवादी संस्कृति की दखल तेजी पर है. इसे रोकना सीएनएम का अहम कर्तव्य है. आदिवासी संस्कृति में मौजूद खूबियों को उभारते हुए जनता की जनवादी संस्कृति को विकसित करने की ओर सीएनएम को कदम बढ़ाना है, इस संकल्प के साथ अधिवेशन कामयाबी के साथ सम्पन्न हुआ.

21 सितम्बर – पार्टी की पहली वर्षगांठ

माड़ डिवीजन के कुत्तुल इलाके में कुल 6 जगहों पर 21 सितम्बर के दिन पार्टी की पहली वर्षगांठ मनाई गई. भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के गठन के बाद से जनयुद्ध को आगे बढ़ाने के दौरान हासिल उपलब्धियों और मुंह बाएं खड़ी चुनौतियों के बारे में इन सभाओं को सम्बोधित करने वाले वक्ताओं ने जनता के सामने रखा. कुत्तुल में 450, बीनागुण्डा में 350, जटवागै में 400, सोनपुर में 300, कोहकामेट्टा में 700 और कुस्तुरमेट्टा में 250 लोगों ने इस मौके पर आयोजित सभाओं में भाग लिया. इन सभाओं में ''कॉमरेड्स चारु मजुमदार और कन्नाई चटर्जी अमर रहें'' तथा ''पीएलजीए को पीएलए में बदल डालो'' के नारे जोर शोर से लगाए गए. इस सप्ताह को लेकर पहले से ही पूरे इलाके में पोस्टरों व बैनरों से बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान चलाया गया. इस प्रकार भकपा (माओवादी) के स्थापना दिवस का संदेश इलाके के हजारों जनता तक पहुंचाया गया.

10 फरवरी – भूमकाल दिवस

10 फरवरी 2006 - भूमकाल संघर्ष की वर्षगांठ के अवसर पर माड़ डिवीजन के कोहकामेट्टा के आसपास कई गांवों में पेस्टरों व बैनरों से बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान चलाया गया. 10 फरवरी को सुबह से ही लोग भूमकाल दिवस मनाने हेतु उत्साह के साथ आने लगे थे. जैसे-जैसे सूरज बढ़ने लगा, कोहकामेट्टा के गोटुल के पास लोगों का जमावड़ा व्यापक होता गया. जन संगठन कार्यकर्ताओं ने जनता को व्यवस्थित ढंग से बिठाया. इसके बाद सीएनएम कलाकारों के दस्ते ने क्रान्तिकारी नाच-गाने का कार्यक्रम शुरू किया. इसके साथ ही रैली शुरू हुई. लोगों ने दो-दो की लाइन में अनुशासित ढंग से कतारबद्ध होकर हाथों में लाल झण्डे, पोस्टर, प्लैकार्ड आदि उठाकर जोर-शोर से नारे लगाए. ''महान भूमकाल जिन्दाबाद'', ''सलवा जुडूम मुर्दाबाद'' आदि नारे लगाए गए. महान भूमकाल स्तम्भ के पास जाकर रैली एक विशाल सभा में बदल गई. वहां पर पार्टी और पीएलजीए के झण्डे फहराए गए. भूमकाल शहीदों समेत देश की नव जनवादी क्रान्ति के दौरान शहीद हुए तमाम वीरों को श्रद्धांजली दी गई. उसके बाद सभा को कॉमरेड कौसल्या समेत जन संगठनों व जनताना सरकार संस्थाओं के कुछ प्रमुख नेताओं ने सम्बोधित किया. भाषणों के दरमियान सीएनएम वालों ने कई गीत पेश किए. लगातार 4 घण्टे तक चले इस समारोह में 10 गांवों से करीब 2,500 स्त्री-पुरुषों ने भाग लिया. इस आयोजन को सफल बनाने में जन मिलिशिया की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही. उन्होंने कोहकामेट्टा की ओर आने वाले तमाम रास्तों को अपने काबू में रखकर सुरक्षा का ऐसा पुख्ता इंतजाम कर रखा था कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सके. एक तरफ पुलिस व अर्ध सैनिक बल 'सलवा जुडूम' के नाम से पश्चिम बस्तर की तर्ज पर माड़ डिवीजन में भी विनाशकारी दमन अभियान चलाने की जी-तोड़ कोशिशें कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जनता ने 'भूमकाल दिवस' में उत्साह के साथ भाग लेकर यह साबित कर दिया कि शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने की उनकी परम्परा को कोई नहीं तोड़ सकता. ✶

दक्षिण बस्तर के एक गांव में सहकारिता के आधार पर जारी खेती के काम

संघर्ष की राह में दण्डकारण्य जनता का आगे कदम

15 नवम्बर को 'गड़चिरोली जिला बन्द' सफल

गड़चिरोली डिवीजन में रोज-रोज बढ़ रहे शत्रु दमन के खिलाफ भाकपा (माओवादी) की गड़चिरोली डिवीजनल कमेटी ने 15 नवम्बर 2005 को जिला बन्द का आहवान किया था. पुलिस वालों ने कुछ ही महीनों के अन्दर भामरागड़ इलाके में 100 से ज्यादा जन संगठन कार्यकर्ताओ को गिरफ्तार किया. झूठी मुठभेड़ों में कई आम लोगों को गोली मार दी. इसके अलावा पुलिस बलों ने 'जन जागरण मेळावा' के नाम से पार्टी और क्रान्तिकारी आन्दोलन के खिलाफ एक जहरीला दुष्प्रचार मुहिम जारी रखी हुई है. संगठन में काम करने वालों को पैसे का लालच दिखाकर आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करना, आत्मसमर्पण करने वालों को सभाओं में लाकर पार्टी के खिलाफ बोलवाना, आदिवासियों के सामूहिक विवाह का ढोंग रचकर विवाहित जोड़ों को बड़े पैमाने पर पैसे देना आदि घिनौनी हरकतों का जिला एसपी शिरीष जैन स्वयं नेतृत्व कर रहा है. इन सबके खिलाफ विरोध दर्ज करते हुए जिले की जनता ने इस बन्द को सफल बनाया. पार्टी और पीएलजीए की इकाइयों ने पोस्टर व पर्चों के जरिए पूरे डिवीजन में प्रचार किया. ताड़िगामा-भामरागड़-लाहेरी रोड में यातायात पूरी तरह ठप्प हो गया.

15 अगस्त - काला दिवस

गड़चिरोली डिवीजन गट्टा इलाके के वीसामुंड़ी गांव में 15 अगस्त को जनता ने काला दिवस मनाया. इस मौके पर सभी लोगों ने झूठी आजादी के खिलाफ नारे लगाए और असली आजादी हासिल करने के लिए सामन्तवाद, दलाल पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने का संकल्प दोहराया. इस मौके पर आयोजित सभा को कॉमरेड सरदू ने सम्बोधित किया. उन्होंने अपने भाषण में उन महान बलिदानी वीरों को याद किया जिन्होंने देश की असली आजादी के लिए अपने प्राणों को मुस्कराते हुए न्यौछावर किया. भगतसिंह, राजगुरु, सुखदेव, गेंदसिह, बाबूराव सेड़िमेक तक कई क्रान्तिकारियों और लोक नायकों ने अंग्रेजों को देश से मार भगाने के उद्देश्य से संघर्ष किया था. लेकिन साम्राज्यवादियों से सांठगांठ करने वाले दलाल पूंजीपतियों और जमींदार वर्गों ने सत्ता को अपने हाथों में लेकर उसी को 'आजादी' बताना शुरू किया. उन्होंने बताया कि जब तक शोषण और उत्पीड़न का खात्मा नहीं होगा तब तक असली आजादी नहीं मिलेगी. इस मौके पर कॉमरेड भास्कर ने सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता जैसे महानगरों में बैठे बड़े पूंजीपति आजादी का जश्न मना रहे हैं. जबकि विदर्भ जैसे पिछड़े इलाकों में लोग दो जून की रोटी के लिए तरह रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि यह कैसी आजादी है, जिसमें एक तरफ भ्रष्ट नेता और अफसर करोड़ों रुपए की घपलेबाजी कर मालामाल बन रहे हैं तो दूसरी तरफ आदिवासी, दलित और अन्य शोषित लोग भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी आदि समस्याओं से दो-चार हैं. लूट और शोषण के खिलाफ संघर्ष करने वालों का दमन किया जा रहा है, उन पर हिंसा और अत्याचार किए जा रहे हैं. उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि असली आजादी लानी है तो देश के लुटेरे वर्गों का सफाया कर मजदूर-किसान एकता के आधार पर सभी मेहनतकश वर्गों की राजसत्ता को कायम करना ही एक मात्र रास्ता है. सभी जनता को भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व में जारी लोकयुद्ध में शामिल होना चाहिए.

26 जनवरी - काला दिवस

माड़ डिवीजन के कोहकामेट्टा इलाके के मुरनार गांव में 26 जनवरी 2006 को काला झण्डा फहराकर सभा की गई. इसमें स्कूली बच्चों समेत करीब 150 लोगों ने भाग लिया. कोहकामेट्टा गांव में आयोजित एक और विरोध सभा में 130 जनता ने भाग लिया. कुंदला, बासिंग, सोनपुर, कीहकाड़, झारावाही, कानागांव, इरकभट्टी आदि सभी जगहों पर झूठे गणतंत्र दिवस के विरोध में सभाएं आयोजित की गईं जिनमें कुल 1000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया.

जन दुश्मनों को सजाएं

उम्मानूर सरपंच का सफाया

गड़चिरोली डिवीजन के उम्मानूर गांव का सरपंच दीपक गावड़े पिछले कई सालों से मुखबिरी कर रहा था. पिछले 10 सालों से उसने सरपंच पद पर रहकर भ्रष्टाचार-घोटालों में खूब माल कमाया था. गांव में महिलाओं के साथ भी इसने कई बार दुरव्यवहार किया था. जुलाई 2004 में उसकी मुखबिरी से छापामार दस्ते पर पुलिस ने हमला किया था जिसमें कॉमरेड सुरेश घायल हुए थे. बाद में उन्हें गिरफ्तार करवाने में उसकी प्रत्यक्ष भूमिका रही. उम्मानूर गांव में पुलिस थाना खुलवाने के लिए इसीने पैरवी की थी. हाल ही में दीपक ने सरपंच पद से इस्तीफा देकर पुलिस में भर्ती होने का फैसला लिया था क्योंकि उसे लग रहा था कि जनता में उसके करतूतों का पर्दाफाश हो चुका है. जनता की सक्रिय मदद से 27 सितम्बर 2005 को छापामार दस्ते ने इसका सफाया कर दिया.

जनता का कट्टर दुश्मन रंजीत साहा का सफाया

बंगाली शरणार्थियों का गांव पीवी-81 का निवासी रंजीत साहा 2002 से जनता के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ था. यह गांव में कभी नहीं रहता था. हमेशा बान्दे कस्बे में पुलिस थाने के इर्द-गिर्द रहकर मुखबिरी करता था. पहले वह मुरगों का धंधा करता था. लेकिन जब उसे लगा कि पुलिस की दलाली करने से बैठे-बैठे ज्यादा पैसा मिलेगा, तो उसने इसी को धंधा बना लिया. आम लोगों को पकड़कर नक्सलवादियों के साथ उनके सम्बन्ध होने के झूठे आरोप मढ़ते हुए थाने में बताने की धमकियां देता था. लोगों से पैसा एंठ लेता था. यहां तक कि व्यापारियों को भी यह धमकियां देता था कि वे नक्सलवादियों को सामान पहुंचा रहे हैं. बान्दे में थाने के आसपास रंजीत खुद आने-जाने वाले लोगों को रोक-टोककर सामानों की तलाशी लेता था. एक बार इसकी सूचना पर 60-70 पुलिस वाले एक गुरिल्ला कैम्प पर हमला करते-करते रह गए. इस क्षेत्र में रंजीत का आतंक इतना बढ़ा था कि हर व्यक्ति पार्टी और पीएलजीए से अपील करता था कि रंजीत को टपका दिया जाए. आखिरकार पैसों के लालची होने की उसकी कमजोरी का ही फायदा उठाकर पीएलजीए दस्ते ने उसे जाल में फंसा दिया. और वहीं उसे मौत के घाट उतार दिया. इस घटना के बाद इस क्षेत्र की जनता ने खुशियां मनाईं. रंजीत के करतूतों से जनता कितनी परेशान थी, इसे समझने के लिए सिर्फ यह जानना काफी है कि इसकी मौत की खबर फैलते ही सैकड़ों घरों में नारियल फोड़े गए. ✶

कॉमरेड सुशील राय, नारायण सान्याल, पतितपावन एवं चंडी सरकार समेत तमाम राजनीतिक बन्दियों को बिना शर्त रिहा करो !

प्यारे देशवासियो,

आप सबों को ज्ञात होगा कि हमारी पार्टी के पोलित ब्युरो सदस्य कामरेड सुशील राय (अशोक, शोम, बरूण दा) एवं पश्चिम बंगाल राज्य कमिटी के सचिव व केन्द्रीय कमिटी सदस्य कामरेड पतितपावन (तापस), राज्य कमिटी सदस्य चंडी सरकार, किशोर, अरूप समेत लगभग 40 साथियों को (15 मई से 21 जून के भीतर) पश्चिम बंगाल की सामाजिक फासीवादी सी.पी.एम. की सरकार ने झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल की काली कोठरियों में कैद कर रखा है। 21 मई, 2005 को हुगली जिला के कोननगर रेलवे स्टेशन से कामरेड बरूण एवं तापस को गिरफ्तार किया गया तथा लगातार चार दिनों तक गुप्त रूप से रखकर उन्हें मानसिक उत्पीड़न एवं शारीरिक यातनाएँ दी गई और 24 मई को जन-दवाब के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उन लोगों को गिरफ्तार कोननगर (कोलकता उपनगर) से किया गया है, पर फासीवादी शासन की पुलिस मनगढ़ंत कहानी गढ़कर उन्हें पश्चिमी मिदनापुर जिला के बेलपहाड़ी से गिरफ्तार करने की बात कह रही है तथा वहाँ के कई झूठे मुकदमे लादकर पश्चिमी मिदनापुर जेल में बंद कर रखा है।

हमारी पार्टी की पोलित ब्यूरो के एक और सदस्य कॉमरेड नारायण सान्याल (विजय दा, प्रसाद) को छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में 28 दिसम्बर 2005 को आन्ध्र की कुख्यात खुफिया विभाग - एसआईबी ने गिरफ्तार किया है. उन्हें बुरी किस्म की यातनाएं देकर जन-दबाव के चलते आन्ध्र की एक अदालत में पेश कर वरंगल जेल में बन्द कर रखा है. पुलिस ने उन्हें आन्ध्रप्रदेश के भद्राचलम से गिरफ्तार करने की मनगढ़न्त कहानी गढ़ दी. उन पर सरकार ने 22 झूठे मामले दर्ज किए हैं.

हमारे पोलित ब्युरो, केन्द्रीय कमिटी एवं राज्य कमिटी के सदस्यों की क्यों हुई है गिरफ्तारी? बिल्कुल साफ है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के नेतृत्व में देश के कई भागों में सशस्त्र संग्राम चल रहा है। यह संग्राम शोषित-उत्पीड़ित जनता के मुक्ति के लिए चल रहा है। हमारी पार्टी के नेतृत्व में जनता के जनवादी राज का निर्माण झारखण्ड-आन्ध्र-बिहार-दण्डकारण्य में हो रहा है। जमीन और जनसत्ता का प्रश्न आज और तीव्रता के साथ शोषक-शासक वर्गों के सामने उठ खड़ा हुआ है। फिर साम्राज्यवादी पूँजी देश में धड़ल्ले से घुस रही है जिसके कारण लाखों-लाख कल-कारखाने बन्द हो गये हैं। फलस्वरूप बड़े पैमाने पर बेरोजगारी एवं गरीबी बढ़ी है। अत: बहुराष्ट्रीय कम्पनियों एवं साम्राज्यवादी लूट तथा सामंतवादी शोषण के खिलाफ हमारी पार्टी के नेतृत्व में क्रांतिकारी जनता सजग एवं संगठित हो सशस्त्र संग्राम में कूद पड़ी है। हमारी पी.एल.जी.ए. के छापामारों ने शोषक-शासक वर्ग एवं साम्राज्यवादी लूट तथा सामंती शोषण एवं दमन के खिलाफ कोरापुट, चंदौली, सारंडा, मधुबन, पदेड़ा, गिरिडीह, जहानाबाद जैसे ऐतिहासिक लड़ाइयों में विजय हासिल कर वर्ग दुश्मनों के कलेजा को दहला दिया है। देशी-विदेशी शोषक-शासक वर्ग इससे घबरा उठा है और घबरा उठा है 21 सितम्बर, 2004 की गठित भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) से।

केन्द्र की संयुक्त प्रगतिशिल गठबन्धन (संप्रग) की सरकार, जिसमें सी.पी.एम. भी हिस्सेदार है, आज 'आंतरिक सुरक्षा' के सवाल को प्रधानता से उठा रही है। दरअसल 'आंतरिक सुरक्षा' के नाम पर देश में चल रहे क्रांतिकारी संग्राम का दमन करना ही इनका मुख्य मकसद है। क्रांतिकारी जनता के दमन के लिए टाडा, पोटा, पोका, मकोका, एस्मा जैसे काले कानून लादे जा रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर अमेरिका ने हमारी पार्टी सी.पी.आई. (माओवादी) को प्रतिबन्धित घोषित किया है तथा हमें आतंकवादी संगठन की सूची में डाला है। आज देश के 13 राज्यों को लेकर एक संयुक्त ऑपरेशनल कमाण्ड (JOC) का गठन किया गया है। बिहार, आन्ध्र, झारखण्ड, दण्डकारण्य, उड़िसा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश के संघर्षशील इलाकों को अर्द्धसैनिक बलों एवं स्पेशल टास्क फोर्स से भरकर जनता पर भारी जुल्म-अत्याचार एवं दमन चलाया जा रहा है। फर्जी मुठभेड़ में पुलिस द्वारा प्रतिदिन दर्जनों क्रांतिकारियों को पूरे देश भर में हत्याएँ की जा रही हैं। पिछले एक साल में देश भर में हजारों माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी की एक कड़ी है- का. बरूण दा, विजय दा, तापस, चंडी सरकार, किशोर, अरूप, प्रसूण, शोमा एवं बुटाई की गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल में 2800 से भी ज्यादा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है जिसमें 1200 माओवादी हैं।

हमारे नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं छापामारों की फर्जी मुठभेड़ में हत्याएँ एवं गिरफ्तारियाँ हमारे संघर्ष को ध्वस्त करने के उद्देश्य से की जा रही हैं। पूरे देश में हमारे ऊपर आघोषित युद्ध चलाया जा रहा है। कई राज्यों ने हमारी पार्टी को प्रतिबन्धित किया है और अधिकांश राज्यों ने बिना प्रतिबन्ध घोषित किये ही प्रतिबन्धित संगठन की तरह व्यवहार कर रही है। किसी भी तरह के प्रतिवाद एवं प्रतिरोध पर रोक है। यहाँ तक की जनवादी संगठनों के कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है। क्रांतिकारी जनता को शांतिपूर्ण एवं खुली जनसभा, रैली, गोष्ठी, सम्मेलन आदि तक नहीं करने दी जा रही है।

29 वर्षों से पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा की सरकार है जिसका मुख्य नेता सी.पी.एम. है। उनके समाजवाद में आज भी लोग भूख से मर रहे हैं। अमलासोल एवं कांथी गांव में भूख से मरने

वाली जनता सी.पी.एम. के 'समाजवाद' का स्पष्ट उदाहरण है। समाजवादी फासीवादी बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है। भ्रष्टाचार और गुण्डागर्दी सी.पी.एम. का आदर्श है। जार्ज बुश की नीतियों को पालन करना तथा साम्राज्यवाद का जय-जयकार आज बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार की समाजवादी कार्यक्रम का अंग है। दमन और सुधार सामाजिक फासीवादी शासन का सूत्र है। सी.पी.एम. भूमण्डलीकरण, निजीकरण एवं उदारीकरण (LPG) का केन्द्र व दूसरे राज्यों में विरोध करती है पर, पश्चिम बंगाल में इसको लागू करने को बेताब है। साम्राज्यवादी नीति (LPG) के लागू करने के लिए तथा साम्राज्यवाद को आश्वस्त करने के लिए ही पश्चिम बंगाल में क्रांतिकारी जन संग्राम को कुचलने का बीड़ा उठा रखा है सी.पी.एम. ने।

पश्चिम बंगाल के गिरफ्तारी के ठीक पहले अप्रैल माह में 'आंतरिक सुरक्षा' के नाम पर आर्मी कमांडरों की बैठक हुई थी, जिसमें माओवादियों को दमन करने की योजना बनाई गयी थी। फिर 17 जून को नक्सलपंथियों के दमन हेतु केन्द्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। 13 राज्यों के ज्वाइंट ऑपरेशनल कमाण्ड की बैठक तो अब हरेक एक-दो माह के भीतर चल रही है, जिसमें दमन के नित्य नये-नये हथकण्डे अपनाये जा रहे हैं। उन हथकण्डों को लागू करने में पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार भी किसी दक्षिणपंथी पार्टी की सरकार से पीछे नहीं है। आज पश्चिम बंगाल माओवादियों के कैद का पिंजरा बना हुआ है कारण कि वाम मोर्चा सरकार जनता की रोजी-रोटी के सवाल को हल करने में विफल हो चुकी है। अत: राजनीतिक विरोध के चलते एवं जब पश्चिम बंगाल की जनता आज नये सिरे से पुन: माओवादियों के नेतृत्व में उठ खड़ी हो रही है तब वाम मोर्चा सरकार संघर्ष को दबाने के लिए दमन चला रही है। पर, दमन से दबाया नहीं जा सकता है क्रांतिकारी जनता के संग्राम को।

का. बरूण का राजनीतिक जीवन मजदूर आन्दोलन से शुरू हुआ। जय इन्जिनियरिंग वर्क्स (उषा कम्पनी) में 65-66 में जो हड़ताल हुई थी उसमें उनकी प्रमुख भूमिका थी। पश्चिम बंगाल के खाद्य आन्दोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। रूस-चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच चली *''महान बहस''* के दौरान से ही वे चीनी लाइन के समर्थक थे। शुरू से ही 'चिन्ता' एवं 'दक्षिण देश' ग्रुप के साथ जुड़े रहे तथा 20 अक्टूबर, 1969 में गठित माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र के साथ भी जुड़े रहे। शुरू से ही वे पश्चिम बंगाल राज्य कमिटी के सदस्य थे। कामरेड के.सी. के निधन के बाद वे एम.सी.सी. के महासचिव बने। 1989 में एम.सी.सी. के प्रथम सम्मेलन में भी वे महासचिव निर्वाचित हुए। अपनी खराब स्वास्थ्य के चलते इन्होंने 1996 में महासचिव पद ग्रहण करने से इन्कार कर दिया। एम.सी.सी.आई. और सी.पी.आई.(एम-एल)(पी.डब्लु.) के विलय एवं नई पार्टी के गठन में भी उन्होंने प्रमुख भूमिका निभायी। का. बरूण एम.सी.सी. के तमाम उतार-चढ़ाव के दौरान एक वरिष्ठ, प्रतिष्ठित एवं सम्मानित नेता रहे हैं। कामरेड सुशील राय (शोम) दक्षिण एशिया के क्रांतिकारी खेमों के बीच भी जाने-माने नेता रहे हैं।

कॉमरेड विजय दा भाकपा (माओवादी) के वरिष्ठ नेताओं में से एक रहे हैं. महान नक्सलबाड़ी सशस्त्र संघर्ष के दिनों में वे तत्कालीन भाकपा (मा-ले) से जुड़े थे. नक्सलबाड़ी संघर्ष के पीछे कदम के बाद मा-ले पार्टी में आए बिखराव के बावजूद भी उन्होने संघर्ष का परचम दृढ़तापूर्वक थामे रखा. भाकपा (मा-ले) पार्टी यूनिटी का गठन कर खासकर बिहार-झारखण्ड में एक शक्तिशाली किसान आन्दोलन को विकसित करने में उन्होने महत्वपूर्ण योगदान दिया. बाद में वे उस पार्टी के महासचिव चुने गए थे. देश में एक एकीकृत क्रान्तिकारी पार्टी की आवश्यकता पर हमेशा जोर देने वाले कॉमरेड विजय दा ने पहले पार्टी यूनिटी और पीपुल्सवार के बीच और बाद में एमसीसीआई और पीपुल्सवार के बीच एकता स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाई. 70 साल के कॉमरेड विजय दा अपने बुढ़ापे की परवाह न करते हुए क्रान्तिकारी कामकाज में संलग्न रहे हैं. पार्टी कतारों में वे एक लोकप्रिय एवं सम्माननीय नेता रहे हैं.

का. पतितपावन (तापस) बचपन से ही एम.सी.सी. के साथ जुड़े रहे हैं। ये मध्यम किसान परिवार के सदस्य रहे हैं। हुगली जिला में किसान आन्दोलन खड़ा करने में इनकी प्रमुख भूमिका रही है। इन्होंने दृढ़तापूर्वक पश्चिम बंगाल के पार्टी लाइन की रक्षा की है। कामरेड तापस ने नई पार्टी के गठन एवं पश्चिम बंगाल राज्य की कमिटियों के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

कामरेड चंडी सरकार रेलवे में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी थे, वहीं से वे मजूदर आंदोलन के साथ जुड़े। नक्सलबाड़ी के बाद नौकरी छोड़कर पेशेवर कार्यकर्ता बन सी.पी.आई.(एम-एल) में शामिल हुए। 70 के दशक में वे चार सालों तक जेल में रहे पर, अपने क्रांतिकारी उसूल पर अडिग रहे। जेल से छूटने के बाद पुन: क्रांतिकारी कामकाज में जुट गये। नदिया जिला में जननेता के रूप में पिछले तीस सालों से वे लोकप्रिय हैं।

अंत में हम मजदूर, किसान, छात्र-नौजवान, महिला, बुद्धिजीवी, कलाकार, जनपक्षीय एवं जनप्रेमी लोगों, लोकतांत्रिक संगठनों एवं व्यक्तियों से अपील करते हैं कि वे राजनीतिक कार्यकर्ताओं एवं क्रांतिकारी जनता समेत कामरेड बरूण, नारायण सान्याल, पतितपावन (तापस), चंडी सरकार, किशोर, अरूप एवं प्रसूण, शोमा, बुटाई के गिरफ्तारी का विरोध करें, उसकी निन्दा करें एवं भर्त्सना करें तथा इनके साथ-साथ तमाम राजनीतिक बंदियों के रिहाई के लिए एक देशव्यापी जन आन्दोलन को तेज करें।

क्रांतिकारीअभिनन्दनकेसाथ

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी

भाकपा (माओवादी)

7 जनवरी 2006

(..... अन्तिम पृष्ठ का शेष)

क्रान्ति के पथ पर आखिर तक चलते रहे. सरकारी दमन ने उन्हें और भी फौलाद बना दिया.

पंजाब में भाकपा (माले) के पतन के बाद वे 1974 में यूसीसीआरआइ (एम-एल) नामक पार्टी में शामिल हुए थे. 1974-82 के बीच उन्होंने उस पार्टी के क्षेत्रीय कमेटी सदस्य के रूप में काम किया था. पर यूसीसीआरआइ (एम-एल) की दक्षिणपंथी सुधारवादी लाइन उन्हें नहीं भाई थी. उस समय वह मजबूत पार्टी भी अपने पतन के दौर से गुजर रही थी. संशोधनवादी तीन दुनिया सिद्धांत को ऊपर उठाने की वजह से केन्द्रीय नेतृत्व का एक बड़ा हिस्सा संशोधनवादी लाइन की तरफ भटक गया था. हालांकि एक छोटे हिस्से ने इस संशोधनवादी सिद्धान्त को नकारा था. इस संशोधनवादी हमले का मुकाबला करने वालों में कॉमरेड शेरी एक प्रमुख नेता थे. इस मुद्दे पर और कई अन्य मुद्दों पर उन्होंने एक स्पष्ट रुख अपनाया था. 1982 में इस पार्टी में फूट पड़ी थी. तब कॉमरेड शेरी ने इस संगठन की दक्षिणपंथी सुधारवादी लाइन को नकार दिया और वे सीसी विरोधी नेतृत्वकारी ग्रुप के सदस्य बने थे. नवम्बर में इस ग्रुप का पहला अधिवेशन सम्पन्न हुआ था जिसमें उसका नाम आरसीसीआइ (एम-एल) रखा गया था. कॉमरेड शेरी इस ग्रुप के संस्थापक सचिव बने थे.

मई 1984 में रिवॅल्यूशनरी इंटरनेशनलिस्ट मूवमेन्ट (रिम) का गठन किया गया था जिसका कॉमरेड शेरी के नेतृत्व में इस ग्रुप ने समर्थन किया था. हरी क्रान्ति को साम्राज्यवादी नीति के हिस्से के तौर पर विकसित इलाके के आंकलन के मुद्दे पर पंजाब के साथ-साथ भारत के कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी आन्दोलन में दो संशोधनवादी लाइनें उभरकर सामने आई थीं. एक रुझान ने इस तरह के विकास की प्रक्रिया के आधार पर भारतीय समाज के लक्षण को बदलकर समाजवादी क्रान्ति और आम विद्रोह की लाइन अपनाने की जरूरत बताई. इस संशोधनवादी रुझान ने संसदीय संस्थाओं में भागीदारी का समर्थन किया. इस रुझान ने भारत को आर्थिक रूप से साम्राज्यवाद पर निर्भर तथा राजनीतिक रूप से उससे स्वाधीन या आंशिकतया स्वाधीन बताना शुरू किया. दूसरा रुझान राष्ट्रीय क्रान्तियों के कुल जमा की बातें करता था. कॉमरेड शेरी ने इन दोनों संशोधनवादी रुझानों के खिलाफ संघर्ष किया तथा नई जनवादी क्रान्ति और दीर्घकालीन लोकयुद्ध के सिद्धान्त का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया.

1992 में सम्पन्न आरसीसीआइ (एम-एल) के दूसरे अधिवेशन के बाद, 1995 में यह ग्रुप दो धड़ों में बंट गया था, आरसीसीआइ (माओवादी) और आरसीसीआइ (एमएलएम). 1996 और 2002 में सम्पन्न आरसीसीआइ (माओवादी) के अधिवेशनों में कॉमरेड शेरी सचिव बने रहे. उनके नेतृत्व में आरसीसीआइ (माओवादी) ने दक्षिण एशियाई माओवादी पार्टियों और संगठनों की समन्वय कमेटी (सीकम्पोसा) को संगठित करने में जबर्दस्त योगदान दिया. जनवरी 2003 में उनके नेतृत्व में आरसीसीआइ (माओवादी) और एमसीसी के बीच एकता सम्पन्न हुई. एकता के बाद एमसीसी का नाम एमसीसीआइ के रूप में बदला था. सीपीआइ (एम-एल) (पीपुल्सवार) के साथ विलय के पहले वे एमसीसीआइ के केन्द्रीय कमेटी सदस्य के रूप में चुने गए थे. सितम्बर 2003 में आरसीसीआइ (एमएलएम) और एमसीसीआइ के बीच एकता हासिल करने में कॉमरेड शेरी ने महत्वपूर्ण योगदान किया. एमसीसीआइ के केन्द्रीय कमेटी सदस्य के तौर पर एकता दस्तावेजों को तैयार करने में उन्होंने तत्परता के साथ भाग लिया जिन्हें कि विलय के बाद जारी किया गया. 21 सितम्बर 2004 को सम्पन्न दो केन्द्रीय कमेटियों की संयुक्त बैठक में उन्हें भाकपा (माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी के साथ-साथ पोलिट ब्यूरो का भी सदस्य चुन लिया गया. केन्द्रीय कमेटी और पोलिट ब्यूरो की बैठकों में भाकपा (माओवादी) के सामने आई समस्याओं को हल करने में कॉमरेड शेरी ने जबर्दस्त योगदान किया. क्रान्तिकारी आन्दोलन के पतन के दौर में कॉमरेड शेरी मजबूती से डटे रहे. उन्होंने वामपंथी और दक्षिणपंथी गलतियों से सीख लिया. एक निराशाजनक दौर में जबकि उनके कई साथी अपने-अपने घरों में लौट रहे थे, उन्होंने मार्क्सवादी साहित्य की ढेर सारी किताबें पढ़ लीं. इस दौर से गुजरते हुए वे एक परिपक्व सिद्धान्तकार के रूप में उभरे थे. उन्होंने कई दस्तावेजों और लेखों की रचना की, जोकि भारत के कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी आन्दोलन की अनमोल पूंजी हैं.

उनके विचारों व व्यवहार के चलते दक्षिणपंथी सुधारवादी आलोचकों ने उन्हें हमेशा वामपंथी दुस्साहसवादी कहा. जबकि इसके विपरीत, उनके लगातार परिपक्व बनते विचारों के चलते भारत और नेपाल के जंगलों व पहाड़ों में कॉमरेड शेरी का नाम गूंजता रहा. कॉमरेड शमशेर सिंह शेरी या कॉमरेड शेर सिंह शेरी की बजाए वे कॉमरेड केएस (करम सिंह) के नाम से लोकप्रिय हो गए. बिहार, झारखण्ड, आन्ध्र, पश्चिम बंगाल, दण्डकारण्य आदि माओवादी आन्दोलन के मजबूत गढ़ों के साथ-साथ पंजाब में उनकी मृत्यु की खबर से क्रान्तिकारी कतारों और मेहनतकश जनता को गहरा सदमा पहुंचा.

कॉमरेड शेरी ने खुद को इंकलाबी रास्ते में आखिर तक दृढ़ता के साथ बनाए रखा ही, साथ ही साथ, पंजाब में सैकड़ों नौजवानों को माओवादी आन्दोलन के साथ जोड़ा. उनके प्रयासों की बदौलत ही आज पंजाब में माओवादी आन्दोलन सरकार के सामने चुनौती खड़ी कर पा रहा है. ऐसे महत्वपूर्ण दौर में कॉमरेड शेरी की मृत्यु पंजाब के

महान क्रान्तिकारी नेता कॉमरेड करम सिंह की पूरे सम्मान के साथ अन्तिम विदाई

31 अक्टूबर 2005 को कॉमरेड शेरी के अन्तिम संस्कार उनके गांव खोखर खलान में किया गया. करीब 1500 लोगों ने शहीद नेता को अंतिम विदाई दी. जिस जगह पर उनका दाह संस्कार किया गया वहां एक स्मारक बनाने का संकल्प लिया गया. बाद में 13 नवम्बर 2005 को खोखर कलान में करीब 6 हजार किसानों, खेतिहर मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और अन्य लोगों ने उन्हें एक संजीदा समारोह में उन्हें श्रद्धांजली पेश की. वे पंजाब के अलावा देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए थे. इस मौके पर आयोजित स्मृति सभा को कई जनवादी व क्रान्तिकारी संगठनों के प्रमुखों ने सम्बोधित किया. 'कॉमरेड करम सिंह अमर रहें' का नारा चारों ओर गूंज उठा. कई संगठनों व पार्टियों की ओर से शोक संदेश पढ़े गए. भाकपा (माओवादी) की केन्द्रीय कमेटी (अस्थाई) का संदेश सभा में पढ़ा गया जिसमें कॉमरेड करम सिंह के महान आदर्शों को ऊंचा उठाए रखने का आहवान किया गया. इस सभा में उपस्थित लोगों ने फैसला लिया कि कॉमरेड शेरी (केएस) की अस्थियों को हुस्सेनिवाला के निकट सतलुज नदी में, जहां पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के स्मारक चिह्न मौजूद हैं, मिलाने का फैसला लिया. इस फैसले के मुताबिक 14 नवम्बर को 50 गाड़ियों का एक काफिला हुस्सेनिवाला की ओर निकल पड़ा. शहीद भगतसिंह, सुखदेव व राजगुरु के स्मारक चिह्नों के पास एक रैली निकाली गई. उसके बाद कॉमरेड शेरी की जीवन संगिनी हरबंस कौर और गांव की जनता ने कॉमरेड शेरी की अस्थियों को नदी में मिलाने की रस्म पूरी की.

माओवादी आन्दोलन के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है. पंजाब की माओवादी ताकतों को एक महान नेता की कमी काफी समय तक खलती रहेगी.

कॉमरेड शेरी ने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में भी माओवादियों की एकता पर अत्यधिक जोर दिया. उन्होंने माना कि विश्व सम्राज्यवाद हमारा साझा दुश्मन है. सर्वहारा वर्ग एक अन्तर्राष्ट्रीय वर्ग है. उसकी मुक्ति की शर्तें समान हैं. उसकी सम्पूर्ण मुक्ति का सवाल विश्व साम्राज्यवाद के उन्मूलन से जुड़ा हुआ है. इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर एकता के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय एकता भी अनिवार्य है. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एकताबद्ध कम्युनिस्ट आन्दोलन ही विश्व साम्राज्यवाद की नई चुनौतियों को कुशलतापूर्वक मात दे सकता है. साथ ही साथ, अखिल भारतीय स्तर पर एकताबद्ध माओवादी आन्दोलन ही माओवादी आन्दोलन के सामने मौजूद अन्दरूनी समस्याओं को कुशलतापूर्वक हल कर सकता है. कॉमरेड शेरी की मृत्यु पंजाब और भारत में माओवादी ताकतों के लिए एक बड़ा धक्का है.

संक्षेप में, नक्सलवादी आन्दोलन में कॉमरेड शेरी एक जाने-माने शख्स रहे, जिन्होंने मजदूर-किसानों की मुक्ति की खातिर अपना सारा जीवन न्यौछावर किया. 63 साल की उम्र में भी वे युवा दिली हुआ करते थे. क्रान्तिकारी आन्दोलन में उत्पन्न समस्याओं के आगे उन्होंने कभी अपना सिर नहीं झुकाया. सरकारी दमन के आगे भी उन्होंने कभी अपना सिर नहीं झुकाया. उन्होंने अपने निजी हितों को हमेशा साझे हितों के मातहत रखा. बिखरे हुए माओवादी आन्दोलन को एकताबद्ध करने के लिए उन्होंने अविश्रान्त प्रयास किए. पंजाब के माओवादियों को देश और दुनिया के माओवादियों से एकताबद्ध करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई. यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कॉमरेड शेरी एक जीता-जागता इतिहास थे. क्रान्तिकारी कतार और मेहनतकश जनता उन्हें हमेशा याद रखेंगे. उनके आदर्शों व मार्गदर्शन पर मजबूती से कदम बढ़ाएंगे तथा उनके सपनों को साकार बनाएंगे. ✶

प्रेस वक्तव्य

भाकपा (माओवादी) का वरिष्ठ नेता व पोलिटब्यूरो सदस्य कॉमरेड नारायणदास सान्याल उर्फ नवीन प्रसाद उर्फ विजय दा की गिरफ्तारी का विरोध करो ! क्रान्तिकारी आन्दोलन के खिलाफ जारी देशव्यापी हमले के तहत माओवादी क्रान्तिकारियों की हत्या, गिरफ्तारी व यातनाओं की निंदा करो !!

28 दिसम्बर 2005 को आन्ध्रप्रदेश के कुख्यात एसआईबी (विशेष खुफिया ब्यूरो) ने रायपुर के डंगनिया इलाके के एक मकान पर धावा बोलकर एक घिनौनी साजिश के तहत कॉमरेड नारायणदास सान्याल को गिरफ्तार किया. कॉमरेड नारायणदास हमारी पार्टी के पोलिटब्यूरो सदस्य और वरिष्ठ नेता हैं. वे पार्टी कतारों और उत्पीड़ित जन समुदायों में नवीन प्रसाद और विजय दा के नामों से लोकप्रिय हैं. वे करीब 70 साल के बुजुर्ग कॉमरेड हैं. किसी मुखबिर के जरिए सूचना पाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया और मानसिक तौर पर बुरी यातनाएं दी गईं. इस गिरफ्तारी के सम्बन्ध में पूछे जाने पर छत्तीसगढ़ के डीजीपी ओपी राठौर ने बेहद गैर-जिम्मेदारी के साथ जवाब दिया कि उन्होंने इस नाम के किसी शख्स को गिरफ्तार ही नहीं किया या उन्हें इसकी कोई खबर नहीं है. बाद में कॉमरेड नारायण सान्याल के भाई ने छग उच्च न्यायालय में बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की और आशंका जताई कि उनके भाई को पुलिस के हाथों मारे जाने का खतरा है. तब जाकर आन्ध्रप्रदेश पुलिस ने उन्हें आन्ध्रप्रदेश के भद्राचलम कस्बे में गिरफ्तार करने का झूठा दावा करते हुए कोत्तागूडेम अदालत में पेश किया. उन पर अलिपिरि में चन्द्रबाबूनाइडू पर किया गया हमला और जहानाबाद काण्ड समेत करीब 22 झूठे मामले लगाए.

21 सितम्बर 2004 को भाकपा (माओवादी) के गठन के बाद यूपीए सरकार और सभी राज्य सरकारों द्वारा छेड़े गए देशव्यापी हमले के तहत ही इस गिरफ्तारी को देखना चाहिए. सरकार ने यह गलतफहमी पाल रखी है कि माओवादी नेताओं की हत्या और गिरफ्तारी करके वह क्रान्तिकारी आन्दोलन को कुचल सकेगी. इसके लिए केन्द्र सरकार की अगुवाई में गठित जेओसी (संयुक्त आपरेशनल कमान) की देखरेख में विभिन्न राज्यों की खुफिया एजेन्सियां सांठगांठ के साथ नित नई साजिशें रच रही हैं. ऐसी ही साजिश के तहत आन्ध्र का खुफिया संगठन - एसआईबी ने छत्तीसगढ़ के पुलिस-प्रशासन के साथ सांठगांठ कर राजधानी रायपुर में कॉमरेड नारायणदास की गिरफ्तारी की. सम्भवतः एसआईबी ने झूठी मुठभेड़ की कहानी गढ़कर उनकी हत्या करने की साजिश रची होगी क्योंकि एसआईबी एक बदनाम संगठन है जिसने पूर्व में दर्जनों क्रान्तिकारी नेताओं की हत्या की थी. लेकिन जनवादी और मानवाधिकार संगठनों के द्वारा आवाज उठाए जाने तथा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाने के बाद उसने उन पर कई झूठे मामले दर्ज करके गिरफ्तारी की घोषणा की.

भाकपा (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी कॉमरेड नारायणदास सान्याल की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करती है और मांग करती है कि उन पर लगाए तमाम झूठे मामले वापस लिए जाएं और उन्हें तत्काल व बिना शर्त रिहा किया जाए. हम दण्डकारण्य और छत्तीसगढ़ समेत देश के सभी बुद्धिजीवियों, जनवादियों, लेखकों, पत्रकारों, मानवाधिकार संगठन कार्यकर्ताओं, छात्र-नौजवानों और मजदूर-किसान भाइयों और बहनों से अपील करते हैं कि कॉमरेड नारायण सान्याल की बिना शर्त रिहाई की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलन्द करें. 'सलवा जुडूम', 'सेन्दरा', 'जन जागरण अभियान' आदि नामों से क्रान्तिकारी आन्दोलन के खिलाफ देश के कई हिस्सों में सरकारों द्वारा जारी फासीवादी दमन व क्रान्तिकारी नेताओं की हत्या, गिरफ्तारी, यातनाओं के खिलाफ जन आन्दोलन छेड़ दें. कॉमरेड नारायणदास सान्याल की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए तथा उनकी बिना शर्त रिहाई की मांग करते हुए जगह-जगह पर जुलूस, सभा-सम्मेलनों और धरना-प्रदर्शनों का आयोजन करें.

दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

5 जनवरी 2006

कॉमरेड शमशेर सिंह शेरी (करम सिंह) जनता के दिलों में सदा अमर रहेंगे !

अपने प्यारे शहीद नेता के आदर्शों को ऊंचा उठाकर उनके नक्शेकदम पर आगे बढ़ो !!

भाकपा (माओवादी) के केन्द्रीय कमेटी एवं पोलिट ब्यूरो के सदस्य कॉमरेड शमशेर सिंह शेरी गंभीर अस्वस्थता के चलते 30 अक्टूबर 2005 को हमसे विदा हो गए. पार्टी कतारों व शोषित जनता के बीच वे 'शेर सिंह शेरी', 'करम सिंह', 'केएस' आदि नामों से काफी लोकप्रिय थे. एक गुरिल्ला जोन में वे मलेरिया बीमारी के शिकार हुए थे जहां जन डॉक्टरों ने उनका इलाज किया था. पर वह ठीक तरह से उससे उबरे नहीं थे और घातक सेरेब्रेल मलेरिया और पीलिया से पीड़ित हो गए. भूमिगत जीवन के कठोर हालात के चलते उनकी सेहत और ज्यादा बिगड़ गई. उन्हें बचाने की पार्टी की ओर से की गई तमाम कोशिशों के बावजूद उन्होंने 30 अक्टूबर को आंतिम सांस ली.

कॉमरेड शेरी का जन्म पंजाब के संगरूर जिला, सुनाम सब डिवीजन, लेहरा गंगा इलाका स्थित खोखर कलान गांव में हुआ था. आर्थिक तौर पर पिछड़ा इलाका माने जाने वाले इस इलाके की लम्बी क्रान्तिकारी परम्परा रही है. लाल पार्टी की अगुवाई में पेप्सू किसान आन्दोलन इसी इलाके में चला था जिसका नेतृत्व कॉमरेड तेजा सिंह स्वतंतर ने किया था. पंजाब के कम्युनिस्ट आन्दोलन के वरिष्ठ नेता कॉमरेड तेजा सिंह स्वतंतर लाल कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे. 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड के सूत्रधार, खूंखार अंग्रेजी अधिकारी जनरल डय्यर को 21 साल बाद लन्दन के कैक्सटन हाल में मौत के घाट उतारने वाले शहीद ऊधम सिंह इसी इलाके के थे. इस तरह अनेक लोक नायकों की जन्मस्थली है यह इलाका.

कॉमरेड शेरी का जन्म 1942 के आखिर में एक मध्यम किसान परिवार में हुआ था. अपनी शहादत के समय वे 63 साल के थे. वे छह भाई और तीन बहनें थे. कॉमरेड शेरी सबसे छोटे थे. उस समय की रूढ़िगत परम्पराओं के चलते 15 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह हरबंस कौर के साथ हुआ था. लेकिन उन दोनों का वास्तविक सह जीवन 1980 के आसपास शुरू हुआ था. उन दोनों के दो बेटे हैं. करीब 35 सालों से कॉमरेड शेरी के घर से बाहर रहने और इस दौरान उनके परिवार को अनगिनत मुश्किलों का सामना होने के बावजूद उनकी पत्नी हरबंस कौर आखिर तक दृढ़ता से खड़ी रहीं. तीखे दमन और सामाजिक दबाव से भी वे विचलित नहीं हुईं.

1963 में बीए पढ़ते समय कॉमरेड शेरी दर्शन बागी के सम्पर्क में आ गए थे जो पंजाब के जाने माने छात्र नेता व पंजाब स्टूडेन्ट्स यूनियन (पीएसयू) के पहले महा सचिव थे. बाद में कॉमरेड शेरी छात्र आन्दोलन में कूद पड़े. उस समय दुनिया भर में विश्व साम्राज्यवादी व्यवस्था के खिलाफ राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष चोट-दर-चोट करते आगे बढ़ रहे थे. चीनी क्रान्ति कॉमरेड माओ की अगुवाई में ऐतिहासिक महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति के जरिए प्रति क्रान्ति को पराजित कर रही थी. उन उथल-पुथल भरे सालों में कॉमरेड शेरी न सिर्फ क्रान्तिकारी आन्दोलन से जुड़ गए थे, बल्कि पंजाब छात्र आन्दोलन के अग्रणी नेताओं में एक बने थे. उस समय उन्होंने लुधियाना के सरकारी कॉलेज और अमृतसर के खालसा कॉलेज में दाखिला लिया था. अगस्त 1967 में पंजाब स्टूडेन्ट्स यूनियन की अमृतसर जिला कमेटी के वे सचिव चुने गए थे. अक्टूबर 1967 में उन्हें राज्य कमेटी के प्रचार सचिव चुन लिया गया था. दिसम्बर 1968 में पीएसयू के पहले महासचिव दर्शन बागी की गिरफ्तारी के बाद उन्हें उसी साल कार्यकारी महासचिव चुन लिया गया. जब वे महासचिव के रूप में काम कर रहे थे, तभी पीएसयू के पहले घोषणा-पत्र और संविधान तैयार कर पारित किए गए थे.

इस बीच, मई 1967 में कॉमरेड चारु मजुमदार की अगुवाई में महान नक्सलबाड़ी संघर्ष फूट पड़ा. उन्होंने भाकपा और माकपा की संशोधनवादी लाइन को नकारकर दीर्घकालीन लोकयुद्ध के रूप में एक ठोस वैकल्पिक लाइन पेश की. उस समय कॉमरेड शेरी ने भाकपा (माले) की स्थापना का स्वागत किया. 1969-70 में वे पार्टी के फैसले के मुताबिक भूमिगत हुए थे. उन्होंने हथियारबन्द संघर्ष की लाइन को न सिर्फ सैद्धान्तिक रूप से ऊंचा उठाया, बल्कि दीर्घकालीन लोकयुद्ध की लाइन को लागू करने में खुद को एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया. पुलिस की झूठी मुठभेड़ों में कुछ वरिष्ठ नेताओं की मौत होने के बाद उन्हें भाकपा (माले) में राज्य कमेटी सदस्य चुन लिया गया था. पाटियाला डीएसपी सिकंदर सिंह की सफाया कार्यवाही में कॉमरेड शेरी ने भी भाग लिया था. 1969-70 के दौरान पंजाब में नक्सलवादी आन्दोलन द्वारा की गई सर्वाधिक सफल कार्यवाही थी वह. उसके बाद पाटियाला और संगरूर जिलों में हुई तमाम फौजी कार्यवाहियों से कॉमरेड शेरी जुड़े हुए थे.

हालांकि छात्र जीवन के समय से ही पुलिस को उनकी तलाश थी, पर इन फौजी कार्यवाहियों के बाद वह कॉमरेड शेरी के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी. उनके गांव के लोगों, उनके दोस्तों, रिश्तेदारों, पत्नी, भाइयों और क्रान्तिकारी आन्दोलन में उनके तमाम परिचित व्यक्तियों पर भयानक सरकारी दमन बढ़ा. खोखर गांव का कोई भी व्यक्ति दिखता है तो पुलिस उसे यातनाएं देना अपना फर्ज समझती थी. उनकी पत्नी हरबंस कौर और भाभी हरबंस कौर को पुलिस ने तीन महीनों तक जेल में रखा था. उन्हें यातनाएं दी गई थीं. उनके करीब 80-90 नौजवान दोस्तों को तो पुलिस ने चुन-चुनकर पकड़ लिया और उन्हें बुरी यातनाएं दीं. पाटियाला में हुई कार्यवाहियों के अलावा, संगरूर जिले के दाधहूर गांव की पुलिस चौकी पर हुआ हमला, चंगालीवाला में जमींदार की हत्या और मोगा में सुविख्यात छात्र संघर्ष के दौरान सरकारी दमन बेहद ज्यादा बढ़ा था. उनकी पत्नी को अपनी जमीन पर खेती करने से रोका गया था. सरकार ने उनकी जमीन जब्त कर ली. लेकिन बदले हुए हालात में उनकी पत्नी ने हिम्मत के साथ अपनी जमीन पर खेती करना शुरू किया. सरकार को चुपचाप देखना पड़ा. आज भी सरकारी दस्तावेजों में वह जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहित है. उनका परिवार आज भी उस जमीन को बेच नहीं सकता. उन्हें कोई कर्ज नहीं मिल सकता. यहां तक कि बिजली का कनेक्शन भी नहीं मिल सकता. जब उन्हें बच्चे पैदा हुए थे तब पुलिस ने कॉमरेड शेरी की पत्नी को बेहद अपमानित किया था, यह पूछते हुए कि बच्चे पैदा कैसे हुए, कहां मिले थे, आदि. कॉमरेड शेरी और उनके पूरे परिवार ने तीखे सरकारी दमन को हिम्मत के साथ झेल लिया. कॉमरेड शेरी ने अपने जीवनकाल में किसी भी राजनीतिक या पुलिस अधिकारी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया. वे भूमिगत रहकर क्रान्ति के प्रति समर्पित रहे. घर-परिवार को छोड़ते समय या सरकारी दमन का सामना करते समय उन्होंने कभी कोई कमजोरी नहीं दिखाई. वे सिर उठाकर

(शेष पेज 26 में....)